



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2005-2006



भारतीय डाक विभाग
(संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
भारत

DEPARTMENT OF POSTS
(MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY)
INDIA

विषय सूची

भाग-1

वार्षिक रिपोर्ट

पृष्ठ संख्या

	विभाग की संकल्पना	1
अध्याय 1	पुनरीक्षा	2
अध्याय 2	संगठन	6
अध्याय 3	डाक प्रचालन	12
अध्याय 4	फिलैटली	20
अध्याय 5	व्यवसाय विकास कार्यकलाप	26
अध्याय 6	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	36
अध्याय 7	प्रौद्योगिकी	42
अध्याय 8	वित्तीय सेवाएं	46
अध्याय 9	वित्तीय प्रबंधन	54
अध्याय 10	मानव संसाधन विकास	62
अध्याय 11	सतर्कता कार्यकलाप	66
अध्याय 12	महिलाओं से संबंधित मुद्दे	68
अध्याय 13	अन्य कार्यकलाप	70
अध्याय 14	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलाप	78

भाग-II

कार्यकलाप

(अप्रैल-दिसम्बर, 2005)

86



CONTENTS

PART-I ANNUAL REPORT

		Page No.
	Vision of the Department	1
Chapter 1	Overview	3
Chapter 2	Organisation	7
Chapter 3	Postal Operations	13
Chapter 4	Philately	21
Chapter 5	Business Development Activities	27
Chapter 6	International Relations	37
Chapter 7	Technology	43
Chapter 8	Financial Services	47
Chapter 9	Financial Management	55
Chapter 10	Human Resource Development	63
Chapter 11	Vigilance Activities	67
Chapter 12	Gender Issues	69
Chapter 13	Other Activities	71
Chapter 14	Development Activities in North-Eastern Region	79

PART-II

Activities (April-December 2005)	87
--	----



डा. शकील अहमद, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा आईआईटीएफ-2005 के दौरान भारतीय डाक पवेलियन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 2005 को बाल दिवस पर डाक-टिकट जारी करते हुए।

Release of Children Day Stamp by Dr. Shakeel Ahmad, Hon'ble Minister of State for Communications and IT on 14 November, 2005 at IITF - 2005, at India Post Pavilion, Pragati Maidan, New Delhi.



13 अक्टूबर, 2005 को आयोजित प्रसिद्ध मैसूर दशहरा जुलूस में 'समय के साथ डाक प्रणाली का विकास' पर झांकी।

A Tableau depicting 'Evolution of Postal System through Ages' in the famous Mysore Dussehra Procession, held on 13 October, 2005.



विभाग की संकल्पना

“भारतीय डाक-सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध,
प्रौद्योगिकी परिचालित,
व्यावसायिक दृष्टि से संचालित तथा
प्रगतिशील संगठन”

VISION OF THE DEPARTMENT

*“India Post a socially
committed, technology driven,
professionally managed &
forward looking Organisation”*

अध्याय 1

पुनरीक्षा

प्रस्तावना

1.1 भारतीय डाक व्यवस्था वर्तमान में कई सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संचार सेवाएं (पत्र, पोस्टकार्ड आदि), दुलाई सेवाएं (पार्सल, लाजिस्टिक पोस्ट), वित्तीय सेवाएं (बचत बैंक, मनीआर्डर, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा, डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी, डाक जीवन बीमा) और प्रीमियम मूल्यवर्धित सेवाएं (जैसे स्पीड पोस्ट, व्यवसाय डाक, रिटेल पोस्ट)। डाकघर बचत बैंक अपने नेटवर्क, खातों और वार्षिक जमा के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा बैंक है।

विभाग के उद्देश्य

1.2 डाक विभाग सभी लोगों को सस्ती कीमतों पर देश में बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- जनजातीय, पहाड़ी तथा दूर-दराज के इलाकों सहित देश के सभी भागों में बुनियादी डाक सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना।
- कार्य-कुशल, विश्वसनीय और किफायती सेवा प्रदान करना।
- बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना।
- बढ़ते कार्य की मात्रा को कुशलता से निपटाने के लिए सेवाओं का आधुनिकीकरण और इस प्रकार ग्राहक एवं कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि करना।
- एक प्रगतिशील संगठन बनना; और
- अधिक संसाधन जुटाना तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाना।

दायित्व, चुनौतियां और कार्य-नीतियां

1.3 विश्वभर में डाकघर की भूमिका में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल और नई प्रौद्योगिकियां पारंपरिक डाक कार्यकलापों की पूरक बन रही हैं। हर कहीं, डाकघर प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक जरूरतों के अनुरूप अनेक जनोपयोगी एवं नई वित्तीय सेवाएं प्रदान करके निरंतर नए व्यवसाय अपना रहा है जिससे उसकी विक्रय क्षमता बढ़ने में मदद मिली है। साथ-ही-साथ डाकघर प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके पारंपरिक सेवाओं को उन्नत बना रहा है तथा प्राइवेट कुरियर उद्योग से बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं संचार प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को त्वरित, अधिक विश्वसनीय और अधिक उत्तरदायी सेवा प्रदान करने की चुनौती का सामना करने के लिए नए उत्पाद और सेवाएं शुरू कर रहा है।

1.4 जहां तक समूचे देश में, भू-भाग को ध्यान में रखे बिना, सस्ती कीमतों पर बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने का संबंध है, भारतीय डाक सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए इसने 31-3-2005 तक 1,55,516 डाकघरों का नेटवर्क स्थापित किया है जिनमें से 1,25,148 शाखा डाकघर हैं जो पूरी तरह ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन डाकघरों के जरिए यह देश में कहीं भी प्रत्येक ग्राहक के घर पर डाक का दैनिक वितरण, लैटर बॉक्सों के जरिए पत्रों का संग्रहण तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पोस्टमैन के माध्यम से ग्राहकों के घर पर ही डाक-टिकटों और डाक-स्टेशनरी की बिक्री सुनिश्चित करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर ग्राहकों को अनेक बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के सभी डाकघरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए डाकघरों के माध्यम से बिल संग्रहण सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि शहरी क्षेत्रों में चुने हुए डाकघरों में कतिपय मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

1.5 देश में कहीं भी संचार के सस्ते साधन प्रदान करने के अलावा भारतीय डाक वाणिज्य, उद्योग, सरकार तथा सांस्थानिक



Chapter 1

OVERVIEW

Introduction

1.1 The Indian Postal System currently provides a number of services which can be broadly classified into four categories : Communication services (Letters, Post Cards, etc.), Transportation services (Parcel, Logistics Post), Financial services (Savings Bank, Money Order, International Money Transfer Service, Public-Private Partnerships for extending financial service outreach through the post office network, Postal Life Insurance) and Premium Value Added Services (Like Speed Post, Business Post, Retail Post). The Post Office Saving Bank is the largest Bank in India in terms of network, accounts and annual deposits.

Objectives of the Department

1.2 The Department of Posts is committed to provide universal access to basic postal services in the country at affordable prices.

The objectives of the Department are to:-

- ensure availability of basic postal services in all parts of the country, including tribal, hilly and remote areas.
- provide efficient, reliable and economic service.
- provide value-added services according to market requirements.
- modernize the services to handle the growing volume of work with efficiency and thereby enhance customer and employee satisfaction.
- be a forward-looking organization, and
- generate more resources and improve financial performance.

Responsibilities, Challenges and Strategies

1.3 The role of the Post Office is undergoing transformation the world over, as electronic mail and new technologies supplement traditional postal activities. Everywhere, the Post Office is increasingly adopting new businesses that help to optimise its retailing strength, by providing a range of public utilities and new financial services that are relevant to the socio-economic needs of each country. It is also simultaneously upgrading traditional services through induction of technology, and introducing new products and services in order to meet the challenges of providing faster, more reliable, and more responsive service to the customer in the face of increasing competition from the private courier industry and continuing advances in communication technology.

1.4 India Post is committed to fulfill the Universal Service Obligation in terms of providing basic postal services throughout the country, irrespective of terrain, at an affordable price. For meeting this requirement it has set up a network of 1,55,516 Post Offices as on 31.3.2005, out of which 1,25,148 are Branch Post Offices catering exclusively to the rural areas. Through these offices it ensures daily delivery of Dak at the doorstep of every customer any where in the country, collection of letters through Letter Boxes, and also sale of Stamps and stationery through village postmen at the doorstep of customers in rural areas. Post Offices in urban and rural areas provide a range of basic postal services to the customers, including banking and insurance services. Bill collection facilities are being extended through all Post Offices in urban areas, and identified Post Offices in rural areas, while certain value added services are being provided in selected offices in urban areas.

1.5 Besides providing access to affordable means of communication anywhere in the country, India Post

निकायों जैसे समाज के विशिष्ट खण्डों की उभरती जरूरतों को भी पूरा करती है जो त्वरित और मूल्यवर्धित सेवाओं की मांग करते हैं। इसके फलस्वरूप, इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राहकों के अनुकूल अनेक उत्पादों और सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके डाक प्रचालन कार्यों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत हुई। ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय की दृष्टि से संवेदनशील डाक की विभिन्न श्रेणियों की प्रोसेसिंग को प्राथमिकता देना भी आवश्यक हो गया। हाल के वर्षों में भारतीय डाक द्वारा प्रदान की गई मूल्यवर्धित सेवाओं में स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बधाई डाक, डाटा पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, बिल मेल पोस्ट, ई-पोस्ट और ई-बिल पोस्ट सेवाएं शामिल हैं। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, जो नई सेवाएं शुरू की गई हैं, उनमें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, वारंट पेमेंट, म्यूचुअल फण्डों और बॉण्ड्स आदि की बिक्री की सुविधाएं शामिल हैं।

1.6 डाक नेटवर्क की पहुंच, एक सुस्थापित लेखांकन प्रणाली और देश के दूर-दराज के इलाकों में भी स्थानीय परिस्थितियों की अंतरंग जानकारी हमारे डाक नेटवर्क की क्षमता है जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्राहकों को और अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी की शुरुआत ने फिजिकल नेटवर्क की क्षमता को उन्नत बनाकर इसे सुविधाजनक बनाया है। प्रशिक्षण, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में अग्रणी सेवा प्रदाताओं के साथ नीतिपरक सहयोग से कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं, तथा एजेंसी आधार पर अधिक से अधिक समनुरूप उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना इस समय भारतीय डाक की उस पहल में शामिल हैं जिस पर वह अपने सामने उभरती हुई चुनौतियों को पूरा करने तथा उभरते हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में संचार एवं विकास की सुविधा प्रदान करने की अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

1.7 ग्राहक को किफायती और व्यवहार्य सेवाएं प्रदान करने की चुनौती भी एक निरंतर चिंता का विषय है। वर्ष 2004-05 के दौरान 58,136.92 मिलियन रु. के कुल कार्यकारी-व्यय की तुलना में कुल राजस्व 44,318.47 मिलियन रु. था। इस प्रकार 13,818.45 मिलियन रुपये का अंतर रहा। डाक राजस्व में वृद्धि 4.11 प्रतिशत थी। जबकि, पिछले वर्ष के बजट घाटे की तुलना में 0.48 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

1.8 पिछले दशक में वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण के परिणामस्वरूप ग्राहकों की उभरती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डाक विभाग का पूर्णतया समर्पित डाकघरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जो लघु बचत सहित कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। डाकघरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप "बन-स्टॉप-पोस्ट फाइनेन्स-शॉप" (जिसे डाक वित्त मार्ट कहा जाता है) के रूप में पूर्णतया रिटेलिंग आउटलेट प्रदान किए जाएंगे। डाक वित्त मार्ट का संचालन कुशल स्टाफ द्वारा किया जाएगा जो जमाकर्ताओं को मूल्यवर्धन परामर्श प्रदान करेगा। कुछ डाकघरों को डाक वित्त मार्ट के रूप में रीमॉडल करने का प्रस्ताव है ताकि मौजूदा डाक नेटवर्क को वित्तीय सेवाओं के लिए मूल्यवर्धन ब्रांड छवि के आउटलेट प्रदान किए जा सकें।

1.9 चालू दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में जनवरी 2004 में, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने डाकघरों, प्रशासनिक एवं लेखा कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना का अनुमोदन किया। यह एक बृहत् योजना स्कीम है जिसका परियव्यय 8362.70 मिलियन है। इसका उद्देश्य दक्षतापूर्वक और वास्तविक समय आधार पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। विभाग का लक्ष्य सभी 839 प्रधान डाकघरों, 6861 बड़े उप डाकघरों, 22 डाक लेखा कार्यालयों और 264 प्रशासनिक कार्यालयों को दसवीं योजना के दौरान कम्प्यूटरीकृत करना है। विभाग 2004-05 के दौरान 839 प्रधान डाकघरों और 1533 उप डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने में सफल रहा। विभाग दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान बाकी के उप डाकघरों का भी कम्प्यूटरीकरण करेगा जिनके कम्प्यूटरीकरण के लिए दसवीं योजना में लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभाग इस योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) में राष्ट्रीय डाटा केन्द्र की स्थापना द्वारा डाकघरों की नेटवर्किंग के लिए भी कार्य कर रहा है।

1.10 डाकघरों के आधुनिकीकरण की योजना स्कीम के अंतर्गत भारतीय डाक ने कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहकों को बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए डाकघरों के प्रचालनात्मक तंत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने की योजना तैयार की। दसवीं योजनावधि के दौरान 1500 डाकघरों के लिए "कार्य-वातावरण में सुधार" तथा 1600 डाकघरों को "नए यांत्रिकी उपकरणों की आपूर्ति" का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2004-05 तक योजना कार्यक्रम - "कार्य वातावरण में सुधार" के अंतर्गत 342 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया और 858 डाकघरों को नए "यांत्रिकी उपकरणों" की आपूर्ति की गई।

also meets the emerging needs of specific segments of society like commerce, industry, Government and institutional bodies, who demand quicker, value added services. This has resulted in the need to customise a number of products and services to meet these requirements and modernise postal operations through induction of technology. It has also become necessary to prioritise the processing of different categories of mail according to time sensitivity to meet customer expectations. The value added postal services offered by India Post in recent years include Speed Post, Business Post, Express Parcel Post, Greetings Post, Data Post, Speed Post, Passport Service, Bill Mail Post, e-Post and e-Bill Post. In the area of financial services, new services introduced include facilities for International Money Transfer, Electronic Fund Transfer, Electronic Clearance Services, Warrant Payment, Sale of Mutual Funds and Bonds etc.

1.6 The outreach of the network, a well established accounting system and intimate knowledge of local conditions even in the remotest corners of the country are the strength of the postal network, which are being further tapped to provide more and more services to customers, depending on local needs. Induction of technology is facilitating this objective by upgrading the capacity of the physical network. Efforts to improve the skills and capabilities of employees through training, strategic collaborations with leading service providers in banking and insurance sectors, and provision of more and more products and services on agency basis are among the initiatives that India Post is currently focusing on to meet the emerging challenges before it and to fulfill its role as a facilitator of communication and development in the emerging socio-economic environment.

1.7 The challenge of providing cost effective and viable services to the customer is also a matter of constant concern. The total revenue during 2004-05 was Rs. 44,318.47 Million against the net working expenses of Rs. 58,136.92 Million, leaving a gap of Rs.13,818.45 Million. The increase in postal revenue was to the extent of 4.11% whereas there was a slight increase in the budgetary deficit of 0.48% over the previous year.

1.8 With liberalization of the financial sector in the

last decade, the Post Office proposes to meet the rising expectations of its customers by providing dedicated offices rendering a basket of financial services including small savings in line with the International trend of the post office providing exclusive retailing outlets as a One-Stop – Post Finance-Shop (called Postal Finance Marts). The Postal Finance Mart will be manned by qualified staff who will provide value addition of advice to depositors. Some post offices are proposed to be re-modeled into Postal Finance Marts, so that the value addition of a brand image outlet for financial services can be provided to the existing postal network.

1.9 In the current Tenth Five Year Plan (2002-07), in January, 2004, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved an ambitious project for computerization and networking of Post Offices, Administrative and Account Offices. This is a major plan scheme and has an outlay of Rs. 8362.70 Million. The objective is to improve quality of services in an efficient and real time basis. The Department has the target to computerize all 839 Head Post Offices, 6861 large Sub-Post Offices, 22 Postal Accounts Offices and 264 Administrative Offices during the Tenth Plan. The Department has been able to computerize 839 Head Post Offices and 1,533 Sub-Post Offices during 2004-05. The Department will computerize the remaining Sub-Post Offices as targeted in the Tenth Plan during the remaining period of Tenth Plan. The Department is also working towards networking of Post Offices by setting up a National Data Centre in National Informatics Centre (NIC) during this Plan period.

1.10 Under the Plan Scheme of Modernisation of Post Offices, India Post planned to make a qualitative change in the operative systems of the Post Offices, to improve the functional efficiency and to provide a better environment for the customer. A target was laid down for “Improving Ergonomics” for 1,500 Post Offices and for “Supply of new Mechanical Equipments” to 1,600 Post Offices during the Tenth Plan period. Till 2004-05, under the Plan activity – “Improving Ergonomics”, 342 Post Offices have been modernized and further 858 Post Offices have been supplied with new “Mechanical Equipments”.

अध्याय 2

संगठन

2.1 डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है। यह विभाग श्री दयानिधि मारन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अधीन काम कर रहा है। डॉ. शकील अहमद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। श्री उ. श्रीनिवासराघवन, सचिव, डाक विभाग के साथ-साथ महानिदेशक, भारतीय डाक और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड हैं।

मुख्यालय में योजना एवं नीति संबंधी कार्य

2.2 डाक सेवा बोर्ड इस विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसमें अध्यक्ष और तीन सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के पास प्रचालन एवं विपणन, विकास तथा कार्मिक के प्रकार्यात्मक विभाग हैं। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार इस बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। सचिव, डाक सेवा बोर्ड द्वारा बोर्ड को सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय में उप महानिदेशक, निदेशक तथा सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक सहयोग देते हैं।

संगठनात्मक परिवर्तन

2.3 प्रौद्योगिकी की शुरुआत के कारण सामने आई चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में हाल में डाक विभाग के संगठनात्मक स्वरूप का पुनर्गठन किया जा रहा है। कार्यात्मक पुनर्गठन इस प्रकार किया गया है ताकि उच्च प्रबंधन की समन्वय एवं मॉनीटरिंग की भूमिका को यथोचित महत्व देते हुए परिवर्तन की संक्रमणकालीन कठिनाइयों से निपटा जा सके। प्रबंधन की सहायता के लिए परम्परागत पिरामिडीय प्रणाली को डैस्क प्रणाली में बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों की शुरुआत एक उत्तरदायी, संवेदनशील एवं कार्यकुशल प्रबंधन स्थापित करने के लिए जरूरी सक्रियता के साथ इस प्रणाली को उत्प्रेरक बनाने के लिए की गई है।

डाक सर्किल

2.4 डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 22 डाक सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्किल राज्य का को-टर्मिनस

होता है। लेकिन गुजरात सर्किल जिसमें दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, केरल सर्किल जिसमें लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र; महाराष्ट्र सर्किल जिसमें गोवा; पूर्वोत्तर सर्किल जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा, पंजाब सर्किल जिसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, तमिलनाडु सर्किल जिसमें पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल सर्किल जिसमें सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं, इसके अपवाद हैं। प्रत्येक सर्किल प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/ मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है। प्रत्येक सर्किल को परिक्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें फील्ड यूनिटें होती हैं, जिन्हें डिवीजन (डाक/रेल डाक सेवा डिवीजन) कहा जाता है। प्रत्येक परिक्षेत्र पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है जो उस क्षेत्र का डाक प्रबंधक होता है। सर्किलों और परिक्षेत्रों में कार्यसंचालन में सहयोग देने के लिए स्टैम्प डिपो, डाक भंडार डिपो तथा मेल मोटर सेवा आदि जैसी अन्य संभार यूनिटें भी होती हैं।

सेना डाक सेवा

2.5 इन 22 सर्किलों के अलावा, सशस्त्र सेनाओं की संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बेस सर्किल भी है। बेस सर्किल अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा के अधीन है। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के लिए भी 75 प्रतिशत कार्मिक डाक विभाग से लिए जाते हैं और शेष कार्मिक सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं।

प्रचालन यूनिट

2.6 देश भर में डाकघरों को मुख्य, उप तथा शाखा डाकघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण डाक सेवा डाकघर, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उप डाकघर विभागीय डाकघर हैं जो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में हैं। प्रधान डाकघरों को उनके कार्यभार तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुसार पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया है, इनमें से सबसे बड़े डाकघर मुंबई और कोलकाता के जनरल पोस्ट आफिस (जी.पी.ओ.) हैं और उनके बाद अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ स्थित जी.पी.ओ. आदि आते हैं।



Chapter 2

ORGANISATION

2.1 The Department of Posts under the Ministry of Communications and Information Technology has Shri Dayanidhi Maran as Minister-in-charge with Dr. Shakeel Ahmad as Minister of State. Dr. U. Srinivasa Raghavan is Secretary, Department of Posts, Director General, Department of Posts and Chairman, Postal Services Board.

Planning and Policy Functioning at Headquarters

2.2 The Postal Services Board is the apex management body of the Department, comprising the Chairman and three Members. The three members of the Board hold functional portfolios of Operations & Marketing, Development and Personnel. The Joint Secretary and Financial Adviser to the Department is a permanent invitee to the Board. The Board is assisted by the Secretary, Postal Services Board, Deputy Directors General, Directors and Assistant Directors General of the Department provide necessary support to the Board at the Headquarters.

Organisational changes

2.3 The organisational set up of the Department has been undergoing restructuring in recent times as a response to the challenges faced due to induction of technology. The functional restructuring is designed to tackle the transitional problems of change giving due importance to the coordinating and monitoring role of the higher management. Steps have been taken to substitute the traditional pyramidal system with a desk system to support the management. These reforms were introduced to infuse the system with dynamism needed to create a responsive, sensitive & efficient management.

Postal Circles

2.4 For providing postal services, the whole country has been divided into 22 Postal Circles. Each circle is co-terminus with a State except Gujarat Circle which

includes Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli; Kerala Circle includes the Union Territory of Lakshadweep; Maharashtra Circle includes Goa; North Eastern Circle consists of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura; Punjab Circle includes the Union Territory of Chandigarh; Tamil Nadu Circle includes Pondicherry; West Bengal Circle includes Sikkim and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands. A Principal Chief Postmaster General/Chief Postmaster General heads each Circle. Each circle is divided into Regions comprising groups of field units, called Divisions (Postal/RMS Divisions). Each Region is headed by a Postmaster General who is the Postal Manager of the area. In the Circles and Regions there are other functional supporting logistical units like Stamp Depots, Store Depots and Mail Motor Service.

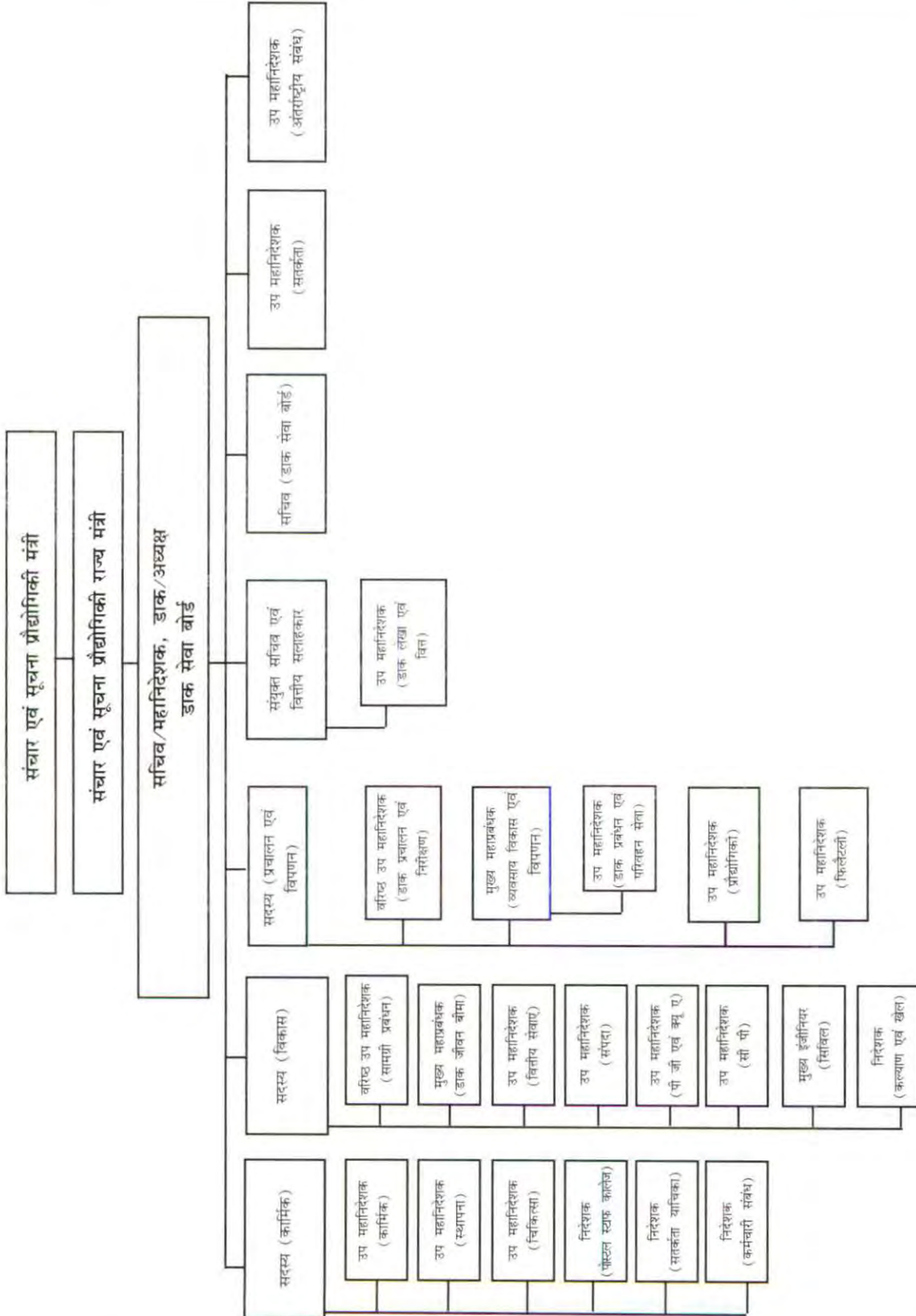
Army Postal Services

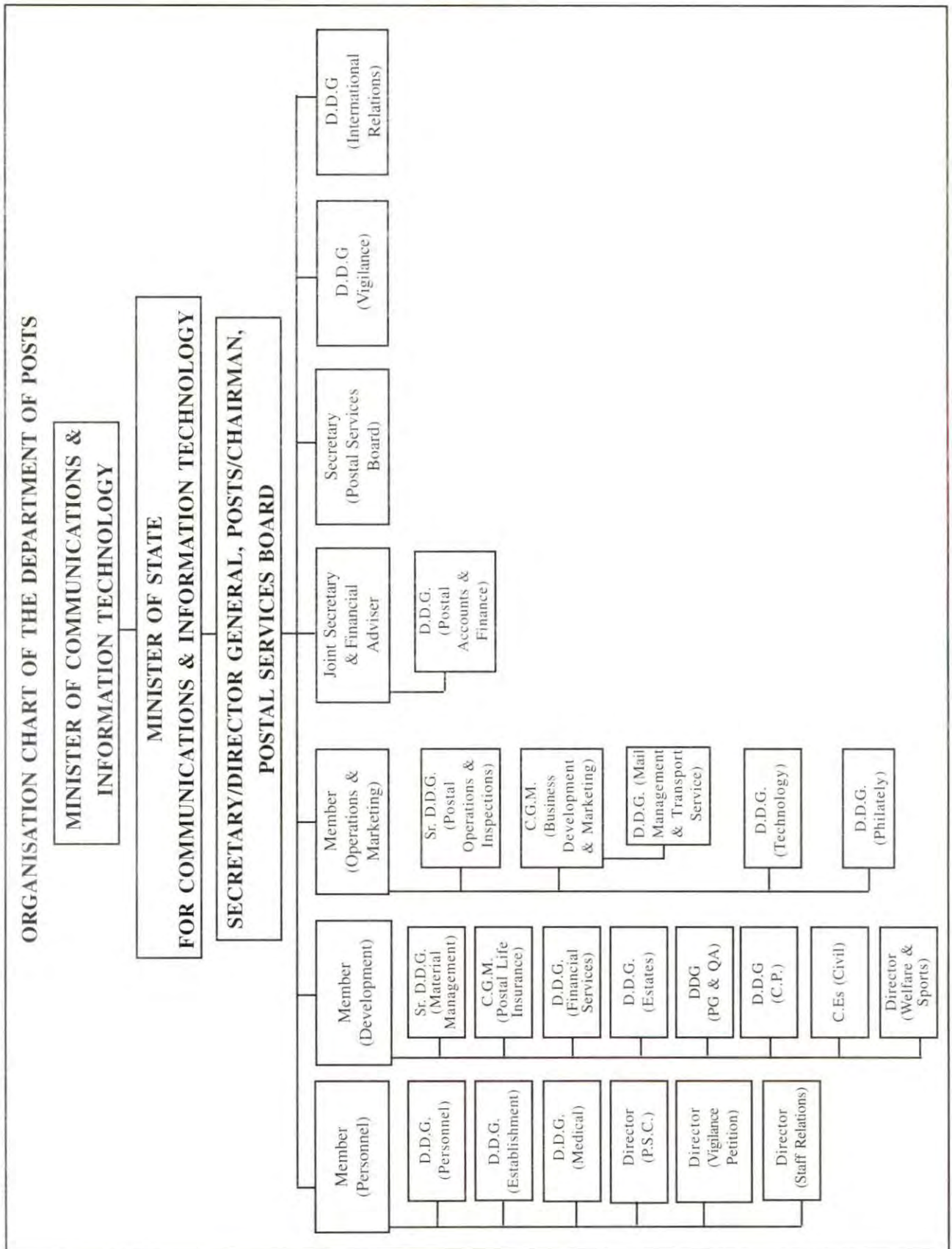
2.5 Over and above these 22 Circles, the communication needs of the armed forces are catered to by the Base Circle. The Base Circle is headed by the Additional Director General, Army Postal Service. The officer cadre of Army Postal Services is drawn on deputation from the Indian Postal Service. 75 per cent of the other ranks of the Army Postal Service are drawn from the Department of Posts and the remaining personnel are recruited by the Army.

Operational Units

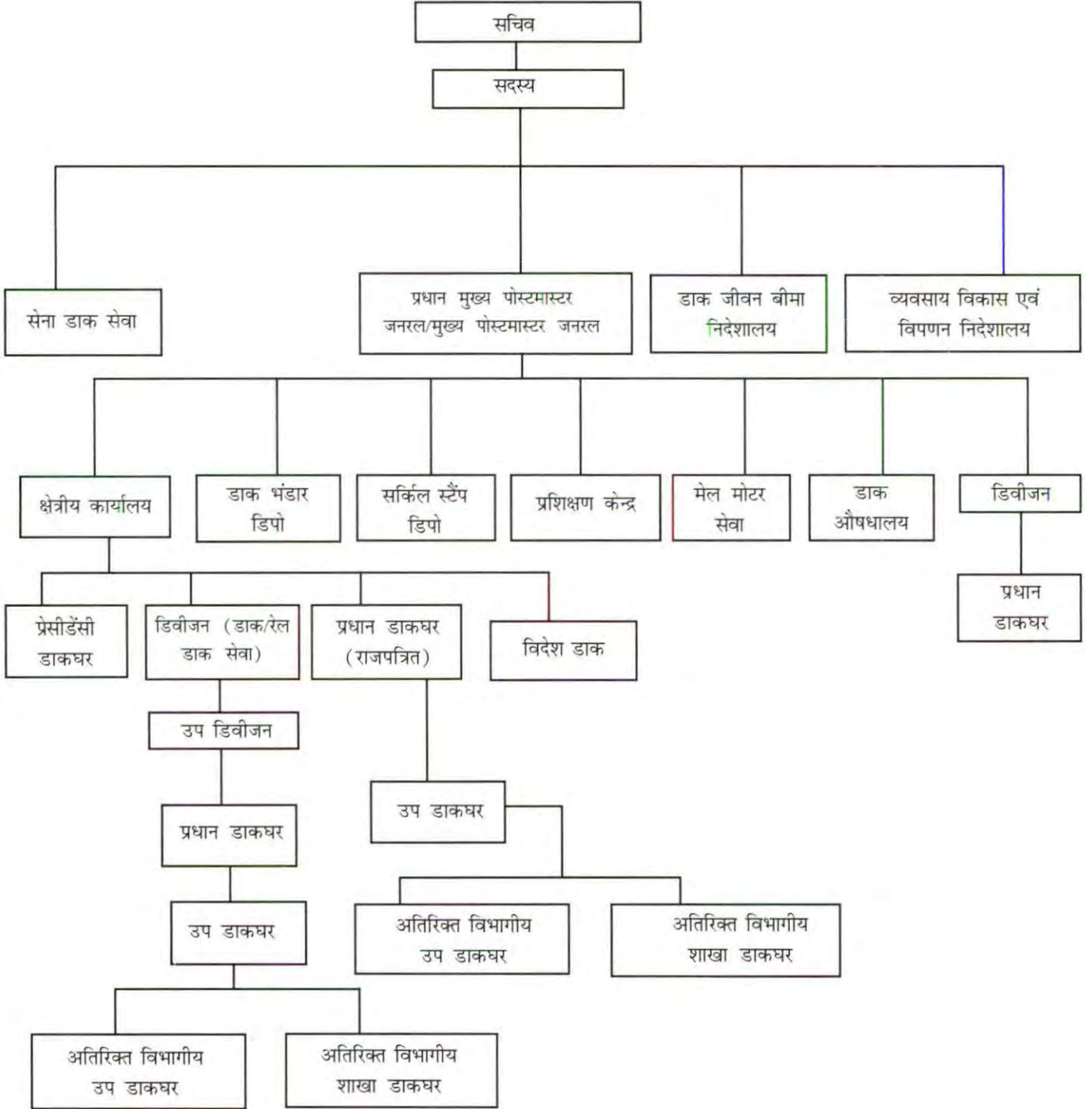
2.6 Post Offices in the country are categorized as Head, Sub and Branch Post Office. Gramin Dak Sewa Post Offices are located in rural areas. The Sub Post Offices are departmental offices located in both rural and urban areas. Head Post Offices are graded into five categories according to their workload and staff strength, the largest being the General Post Offices (GPOs) at Mumbai and Kolkata, followed by GPOs at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Kanpur, Lucknow and so on.

डाक विभाग का संगठनात्मक चार्ट



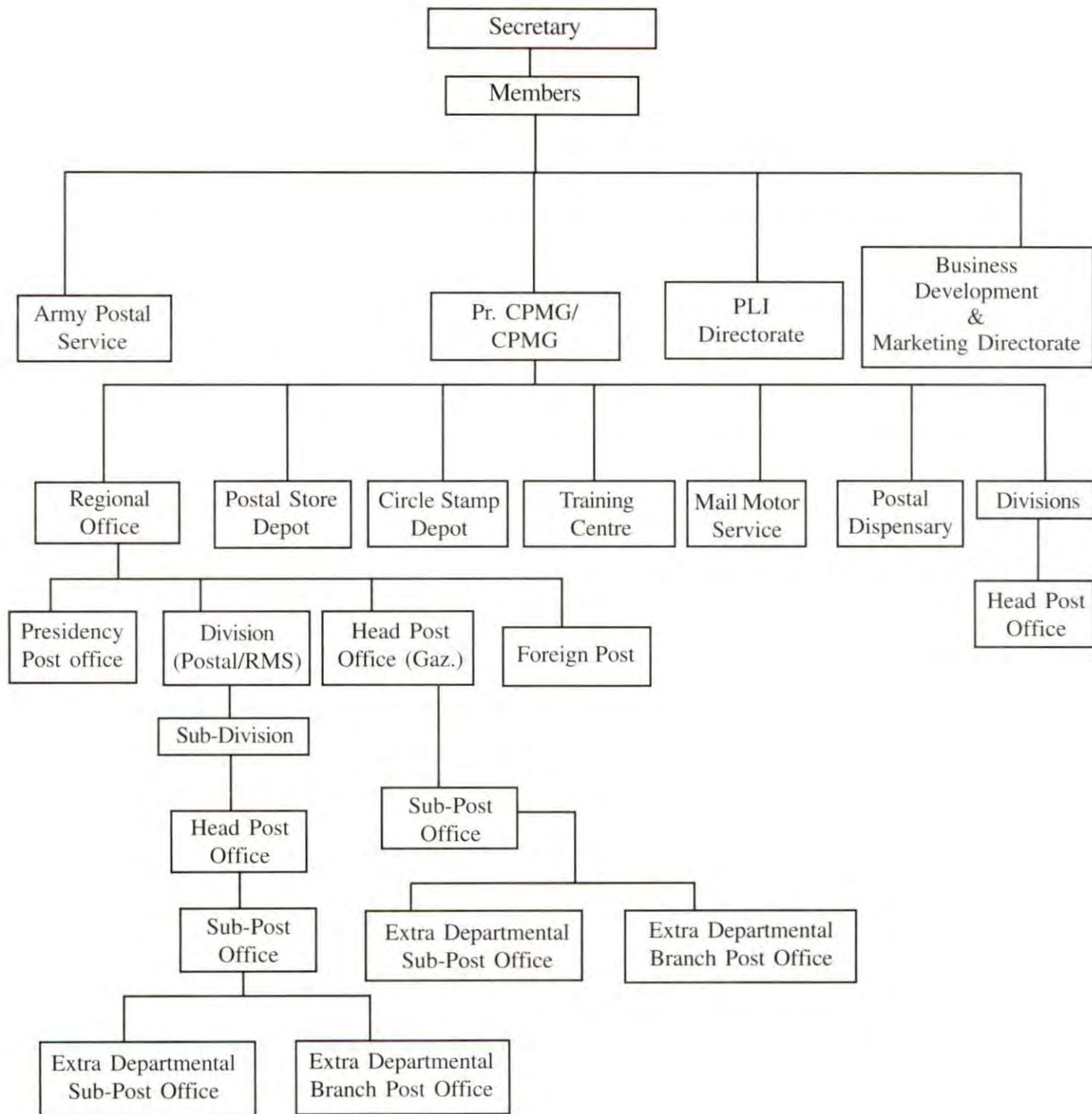


डाक विभाग



टिप्पणी :- कुछ सर्किलों में डाक भंडार डिपो/डाक औषधालय क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल के नियंत्रणाधीन हैं।

DEPARTMENT OF POSTS



Note:- In some of the circles, Postal Store Depot/Postal Dispensaries are under the control of Regional Postmasters General.

अध्याय 3

डाक प्रचालन

डाक नेटवर्क

3.1 भारत का विश्व में 1,55,516 डाकघरों के साथ सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जिसमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 23,344 डाकघर थे जो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में थे। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात से इस नेटवर्क में 7 गुना वृद्धि हुई है और यह विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। औसतन एक डाकघर 21.13 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र तथा 6,615 की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है।

3.2 देश के डाक नेटवर्क का विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को खोलकर किया गया। अतिरिक्त विभागीय डाकघर अंशकालिक आधार पर कार्य करते हैं जिसमें कार्य अवधि न्यूनतम तीन घंटे और अधिकतम 5 घंटे होनी चाहिए। उन्हें अंशकालिक स्थानीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जिन्हें प्रदत्त सेवा के लिए भत्ता दिया जाता है। दूसरी ओर विभागीय डाकघर आठ घंटे की अवधि के लिए कार्य करता है तथा उन्हें पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है।

3.3 डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए डाकघर खोलने के लक्ष्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत शुरुआत से रखे गए हैं। योजना सहयोग नए डाकघर खोलने की आवर्ती एवं अनावर्ती लागतों के लिए भी उस योजना अवधि में उपलब्ध था जिसमें वे खोले गए थे। डाकघरों को दूरी, जनसंख्या तथा आय मानदंडों के आधार पर जिन्हें इस प्रयोजन हेतु निर्धारित किया गया है, खोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए सभी डाकघरों को रियायत दी जाती है तथा यह सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 66.67% से पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 85% तक दी जाती है। तथापि शहरी क्षेत्रों में डाकघरों को कोई रियायत प्रदान नहीं की जाती क्योंकि उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय रूप से

आत्मनिर्भर हो तथा प्रथम वर्ष के पश्चात अपनी लागत से 5% अधिक अर्जित करें।

3.4 नेटवर्क के विस्तार की नीति में हाल के वर्षों में कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसमें विभाग के घाटे को कम करने में ध्यान दिया गया है जिसमें 40% से अधिक नेटवर्क में दी जाने वाली रियायत के कारण है। परियोजना हेतु योजना सहयोग योजना लक्ष्यों में कमी के फलस्वरूप कम हो गया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग भी पर्याप्त रूप से कम हुआ है, अब योजना धनराशि को प्रत्येक डाकघर खोलने के लिए केवल एक समय के अनावृत्ति व्यय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। कोई डाकघर खोलने के लिए आवश्यक मैनपावर को भी मौजूदा संसाधनों को पुनःव्यवस्थित करके पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार जनवरी 2003 से सर्किल अध्यक्षों को एक दूसरे के निकट अवस्थित एक या दो कर्मचारी वाले डाकघरों को पुनःव्यवस्थित करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात् न्यूनतम निर्धारित दूरी से कम उन क्षेत्रों में जिन्हें डाकघर सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी प्रकार जनवरी, 2005 से उन्हें सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के नजदीक स्थित अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को जरूरतमंद क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने की शक्तियां दी गई हैं। इससे विभाग को जरूरतमंद क्षेत्रों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने और साथ ही नेटवर्क का यौक्तिकरण करने में मदद मिली है, जो 10वीं योजना नीति के अंतर्गत आवश्यक है।

3.5 मितव्ययी तरीकों से डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के तरीकों की पहचान हेतु भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। लाइसेंसशुदा स्टैम्प वेन्डर स्कीम, लाइसेंसशुदा पोस्टल एजेंट्स स्कीम तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र कुछ ऐसे कदम हैं जो इस संबंध में उठाए गए हैं। अब तक दसवीं योजना के अंतर्गत 7,697 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए हैं जिसमें 2,371 पंचायत संचार सेवा केन्द्र सम्मिलित हैं। जैसे कि इन स्कीमों का



Chapter 3

POSTAL OPERATIONS

Postal Network

3.1 India has the largest Postal network in the world with 1,55,516 Post Offices of which 89% are in the rural areas. At the time of independence, there were 23,344 Post Offices, which were primarily in the urban areas. Thus the network has registered a seven-fold growth since independence; the focus of this expansion is primarily in the rural areas. On an average, a Post Office serves an area of 21.13 sq. km. & population of 6,615.

3.2 Expansion of Postal Network in the country, especially in rural areas, was done mainly by opening Extra Departmental Post Offices. The Extra Departmental Post Office functions on part-time basis for minimum of three hours and a maximum of five hours. They are manned by part-time locally recruited employees, who are paid an allowance for the services they render. On the other hand, the Departmental Post Office function for a period of eight hours and is manned by full-fledged departmental employees.

3.3 Targets for opening Post Offices for expansion of the Postal Network have been given since inception under Annual Plans. Plan support was also available for the recurring and non-recurring costs of the new Post Offices during the plan period in which they were opened. Post Offices are opened subject to distance, population and income norms fixed for the purpose. Subsidy is also given to all Post Offices opened in the rural area, and it ranges from 66.67% in normal rural area to 85% in hilly, tribal, desert and remote areas. However, no subsidy is offered to Post Offices in urban areas, as they are expected to be financially self-sufficient and earn 5% more than their costs after the first year.

3.4 The strategy for expansion of the network has undergone some modifications in recent years with increasing focus on reducing the deficit of the Department, over 40% of which is attributed to the subsidy on the network. Plan support for the scheme has dwindled substantially as a result of reduction of Plan Targets; financial support under Plan has also reduced substantially, as Plan funds being made available for a one time non-recurring expenditure only for opening of every new Post Office. The manpower requirements for opening a Post Office are also being met only through redeployment of existing resources. Similarly, since January, 2003 Heads of Circles have been empowered to re-deploy existing single or double handed Post Offices located in close proximity to each other, i.e. at lesser than the minimum prescribed distance, to areas which are in need of Post Office facilities. Similarly, since January, 2005 they have been empowered to relocate Extra Departmental Branch Post Offices located in close proximity in normal rural areas to the needy areas. This has helped the Department to meet the emerging requirements in needy areas, while simultaneously rationalizing the network, as required under the 10th Plan Policy initiatives.

3.5 Efforts are also being made to identify means of providing postal services through more cost effective measures. The Licensed Stamp Vendor Scheme, Licensed Postal Agents Scheme and the Panchayat Sanchar Seva Yojana (PSSY) were some of the initiatives that were taken up in this regard. So far 7,697 Panchayat Sanchar Sewa Kendras (PSSKs) have been opened, including 2,371 PSSKs under the 10th Plan. As

आकलन उनकी पुनःसंरचना की आवश्यकता दर्शाता है, चालू वर्ष में पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखे गए थे।

3.6 नेटवर्क की रिटेलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। चालू वर्ष में एक उठाया गया महत्वपूर्ण कदम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाक नेटवर्क के माध्यम से मैसर्स ओरिएंटल इंडियोरेंस कम्पनी लिमिटेड के गैर-जीवन बीमा उत्पाद की रिटेलिंग है। नेटवर्क का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के माध्यम से वायरलेस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बीएसएनएल के फ्रैन्चाइजी के रूप में ग्राहकों के द्वार तक मोबाइल पीसीओ सुविधा प्रदान करने के लिए भी हो रहा है।

डाक सेवाएं

3.7 डाकघर में डाक प्रचालनों में अन्य सेवाओं के साथ-साथ निम्नलिखित मूल डाक सेवाओं का समूचा क्षेत्र शामिल है:-

- (i) डाक-टिकट तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री
- (ii) पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग
- (iii) बीमाकृत वस्तुओं की बुकिंग
- (iv) मूल्यदेय वस्तुओं की बुकिंग
- (v) मनीआर्डर और पोस्टल आर्डरों के माध्यम से धन प्रेषण
- (vi) पार्सलों की बुकिंग

3.8 परंपरागत रूप से ये सेवाएं मैनुअल काउंटरों पर प्रदान की जा रही थीं। ग्राहकों को प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब काउंटर प्रचालनों को उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि एक ही खिड़की से अधिकाधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकें जिससे सेवाएं अधिक अनुक्रियाशील हों और उनमें गलती की संभावना भी कम हो।

मनीआर्डर सेवा

3.9 पिछले वर्ष के परियात की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पारेषित मनीआर्डर के मूल्य तथा मनीआर्डर परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-1 में दिए गए हैं।

तालिका 1 मनीआर्डर परियात तथा मूल्य (मिलियन में)			
	2003-04	2004-05*	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1. मनीआर्डर परियात	110.15	120.65	9.53%
2. पारेषित मनीआर्डरों का मूल्य	68750.24	70521.65	2.58%

*अनंतिम

डाक प्रचालन

3.10 डाक प्रोसेसिंग, पारेषण तथा उनका वितरण विभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। देश की 5,84,006 पत्र-पेटियों से पत्रों को एकत्रित किया जाता है। 460 रेल डाक सेवा (आर एम एस) कार्यालयों के नेटवर्क पर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है तथा देश

भर में सड़क, रेल तथा वायुयान द्वारा इन्हें प्रेषित किया जाता है।

डाक की मात्रा

3.11 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान डाक परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-2 में दिए गए हैं।

the assessment of these schemes indicates the need for restructuring them, therefore, no targets were fixed in the current year for opening of PSSKs.

3.6. Efforts are also underway to optimize the retailing capacity of the network. One major initiative already taken up in the current year is the retailing of non-life insurance products of M/s. Oriental Insurance Company Limited through the postal network to cater to the requirements of various segments of society in urban and rural sector. The network is also being utilised to provide mobile PCO facility at the doorstep of the customers in rural areas through GDS Employees of Department of Posts, as franchisees of BSNL, using the Wireless in Local Loop (WLL) Technology.

Postal Services

3.7 Postal operations at the post office encompass the entire gamut of the basic postal services which interalia include:

- (i) Sale of stamps and stationery
- (ii) Booking of registered articles
- (iii) Booking of insured articles
- (iv) Booking of value payable articles
- (v) Remittance of money through money orders and postal orders
- (vi) Booking of Parcels

3.8 Traditionally, these services were being provided at manually operated counters. Considering the vital need for providing the benefit of technology to the customers, the counter operations are now being progressively computerised to provide a greater range of service to the customer from a single window leading to services being more responsive, and error free.

Money Order Service

3.9 Comparative statistics of Money Order traffic and the value of Money Orders transmitted, compared with the previous year is given in Table 1.

TABLE 1 MONEY ORDER TRAFFIC AND VALUE (in Million)			
	2003-2004	2004-2005*	Increase/Decrease (in % age)
1. Money Order traffic	110.15	120.65	9.53 %
2. Value of MOs transmitted	68750.24	70521.65	2.58 %

* Provisional

Mail Operations

3.10 Mail processing, transmission and delivery are the core activities of the Department. Mail is collected from 5,84,006 letter boxes in the country. This is processed by a network of 460 Railway Mail Service

Offices, and conveyed by road, rail and airlines all over the country.

Mail Volume

3.11 Comparative statistics of mail traffic handled during 2004-2005 as compared to previous year is given in Table-2.

तालिका 2
डाक परियात (मिलियन में)

	2003-04	2004-05	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1. पंजीकृत वस्तुएं	213.59	214.18	(+)0.28 %
2. अपंजीकृत वस्तुएं	8421.64	7146.18	(-)15.15%
कुल (1+2)	8635.23	7360.36	(-)14.76%

डाक प्रबंधन

3.12 देशभर में अत्यधिक प्रभावी और अधिकतम कुशल डाक पारेषण नेटवर्क स्थापित करने की योजनाओं को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभाग ने डाक परियात के विभिन्न भागों का पता लगाया है और प्रत्येक भाग के लिए परियात के निपटान का विशिष्ट तरीका निश्चित किया है। इस प्रकार महानगरों के बीच की डाक के लिए मैट्रो चैनल, राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों के बीच तथा इसके विपरीत के लिए राजधानी चैनल, स्थानीय डाक के लिए ग्रीन चैनल, थोक डाक के लिए बिजनेस चैनल और समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए पत्रिका चैनल जैसे विशिष्ट चैनल बनाए गए हैं।

3.13 दीपावली, क्रिसमस, रक्षाबंधन तथा नववर्ष जैसे फैस्टिवल सीजन के दौरान डाक की मात्रा में होने वाली आकस्मिक वृद्धि से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रमुख शहरों में, लोगों को उनके पत्र सीधे गंतव्य थैलों में डालने के लिए उचित सुझाव दिया गया जिससे प्रेषितियों को पत्रों का वितरण जल्दी किया जा सके।

डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण

3.14 विभाग ने डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण की एक नीति प्रारंभ की है। डाक कार्यालयों के आधुनिकीकरण का उद्देश्य डाक कार्यालयों में बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना और बेहतर कार्य के वातावरण का निर्माण करना है जिससे संपूर्ण कार्यकुशलता प्राप्त हो सके।

3.15 लेखादेय मदों जैसे पंजीकृत पत्रों, बीमाकृत मदों आदि की छंटाई को इन मदों के त्वरित निपटान एवं सुरक्षा के उद्देश्य से और शिकायतों/पूछताछ के मामले में अधिक शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

3.16 वर्ष के दौरान 29 मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है जबकि समीक्षाधीन अवधि के अंतर्गत 10 प्रधान रिकॉर्ड कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। विभाग द्वारा रेलवे कोच फैक्टरी, कपूरथला, पंजाब के माध्यम से 25 नई ब्रॉड गेज पूर्ण बोगी डाक वैन बनवाई गई।

मेल मोटर सेवा (एम एम एस)

3.17 मेल मोटर सेवा विभाग के 1149 मेल मोटर वाहनों और 486 स्टाफ कारों/निरीक्षण वाहनों के रखरखाव, प्रचालन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। विभाग के अपने मेल मोटर वाहन 94 स्टेशनों में चलते हैं। इनमें से 17 स्टेशनों पर बड़े मरम्मत कार्य और रखरखाव कार्य करने के लिए पूर्ण विकसित वर्कशाप सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान, विभागीय डाक वाहनों ने डाक प्रेषित करने के लिए 25.52 मिलियन कि.मी. की दूरी तय की। इस अवधि के दौरान एम.एम.एस. पर 506.75 मिलियन रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 2004-05 के दौरान औसत लागत प्रति कि.मी. 19.86 रु. थी। अब मेल मोटर सेवा सक्रिय रूप से पर्यावरण में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहा है। मुम्बई में शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इसने वहां 105 सीएनजी प्रोपेल्ड मेल वैन खरीदी हैं। अब मेल मोटर सेवा संगठन में यातायात नियंत्रण प्रणाली मानव-संचालित न होकर कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है। सभी एमएमएस डिपो को यातायात नियंत्रण पर विभाग में ही विकसित किए गए साफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

TABLE 2
MAIL TRAFFIC (in Million)

	2003-2004	2004-2005	Increase/Decrease (in %age)
1. Registered	213.59	214.18	(+) 0.28%
2. Unregistered	8421.64	7146.18	(-) 15.15%
TOTAL (1+2)	8635.23	7360.36	(-) 14.76%

Mail Management

3.12 Plans for achieving an efficient mail transmission network throughout the country have been put into effect. With this objective the Department has identified different segments of mail traffic and devised exclusive handling for each segment. Thus, there are specialised channels like Metro Channel for mail between metro cities, Rajdhani Channel for mail between the national capital and the state capitals and vice-versa, Green Channel for local mail, Business Channel for bulk mail and Patrika Channel for newspapers and periodicals.

3.13 Special arrangements to meet the sudden spurt in traffic during festival season like Diwali, Christmas, Raksha Bandhan and New Year were made. In major towns, appropriate guidance was provided to the members of the public to post their letters directly into the destination mail-bags to speed up transmission and delivery to the addressees.

Modernisation and Computerisation of Mail Operations

3.14 In order to expedite transmission, processing and delivery of mail, the Department has embarked on a policy of computerisation and modernisation of the mail processing, transmission and delivery in post offices. The modernisation of mail offices aims at providing better equipment and improved work environment in the Mail Offices.

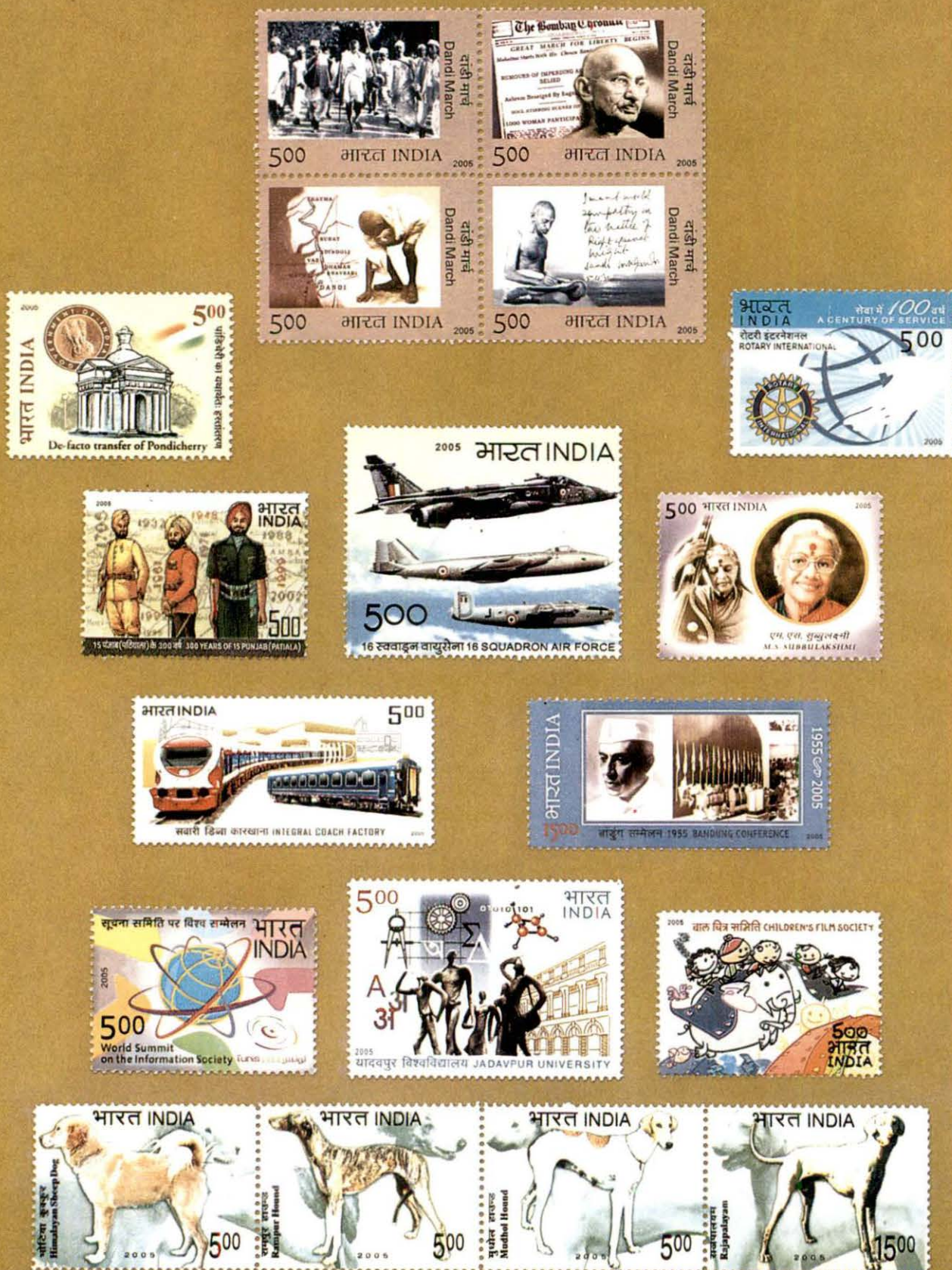
3.15 Sorting of accountable articles like Registered Letters, Insured Articles etc., has been computerised for speedy and safe handling of articles and for more expeditious response in case of enquiries.

3.16 During the year, 29 Mail Offices were modernised, while 10 Head Record Offices were computerised. 25 new Broad Gauge Full Bogie Postal Vans were got manufactured by the Department through Railway Coach Factory, Kapurthala(Punjab).

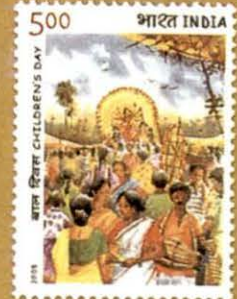
Mail Motor Service (MMS)

3.17 The Mail Motor Service is responsible for maintenance, operations and administration of 1149 Mail Motor Vehicles and 486 staff cars/inspection vehicles of the Department. The Department operates its own fleet of mail motor vehicles at 94 stations. Full-fledged workshop facilities for major repairs and maintenance are available at 17 of these stations. During 2004-2005, the MMS Vehicles covered 25.52 Million Kms. for conveyance of mails. A total expenditure of Rs. 506.75 Million was incurred on MMS during this period. During the year 2004-05, the average cost per Km. was Rs. 19.86. The Mail Motor Service is now actively participating to improve the condition of environment. It has introduced 105 CNG propelled Mail Vans in Mumbai to reduce pollution level of the city. Now the Traffic control system in MMS Organisation has been switched over from manual to computerised system. The in-house developed software on Traffic Control has been provided to all MMS Depots.

कुछ विशेष डाक-टिकट



SOME THEMATIC STAMPS



अध्याय 4

फिलैटली

डाक-टिकट

4.1 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भ में डाक-टिकटों के माध्यम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को उजागर करने में प्रयुक्त किया गया एवं इनमें पंचवर्षीय योजनाओं, इस्पात संयंत्रों, बांधों आदि जैसे विषयों को दर्शाया गया। इसके बाद, देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर को दर्शाया जाने लगा तथा कला, स्थापत्य, समुद्री विरासत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं सिनेमा पर विषयपरक सेटों में अनेक सुन्दर डाक-टिकट जारी किये गए। स्मारक डाक-टिकटों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले महान नेताओं को भी सम्मानित किया गया है इनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। चित्रकारी, साहित्य, संगीत, सामाजिक उत्थान आदि क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान करने वाले महापुरुषों को भी स्मारक डाक-टिकटों द्वारा सम्मानित किया गया है। एक प्रकार से, डाक-टिकटें डाक-शुल्क भुगतान के अपने मूल उद्देश्य के अलावा देश के लिए सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका भी निभा रही हैं।

4.2 डाक-टिकटों की "डाक-शुल्क का भुगतान" एवं "सांस्कृतिक राजदूत" की दोहरी भूमिका को देखते हुए दो श्रेणी की डाक-टिकटें अस्तित्व में आई हैं अर्थात् "नियत डाक-टिकटें" एवं "स्मारक डाक-टिकटें"। प्रथम डाक-टिकटें डाक मदों पर डाक-शुल्क के भुगतान के रूप में दैनन्दिन प्रयोग के लिए हैं। इनमें कम डिजाइन आगत निहित हैं जिससे उनके निर्माण पर कम व्यय आता है और उन्हें बड़ी मात्रा में मुद्रित करवाया जाता है। दूसरी श्रेणी की डाक-टिकटों को सौन्दर्यपरक दृष्टिकोण से डिजाइन एवं मुद्रित किया जाता है। इन्हें कम मात्रा में मुद्रित करवाया जाता है और यह डाक-टिकट संग्रहकर्ताओं में अधिक रुचि जागृत करती हैं।

4.3 भारत की फिलैटलिक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- विशेष/स्मारक डाक-टिकटों की डिजाइनिंग, मुद्रण एवं वितरण।
- नियत डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्रकार्ड, पोस्टकार्ड, हवाई पत्र एवं रजिस्टर्ड आवरण आदि मदों की डिजाइनिंग, मुद्रण एवं वितरण।
- फिलैटली का संवर्धन। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर फिलैटलिक प्रदर्शनियों का आयोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व प्रदर्शनियों में भाग लेना एवं राज्य/क्षेत्रीय और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों की मॉनीटरिंग करना शामिल है।
- राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय, डाक भवन की देखरेख करना।

फिलैटली पर नीति

4.4 स्मारक डाक-टिकट जारी करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम पर सरकार को सलाह देने के लिए एक फिलैटली सलाहकार समिति (पीएसी) का गठन किया गया है। विभाग संसद एवं राज्य विधान सभा के सदस्यों, राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों और संस्थानों और व्यक्तियों से डाक-टिकट जारी करने के संबंध में प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में प्रस्ताव प्राप्त करता है। डाक-टिकटों के जारी किये जाने के समय उनका फिलैटलिक मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति कुछ दिशा-निर्देशों के आधार पर इन प्रस्तावों की जांच करती है तथा डाक-टिकटों के मुद्रण एवं विक्रय क्षमता के दृष्टिगत वार्षिक डाक-टिकट जारी किये जाने संबंधी कार्यक्रम की अनुशंसा करती है। फिलैटली सलाहकार समिति फिलैटली एवं इसके संवर्धन संबंधी नीतिगत मुद्दों की भी



Chapter 4

PHILATELY

The Postage Stamp

4.1 After independence, the medium of postage stamps was initially used to highlight the country's achievements in science and technology as well as its socio-economic development by depicting themes like the Five-Year Plans, Steel Plants, Dams, etc. Subsequently, the country's rich cultural and natural heritage came to be showcased and many beautiful stamps were issued in thematic sets on art, architecture, maritime heritage, science, technology, defence and cinema. Great leaders of national and international standing have also been honoured with commemorative stamps, the most prominent being Mahatma Gandhi, the Father of the Nation. Personalities, who have made immense contributions in areas like painting, literature, music, social upliftment etc., have also been honoured with commemorative stamps. In a sense stamps have come to play the role of cultural ambassadors for the country apart from its primary purpose of being a token of payment of postage.

4.2 In keeping with its dual character of "Token of Postage" and "Cultural Ambassadors" two categories of stamps have emerged, viz. the "Definitive Postage Stamps" and the "Commemorative Postage Stamps". The former is meant for day-to-day use as token of payment of postage on mail articles. They incorporate less design inputs entailing minimum expenditure in their manufacture, and are printed in large quantities. The latter, on the other hand, are designed and printed with greater aesthetic inputs. They are manufactured in smaller quantities and generate more interest among stamp collectors.

4.3 The philatelic activities of India Post include:-

- Designing, printing and distribution of special/commemorative postage stamps.
- Designing, printing and distribution of definitive postage stamps and items of postal stationery like Envelope, Inland Letter Card, Postcard, Aerogram and Registered Cover etc.
- Promotion of Philately. This also entails conducting Philatelic Exhibitions at the national level and participation in international and world exhibitions, as well as monitoring of exhibitions at State/Regional and District levels.
- Maintenance of the National Philatelic Museum, Dak Bhavan.

Policy on Philately

4.4 A Philatelic Advisory Committee (PAC) has been constituted to advise the Government on the annual programme for issue of commemorative stamps. Every year, the Department receives a large number of proposals for issue of stamps from Members of Parliament and State Legislative Assemblies, State Governments and other organizations and institutions, and individuals. The Committee examines these proposals on the basis of certain guidelines meant to ensure the philatelic value of the stamps when issued, and recommends the annual stamp issue programme, taking into account also the capacity to print and sell. The PAC also examines policy issues related to philately.

जांच करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। समिति में डाक विभाग एवं आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से सरकारी सदस्य एवं नामांकन द्वारा गैर-सरकारी सदस्य शामिल किये जाते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों को संसद सदस्यों एवं प्रसिद्ध फिलैटलीविदों एवं जीवन के विविध क्षेत्रों जैसे कला, संग्रहालय विद्या, पुरातत्व विज्ञान, डिजाइन, फोटोग्राफी एवं शिक्षा के क्षेत्र से प्रख्यात लोगों में से चुना जाता है।

फिलैटली का उन्नयन

4.5 डाक विभाग ने फिलैटली को ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, हांगकांग, थाइलैंड आदि अनेक अन्य डाक प्रशासनों के अनुभव के अनुसरण में राजस्व अर्जन के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में अपनाया है। विभाग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान फिलैटली के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

- योजना गतिविधियों के भाग के रूप में समूचे देश में जिला स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन।
- फिलैटलिक ब्यूरो, जो ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने के स्थान हैं, का प्रौद्योगिकीय एवं सौन्दर्यपरक उन्नयन।
- अधिकारियों एवं स्टाफ का गहन प्रशिक्षण।
- फिलैटली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बाजार सर्वेक्षण/प्रचार प्रक्रियाएं अपनाना।
- बाल दिवस यानी 14 नवम्बर को विद्यालय के छात्रों के मध्य वार्षिक डाक-टिकट डिजाइन प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। 1999 से प्रतिवर्ष डाक-टिकट डिजाइन स्पर्धा की श्रेष्ठतम प्रविष्टि को अगले वर्ष जारी की जाने वाली बाल दिवस डाक-टिकट के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

पंजीकृत ग्राहक

4.6 फिलैटली के उन्नयन के लिए विभाग के समेकित प्रयासों से देश के विभिन्न भागों में फिलैटली के प्रचार-प्रसार को एक

शौक के रूप में बेहद बढ़ावा मिला है। फिलैटलिक जमा खाते की मार्फत डाक-टिकटों की नियमित आपूर्ति के लिए विभाग के पास पंजीकृत ग्राहकों की संख्या जो वर्ष 1999-2000 में 23,905 थी, वर्ष 2004-05 में बढ़कर 1,10,288 हो गई है। विभाग द्वारा हाल ही में किये गए एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार देश में डाक-टिकट संग्रहकर्ताओं की कुल संख्या चालीस लाख से अधिक होने का अनुमान है।

डाक-टिकट एवं लेखन सामग्री

4.7 वर्ष 2004-05 के दौरान, कला एवं संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह, अंतर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय संबंधों आदि पर सुन्दर डाक-टिकटों सहित चौंसठ (64) नियत/स्मारक/विशिष्ट डाक-टिकट जारी किये गए हैं। अधिक रुचिकर एवं महत्वपूर्ण विषय रहे: भा.नौ.पो. तरंगिणी द्वारा परिनौसंचालन यात्रा; महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण; भारत-ईरान संयुक्त डाक-टिकट; भारतीय डाक के 150 वर्ष; आगरा किला; ताजमहल; संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारतीय सेना की भूमिका; श्वानों की प्रजातियां; पूर्वोत्तर भारत के वनस्पति एवं जीव-जन्तु; एवं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष (नियत)।

4.8 जन जागृति आदि लाने के लिए डाक लेखन सामग्री की विभिन्न मदों यथा पोस्टकार्ड, लिफाफे, पंजीकृत लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड एवं हवाई पत्रों पर अंग्रेजी, हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में सामाजिक रूप से संगत संदेश जारी किये गए।

4.9 देशभर में सभी प्रधान डाकघरों एवं मुख्य डाकघरों सहित, 67 फिलैटलिक ब्यूरो और लगभग 1,111 फिलैटलिक काउंटरों द्वारा फिलैटलिक मदों की बिक्री की जाती है। वर्ष 2004-05 के दौरान अर्जित फिलैटलिक राजस्व 251.10 मिलियन रुपये था।

4.10 देश में बच्चों के लिए 14 नवम्बर, 2004 को "डाक-टिकट डिजाइन प्रतिस्पर्धा, 2004" का आयोजन किया गया। डाक-टिकट डिजाइन का शीर्षक त्यौहार/समारोह था।

and its promotion and submits its recommendations. The Committee comprises official members from the Departments of Posts and Economic Affairs as well as non-official members by nomination. The non-official members are drawn from among the Members of Parliament and noted philatelists as well as eminent personalities from various walks of life like art, museology, archaeology, design, photography and academic.

Promotion of Philately

4.5 Philately has been taken up by the Department of Posts as a priority revenue generation area, in line with the experience of a number of other postal administrations such as Britain, France, USA, Hong Kong, Thailand, etc. Various measures taken by the Department to promote and develop philately during the last few years include the following :-

- Holding of District Level Exhibitions across the country as part of Plan activities.
- Technological and aesthetic upgradation of the Philatelic Bureaux, which are the points of customer inter-face.
- Extensive training of officers and staff.
- Market survey/publicity exercises to generate awareness about philately.
- Annual Stamp Design Competition held among school children on 14th November i.e. on Children's Day. Every year, since 1999, the best entry of the Stamp Design Competition is being used as the basis of the Children's Day stamp brought out in the next year.

Registered Customers

4.6 The Department's concerted efforts for promotion of Philately has given a tremendous boost to

the popularity of philately as a hobby in different parts of the country. The number of customers registered with the Department for regular supply of stamps through Philatelic Deposit Account, which stood at 23,905 in 1999-2000, has increased to 1,10,288 by 2004-2005. The total number of stamp collectors in the country is estimated at over four million as per an independent study commissioned by the Department recently.

Stamps and Stationery

4.7 Sixty four definitive/commemorative/special postage stamps have been issued during 2004-2005 including beautiful stamps on art and culture, international sporting events, international and bilateral relations, etc. Among the more interesting and significant issues were the stamps/sets on Circumnavigation of INS Tarangni; the great Trigonometrical survey; Indo-Iran Joint Issue; 150 years of India Post; Agra Fort; Taj Mahal; Role of Indian Army in UN Peace Keeping Operations; Breeds of Dogs; Flora and fauna of North-East India, and the International Year of Physics(Definitive).

4.8 Items of postal stationery viz. postcard, envelope, registered envelope, inland letter card and aerogram carrying advertisements, socially relevant messages aimed at generating public awareness, etc., in English, Hindi as well as regional languages have been issued.

4.9 Sale of philatelic items is carried out all over the country through 67 Philatelic Bureaux and around 1,111 Philatelic Counters including all the Head Post Offices and Mukhya Dak Ghars of the country. Philatelic revenue earned during the year 2004-05 was Rs. 251.10 Million.

4.10 The "Design a Stamp Competition, 2004" for children was held all over the country on 14th November, 2004. The theme for the stamp design was 'Festivals/Celebrations'.

फिलैटलिक प्रदर्शनियां

4.11 भारतीय डाक ने वेलेंशिया (स्पेन) एवं सिंगापुर में आयोजित दो अंतर्राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनियों में आमंत्रित श्रेणी में डाक-टिकट प्रदर्शित कर भाग लिया। भारतीय डाक ने रोमानिया, चीन, स्वीडन एवं डेनमार्क में आयोजित, घरेलू प्रदर्शनियों/संयुक्त फिलैटलिक प्रदर्शनियों में प्रदर्श सामग्री भेजकर, चार अन्य प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

4.12 सर्किलों द्वारा राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्र/जिला स्तर पर आयोजित बीस प्रदर्शनियों में भाग लेकर आमंत्रित श्रेणी में राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहालय की डाक प्रदर्श सामग्री प्रदर्शित की गई।

4.13 भारतीय डाक ने विश्व फिलैटली विकास संघ (डब्ल्यूएडीपी) में एक गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त की चूंकि डाक सचिव अगस्त, 2004 तक इसके अध्यक्ष रहे।

4.14 भारतीय डाक के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय डाक ने चार स्मारक डाक-टिकट जारी करने के अलावा, 100 रुपये एवं 1 रुपये के स्मारक सिक्के भी जारी किये। डाक -टिकट एवं सिक्के भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर, 2004 को आयोजित एक समारोह में जारी किये गए।

4.15 भारतीय डाक के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय डाक ने पहली बार 26 जनवरी, 2005 को गणतंत्र दिवस की परेड में एक झांकी निकाली।

Philatelic Exhibitions

4.11 India Post participated in two International Philately Exhibitions held at Valencia (Spain) and Singapore by exhibiting stamps in the invitee class. India Post also participated in four other exhibitions held at Romania, China, Sweden and Denmark by sending exhibits for display in domestic exhibitions/joint philatelic exhibitions.

4.12 Exhibits from the National Philatelic Museum were displayed in the invitee class in twenty exhibitions held by the Circles at National/State/Regional/District levels.

4.13 India Post held a prestigious position in the World Association for the Development of Philately (WADP) as Secretary Posts, India was the Chairperson up to August, 2004.

4.14 Apart from a set of 4 commemorative stamps, India Post also brought out commemorative coins of denominations for Rs. 100/- and Re. 1/- on the occasion of 150 years of India Post. The stamps and coins were released by the Hon'ble President of India and Prime Minister of India at a function held on 04th October, 2004.

4.15 For the first time ever the Department of Posts put up a Tableau in the Republic Day Parade on 26th January, 2005, to mark the Sesquicentenary of India Post.

अध्याय 5

व्यवसाय विकास कार्यकलाप

5.1 विभाग के मूल्यवर्धित प्रीमियम उत्पादों के डिजाइन, निगरानी, विकास एवं विपणन के लिए 1996 में व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 2004-05 में व्यवसाय विकास निदेशालय को **व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय** में पुनर्गठित किया गया। निदेशालय में अब एक पार्सल एवं लॉजिस्टिक डिवीजन, एक विपणन डिवीजन और एक प्रचालन डिवीजन है। सभी सर्किलों में विपणन एवं पार्सल डिवीजन भी सृजित किये गए हैं। मेट्रो सर्किलों में विपणन का दायित्व एसएजी स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय का मुख्य दायित्व मूल्यवर्धित सेवाओं में कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वर्तमान मूल्यवर्धित एवं परंपरागत डाक एवं पार्सल उत्पादों और सेवाओं का प्रशासन, विस्तार एवं संवर्धन;
- वित्तीय एवं बीमा उत्पादों एवं सेवाओं को छोड़कर नवीन मूल्यवर्धित उत्पादों एवं सेवाओं की योजना एवं प्रस्तावना;
- उनकी रिटेलिंग एवं नेटवर्किंग के लिए प्रक्रिया, विनियमन एवं दिशा-निर्देश;
- बाजार अध्ययन, बाजार परीक्षण एवं उत्पाद सुधार;
- बाजार नीतियां, गठबंधन एवं सहयोग;
- मूल्यवर्धित उत्पादों एवं सेवाओं की वृद्धि की समीक्षा एवं निगरानी;
- विभाग के निष्क्रिय संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की संभावना की खोज।

उत्पाद

5.2 व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, व्यवसाय डाक-कुल डाक समाधान, सीधी डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत पोस्टकार्ड, लॉजिस्टिक पोस्ट, ई-बिल पोस्ट, ई-पोस्ट, रिटेल पोस्ट एवं बिल मेल सेवा के प्रबंधन एवं विपणन के लिए जिम्मेदार है।

व्यवसाय वृद्धि

5.3 वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान प्रीमियम उत्पादों से अर्जित राजस्व 9,533.40 मिलियन रुपये था। उत्पाद वार राजस्व तालिका 3 में दर्शाया गया है।

विभाग के समग्र राजस्व में प्रीमियम उत्पादों से राजस्व का अंश वर्ष 2004-05 में 21.51 प्रतिशत से अधिक था। पिछले कुछ वर्षों में यह निरंतर बढ़ रहा है जैसा चित्र से स्पष्ट है।

स्पीड पोस्ट

5.4 तीव्र एवं समयबद्ध वितरण सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत, सात मेट्रो शहरों को जोड़ते हुए वर्ष 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। आज स्पीड पोस्ट के नेटवर्क में, 157 राष्ट्रीय एवं 953 राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क की मार्फत, व्यवहारिक तौर पर, भारत के सभी प्रमुख शहर एवं कस्बे जुड़े हैं। इसके अलावा, 97 देशों के महत्वपूर्ण शहरों में स्पीड पोस्ट मर्चें भी बुक की जा सकती हैं।

5.5 स्पीड पोस्ट देश एवं विश्व भर में ग्राहकों को पत्रों, कागजात एवं पार्सल के रूप में, प्रत्येक 35 कि.ग्रा. तक, समयबद्ध एवं आश्वस्त वितरण सेवा प्रदान करती है। स्टेशनों को जोड़ने के लिए उपलब्ध तीव्रतर परिवहन वाहन के दृष्टिगत वितरण मानक निर्धारित किये जाते हैं। इसके प्रचालन एवं प्रबंध में, वाणिज्यिक रवैया के तौर पर, व्यवसाय सेवा के रूप में इसकी व्यवस्था की जाती है।

Chapter 5

BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES

5.1 Business Development Directorate was set up in 1996 to design, monitor, develop and market value-added premium products of the Department. The Business Development Directorate was reorganized into **Business Development and Marketing Directorate** in the year 2004-05. The Directorate now has a Parcel and Logistics Division, a Marketing Division and an Operations Division. Marketing and Parcel Divisions have also been created in all the Circles. In the Metro Circles, the responsibility for marketing has been assigned to SAG level officers. The main responsibility of the Business Development and Marketing Directorate is to ensure focused management of value added services and it includes the following :-

- Administration, expansion and promotion of the existing value-added and traditional mail and parcel products and services;
- Planning and introduction of new value-added products and services, except financial and insurance products and services;
- Procedures, regulations and guidelines for their retailing and networking;
- Market study, market testing and product improvement;
- Market strategies, alliances and cooperation;
- Monitoring and review of growth of value-added products and services;
- Exploring the scope of commercial utilization of idle resources of the Department.

Products

5.2 The Business Development and Marketing Directorate is responsible for the management and marketing of Speed Post, Speed Post Passport Service, Business Post – Total Mailing Solutions, Direct Post, Express Parcel Post, Media Post, Meghdoot Post Card, Logistics Post, e-Bill Post, e-Post, Retail Post and Bill Mail Service.

Business Growth

5.3 During the financial year 2004-05, the revenue realized from premium products was Rs. 9,533.40 Million. The Product-wise revenue is reflected in Table-3.

The share of revenue from Premium Products in the overall revenue of the Department was over 21.51% in 2004-05. It has been growing over the years, as shown in the graph.

Speed Post

5.4 Speed Post Services were introduced in 1986, linking 7 Metro Cities, with a view to provide fast and time-bound delivery services. As on date, Speed Post has a network linking practically all the major towns and cities of India through a network of 157 National and 953 State Speed Post Centres. In addition, the Speed Post articles can also be booked for important cities in 97 countries.

5.5 Speed Post offers the customer, time-specific and assured delivery service of letters, documents and parcels up to 35 Kgs. each across the country and around the world. Delivery norms are fixed taking into account the fastest transport available to link the stations. It is managed as a business service with commercial approach in its operations and management.

तालिका 3
व्यवसाय विकास कार्यकलापों की उत्पादवार राजस्व वृद्धि

(मिलियन रु. में)

उत्पाद	वर्ष 2003-04 में राजस्व	वर्ष 2004-05 में राजस्व	प्रतिशत वृद्धि
स्पीड पोस्ट	2,983.59	3,541.60	18.70
व्यवसाय पोस्ट	3,651.14	4,730.60	29.57
मीडिया पोस्ट	57.47	63.60	10.67
एक्सप्रेस पोस्ट	314.49	377.00	19.88
रिटेल पोस्ट	336.50	505.00	50.07
बधाई डाक	3.95	4.20	6.33
*अन्य व्यवसाय सेवाएं	125.39	311.40	148.35
कुल	7,472.53	9,533.40	27.58

* अन्य में शामिल है: ई-पोस्ट, ई-बिल पोस्ट, बिल मेल सेवा, स्पीड पोस्ट, पासपोर्ट सेवा आदि।

व्यवसाय विकास के कार्यकलापों का उत्पादवार राजस्व विभाजन
INDIA POST OVERALL Vs. PREMIUM PRODUCTS REVENUE

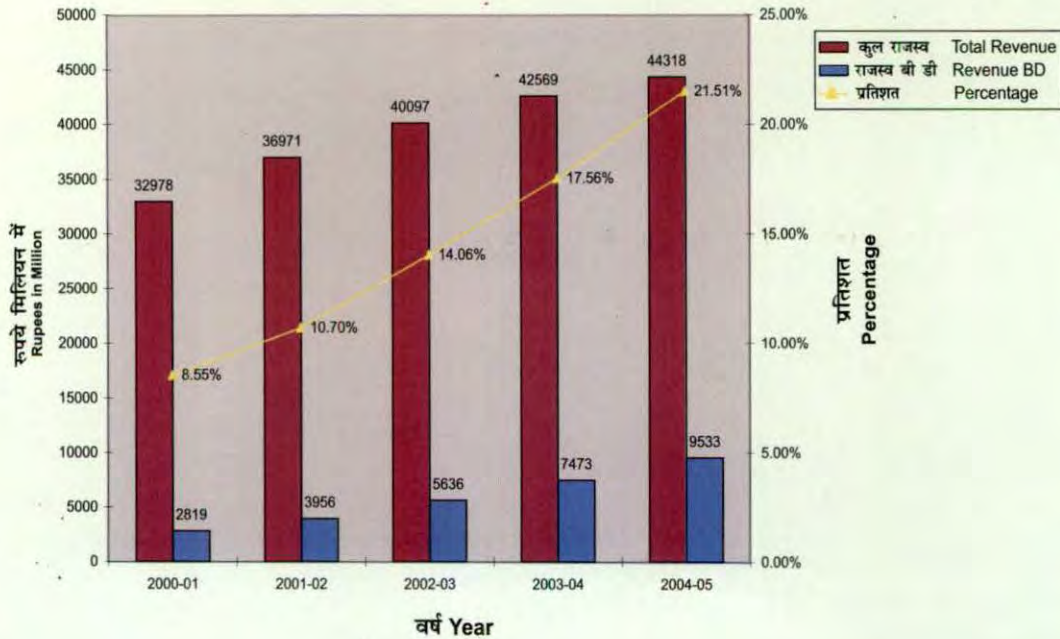
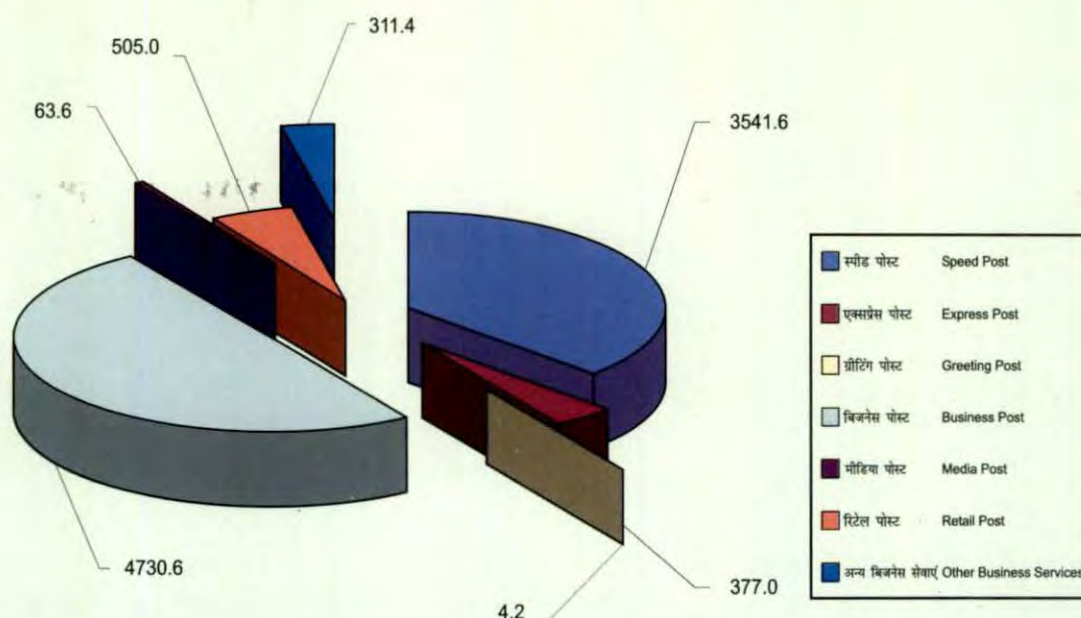


TABLE 3
PRODUCT-WISE REVENUE GROWTH OF BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES
(Rs. in Million)

Product	Revenue in 2003-2004	Revenue in 2004-2005	% of increase
Speed Post	2,983.59	3,541.60	18.70
Business Post	3,651.14	4,730.60	29.57
Media Post	57.47	63.60	10.67
Express Post	314.49	377.00	19.88
Retail Post	336.50	505.00	50.07
Greeting Post	3.95	4.20	6.33
*Other Business Services	125.39	311.40	148.35
Total	7,472.53	9,533.40	27.58

*Others include: e-Post, e-Bill Post, Bill Mail Service, Speed Post Passport Service, etc.

व्यवसाय विकास के कार्यकलापों का उत्पादवार राजस्व विभाजन
2004-05 (रुपये मिलियन में)
Product-wise Revenue Segmentation of Business Development Activities
2004-05 (Rs. in Million)



5.6 स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कागजात और पार्सल के अतिरिक्त, अनेक अन्य सेवाएं प्रस्तावित की जाती हैं। यह स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, स्पीड पोस्ट धनादेश एवं स्पीड पोस्ट उपहार सेवा है। वर्ष 2004-05 के दौरान, स्पीड पोस्ट से राजस्व अर्जन 3,541.60 मिलियन रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्शाता है। स्पीड पोस्ट में ग्राहक सेवा एवं वितरण दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पीड पोस्ट में सर्वाधिक राजस्व महाराष्ट्र सर्किल द्वारा अर्जित किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वर्ष 2004-05 तक 545 स्पीड पोस्ट केन्द्रों में कम्प्यूटर लगाये गए हैं।

ऑनलाइन ट्रैक एवं ट्रेस का क्रियान्वयन

5.7 स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट हेतु इंटरनेट आधारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें ग्राहक विभाग की वेबसाइट www.indiapost.gov.in को खोलकर अपने सामान की स्थिति का ऑनलाइन पता कर सकता है। यह सुविधा राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों एवं चुनिंदा राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों में प्रारंभ की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सभी स्पीड पोस्ट मदों के लिए ट्रैक एवं ट्रेस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सभी राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों को बैंड सर्वर से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2004-05 तक ट्रैक एवं ट्रेस सुविधा हेतु 257 स्पीड पोस्ट केन्द्रों को कम्प्यूटर प्रदान किये गए हैं।

स्पीड पोस्ट के अंतर्गत मूल्यवर्धन

5.8 विभाग ने कारपोरेट ग्राहकों से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धन एवं सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने संबंधी अनेक कदम उठाए हैं। कारपोरेट ग्राहकों के लिए प्रदान की गई कुछ मूल्यवर्धित सेवाएं निम्नवत हैं :-

- बुक अभी करें भुगतान बाद में (बीएनपीएल) सेवा;
- निःशुल्क पिक-अप;
- नोडल वितरण केन्द्र;
- स्पीड पोस्ट एकत्रीकरण केन्द्रों (एसपीपीसी) से बड़ी मात्रा में प्राप्त मदों का सीधे वितरण;

- परिमाण आधारित छूट दरें;
- विश्व में कहीं भी वितरण हेतु संविदात्मक सेवा।

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा

5.9 डाक विभाग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से 5 मार्च, 2001 को स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा प्रारम्भ की है। स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में स्थित स्पीड पोस्ट केन्द्रों में पासपोर्ट आवेदन पत्रों की प्राप्ति का विकेन्द्रीकरण करना है। स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा के अंतर्गत, विदेश मंत्रालय की तरफ से, चुनिंदा स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर पासपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। इस सेवा के दो मूल अंग हैं यानी (क) चुनिंदा स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर लिफाफों के साथ-साथ पासपोर्ट आवेदन पत्रों की बिक्री; (ख) भरे हुए पासपोर्ट आवेदन पत्रों को स्वीकार करना एवं आगे कार्रवाई हेतु उन्हें पासपोर्ट कार्यालयों को प्रेषित करना। इस सेवा के अंतर्गत, स्पीड पोस्ट केन्द्र पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करने वाले कार्यालयों के रूप में कार्य करते हैं अर्थात् ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हैं। कुल 213 डाकघरों/स्पीड पोस्ट केन्द्रों के साथ यह सेवा अब देश भर में उपलब्ध है और सेना डाक सेवा के अंतर्गत इसका डाकघरों तक भी विस्तार किया गया है।

व्यवसाय डाक

5.10 व्यवसाय डाक बड़ी मात्रा में ग्राहकों के लिए ग्राहकोनुकूल सेवाएं प्रदान करके कुल व्यवसाय समाधान प्रदान करती है। बड़ी मात्रा में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख शहरों में व्यवसाय डाक केन्द्र या वृहद मेलिंग केन्द्र स्थापित किये गए। इस सेवा के अंतर्गत, डाक द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार की पारंपरिक सेवाओं के साथ एकत्रण, इनसर्शन, पता लेखन, सीलिंग, फ्रैंकिंग इत्यादि के रूप में मूल्यवर्धन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष मूल्यवर्धन एवं पूर्व मेलिंग गतिविधि के रूप में मुद्रण को भी सूची में शामिल कर लिया गया। अधिकाधिक कारपोरेट ग्राहक व्यवसाय पोस्ट सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और मेट्रो शहरों एवं कस्बों में व्यवसाय मेल का बढ़ना निरंतर जारी है। वर्ष 2004-05 में व्यवसाय पोस्ट द्वारा अर्जित राजस्व 4,730.60 मिलियन रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत से भी अधिक है। व्यवसाय पोस्ट से अर्जित राजस्व स्पीड पोस्ट से अर्जित राजस्व से भी अधिक हो गया है।

5.6 Besides booking domestic and international documents and parcels, a bouquet of other services is offered under the brand Speed Post. These are Speed Post Passport Service, Speed Post Money-Orders and Speed Post Gift Service. During 2004-05, revenue generation from Speed Post has been Rs. 3,541.60 Million, representing a growth rate of about 19% over the previous year. Customer service and delivery efficiency is the focus in Speed Post. The highest revenue in Speed Post was generated by Maharashtra Circle. Under the Tenth Plan, 545 Speed Post Offices have been provided with computers till 2004-05.

Implementation of Online Track & Trace

5.7 Internet based Track and Trace System has been implemented for Speed Post and Express Parcel Post wherein a customer can find out the status of his consignment online through the Internet by logging on to the Department's website www.indiapost.gov.in. The facility has been operationalized in the National Speed Post Centres and in selected State Speed Post Centres. In the Tenth Five Year Plan, it is proposed to link all the State Speed Post Centres with the web-server for providing on-line track and trace service for all speed post articles. 257 Speed Post Centres have been provided computers for track and trace till 2004-05.

Value Additions under Speed Post

5.8 In order to increase revenue from corporate customers, Department has taken a number of steps to provide value additions and better quality of services to the customers. Some of the value added services provided to Corporate Customers are :-

- Book Now Pay Later (BNPL) facility;
- Free pick-up;
- Nodal Delivery Centres;
- Direct delivery of articles received in bulk from Speed Post Concentration Centre (SPCC);
- Volume based discounted rates;

- Contractual Service for delivery anywhere in the country.

Speed Post Passport Service

5.9 Department of Posts, in partnership with Ministry of External Affairs launched Speed Post Passport Service on 5th March 2001. The primary objective of Speed Post Passport Service is to decentralize the acceptance of passport application forms to Speed Post Centres across the country. Under the Speed Post Passport Service, Passport Application Forms are accepted at selected Speed Post Centres, on behalf of the Ministry of External Affairs. This service has two basic components i.e. (a) Sale of Passport Application Forms along with envelopes at selected Speed Post Centres; (b) Acceptance of filled-up Passport Application Forms and dispatch to Passport Offices, for further processing. Under this service, Speed Post Centres function as Passport Application Acceptance Offices thus providing convenience to the customers. The Service is available now across the country with total outlets of 213 Post Offices/Speed Post Centres, and has been extended to the Post Offices under the Army Postal Service.

Business Post

5.10 The Business Post offers total business solutions for the bulk users by providing customised services. Business Post Centres or Mass Mailing Centres were established in major cities to cater to the needs of Bulk Mailers. The service provides value addition to all traditional services offered by the Post in the form of collection, insertion, addressing, sealing, franking, etc. This year, printing as a value addition and a pre-mailing activity, was also added to the list. More and more corporate customers have been using Business Post Services and Business Mail continues to grow in the Metro Cities and Towns. In the year 2004-05, the revenue generated through Business Post is Rs. 4,730.60 Million, which is about 30% more than the previous year. The revenue from Business Post has surpassed the revenue generated from Speed Post also.

सीधी डाक

5.11 अनेक देशों ने सीधे डाक विपणन की अत्यधिक वृद्धि की संभावना वाले व्यवसाय मेल के एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में पहचान की है। उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ सीधी डाक के भारत में भी तीव्रता से बढ़ने की आशा है। बिना पता लिखी डाक के लक्षित जनता के दरवाजे पर वितरण के प्रयोजन से जून, 2005 में सीधी डाक नामक सेवा प्रारम्भ की गई।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

5.12 एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट के माध्यम से भूतल परिवहन द्वारा पार्सलों का एक्सप्रेस वितरण किया जाता है। वाणिज्यिक हित को देखते हुए उत्पाद को मार्च, 1999 में पुनः प्रारम्भ किया गया। इसमें 35 कि.ग्रा. तक वजन वाले पार्सलों की बुकिंग एवं प्रेषण किया जा सकता है। इस सेवा को कारपोरेट ग्राहकों को संविदात्मक आधार पर उपलब्ध करवाया गया है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की दरें अक्टूबर, 2004 में संशोधित की गई थीं। वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व बढ़कर 377.00 मिलियन रुपये हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि परिलक्षित करता है।

मीडिया पोस्ट

5.13 मीडिया पोस्ट के द्वारा कारपोरेट ग्राहकों/सरकारी संगठनों एवं अन्य बड़े निजी संस्थानों को अपने उत्पाद/सेवाओं को डाक स्टेशनरी, पत्र-पेटिकाओं आदि पर विज्ञापित करवाने का अवसर दिया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान मीडिया पोस्ट से अर्जित राजस्व 63.60 मिलियन रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.67 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

मेघदूत पोस्टकार्ड

5.14 मेघदूत नामक एक नये प्रकार का पोस्टकार्ड 2 सितम्बर, 2002 को प्रारम्भ किया गया। इस पोस्टकार्ड का मूल्य प्रति कार्ड 0.25 रुपये रखा गया है। इसमें पते वाली साइड में बायीं ओर आधे हिस्से में विज्ञापन मुद्रित होता है। यह विज्ञापन चार रंगों में हो सकता है। यह ग्रामीण विपणन के लिए आदर्श अवसर प्रदान करता है। विज्ञापन की दर दो रुपये प्रति पोस्टकार्ड है। अधिक मात्रा पर छूट भी उपलब्ध है। विभाग ने इस उत्पाद से वर्ष 2003-04 में 13.60 मिलियन रुपये और वर्ष 2004-05 में 15.97 मिलियन रुपये अर्जित किये हैं।

लॉजिस्टिक पोस्ट

5.15 लॉजिस्टिक पोस्ट नामक एक नई सेवा वर्ष 2004-05 में प्रारम्भ की गई। डाक विभाग के लिए इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेवा एवं व्यावसायिक अवसरों के बाजार अंश के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन किये जाने के बाद इस सेवा को प्रारम्भ किया गया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि लॉजिस्टिक सेवा का बाजार अंश 600,000 से 700,000 मिलियन रुपये प्रतिवर्ष के मध्य था; और डाक विभाग भारत में बढ़ते वाणिज्य के लिए एक विश्वसनीय सेवा उपलब्ध करवा सकता है और साथ ही इससे अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त कर सकता है।

ई-बिल पोस्ट

5.16 यह एक नई सेवा है जिसे विभाग ने ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी क्षमताओं के एक अंश के रूप में प्रारम्भ किया है। यह सेवा, फिलहाल, बंगलूर एवं कोलकाता में उपलब्ध है और अन्य शहरों में इसके शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की संभावना है। ग्राहकों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत इसे डिजाइन किया गया है। यह सेवा प्रयोक्ताओं द्वारा डाकघर काउंटर पर बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, पानी एवं अन्य प्रकार के बिलों/देयताओं के भुगतान करने के लिए उपयोगी है। प्रयोक्ता समीपस्थ डाकघर में जा सकता है और अपने उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकता है। विभाग भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) एवं अन्य ऑन लाइन व्यापारिक संगठनों के साथ परामर्श करके देश में ई-कॉमर्स के विकास हेतु इस सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाने का विचार रखता है।

ई-पोस्ट

5.17 डिजिटल अंतराल को भरने के लिए डाक विभाग द्वारा 30 जनवरी, 2004 को इस ई-क्षम सेवा को देश भर में प्रारम्भ किया गया। ई-पोस्ट में ई-मेल के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं जिन्हें प्रेषितियों के पत्तों के समीपस्थ डाकघरों में मुद्रित करके पत्रों के रूप में प्रेषितियों के पत्तों पर भेजा जाता है। इसी प्रकार से, लिखित में संदेश डाकघर में लाए जा सकते हैं जिनकी जांच की जाती है और उन्हें विश्व में किसी भी ई-मेल आईडी को या भारत में किसी भी पते पर ई-मेल के रूप में भेजा जा सकता है। डाकघर की पहुंच हर कहीं करने के दृष्टिगत इस सेवा को प्रारम्भ किया गया था। विभाग ने इसे सेवा का ऑन लाइन उपयोग करने के लिए पूर्व प्रदत्त (प्रीपेड) कार्ड जारी किये हैं। ई-पोस्ट सेवा के अंतर्गत प्रति प्रेषिति ए-4 आकार के संदेश के लिए 10 रुपये प्रति संदेश वसूल किये जाते हैं। वर्ष 2004-05 के

Direct Post

5.11 Many countries have identified Direct Mail Marketing as an important component of business mail with high potential for growth. With high economic growth, Direct Mail volumes are expected to grow significantly in India also. A service called 'Direct Post' was introduced in June, 2005 to deal with the delivery of unaddressed mail to the door-steps of the target population.

Express Parcel Post

5.12 Express Parcel Post provides express delivery of parcels through surface transportation. The product was re-launched in March 1999 with a commercial focus. It provides booking and dispatch of parcels weighing up to 35 Kgs. The service is provided to Corporate Customers on contractual basis. The rates of Express Parcel Post were revised in October 2004. During 2004-05, the revenue touched the figure of Rs. 377.00 Million, showing an increase of about 20% over the previous year.

Media Post

5.13 Media Post provides opportunities to corporate customers/Govt. organizations and other large private institutions to have their products/services advertised on the postal stationery, letter boxes, etc. During 2004-05, revenue from Media Post has been Rs. 63.60 Million, showing an increase of 10.67% over the previous year.

Meghdoot Post Card

5.14 A new kind of Postcard called Meghdoot Post Card was launched on September 2, 2002. This Postcard is priced at Rs. 0.25 each and carries an advertisement on the left half portion on the address side. The advertisement can be in four colours. It provides an ideal opportunity for rural marketing. The rate for advertisement is Rs. 2/- per post card. Volume discounts are also available. The Department has earned Rs. 13.60 Million in 2003-04 and Rs. 15.97 Million in 2004-05 from the product.

Logistics Post

5.15 A new service called "Logistics Post" was introduced in 2004-05. This service was introduced after a study was commissioned to evaluate the market size of Logistics Service and business possibilities for the Department of Posts in this area. The study concluded that the market size of Logistics Service was between Rs. 600,000 to 700,000 Million per annum; and the Department of Posts could provide a reliable service to growing commerce in India, as also earn additional revenue from a part of it.

e-Bill Post

5.16 This is a new service, which has been launched by the Department as one of the technology-enabled services for customers. Presently, this service is available at Bangalore and Kolkata and is likely to start in other cities very soon. This has been designed keeping in view the requirement of the clients. The service is useful for payment of electricity, telephone, mobile, water and other kinds of bills/dues at the Post Office Counter by the users. The user can go to a nearby Post Office and pay their utility bills. After interaction with the Confederation of Indian Industries (CII) and various online trading associations, the Department plans to utilize this software for the development of e-Commerce in the country.

e-Post

5.17 To bridge the digital divide, this e-enabled service was launched nation wide by Department of Posts on 30th January, 2004. The e-Post allows sending of messages through e-mail to be printed in Post Offices nearest to the addressees and to be delivered to them at their postal addresses as letters. Similarly, written message can be brought to a Post Office, which will be scan and send them as e-mail to any e-mail ID in the world or to a postal address in India. This service has been introduced keeping in view the last mile advantage of the Post Office. The Department has issued pre-paid cards to use this Service online. The charges for e-post services are Rs. 10/- per message of A-4 size per addressee. Rs. 3.04 Million were generated as revenue during the year 2004-05. The Corporate world has found

दौरान इस सेवा से राजस्व के रूप में 3.04 मिलियन रुपये अर्जित किये गए। कारपोरेट जगत ने बिल, स्टेटमेंट, नोटिस आदि जारी करने के लिए ई-पोस्ट को एक तीव्र एवं मितव्ययी सेवा के रूप में पाया है। ई-पोस्ट के कारपोरेट रूप, जिसे कारपोरेट ई-पोस्ट कहा जाएगा, को कार्यालय में एक पी सी से 9999 पत्तों पर एकसाथ ई-पोस्ट संदेश भेजने के लिए शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

रिटेल पोस्ट

5.18 भारतीय डाक, सरकारी एवं निजी संगठनों के लिए, रिटेल पोस्ट की मार्फत, देशभर में फैले अपने 1,55,000 से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क के द्वारा, टेलीफोन/बिजली/मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं आदि जैसे सेवा उद्योगों के लिए ग्राहक बिल वसूलने की सुविधा प्रदान करता है। डाकघर अपने काउंटरों पर सार्वजनिक निकायों के प्रपत्र भी बेचते हैं। इसके अलावा, सैलुलर कंपनियां भी कैश कार्ड एवं रिचार्ज कूपन आदि बेचने के लिए डाकघर केन्द्रों का उपयोग करती हैं। इस उत्पाद में वर्ष 2004-05 के दौरान 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बिल मेल सेवा

5.19 इस सेवा को वित्तीय विवरण, बिल, मासिक खाता बिल या इसी प्रकार की अन्य मदों, जिन्हें सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों को प्रेषित किया जाना है, के रूप में संचार की बुकिंग के लिए, 15 सितंबर, 2003 को, देश भर में प्रारम्भ किया गया। यह सेवा मदों के स्थानीय या जिले के भीतर, नियमित आधार पर, वितरण के लिए है। इस सेवा के लिए निर्धारित

अवधि 45 दिन है। बिल मेल सेवा हेतु प्रथम 20 ग्राम के लिए प्रभार 3 रुपये और अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके अंश के लिए प्रभार 1.60 रुपये होगा। इस सेवा से वर्ष 2004-05 के दौरान 193.50 मिलियन रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इस वर्ष एक राष्ट्रीय बिल मेल सेवा प्रारम्भ की गई थी जिसमें इस सेवा को, समूचे भारत वर्ष में बिल वितरण हेतु, स्पीड पोस्ट, ईपीएफ आदि जैसी अन्य सेवाओं के साथ पैकेज रूप में प्रस्तुत किया गया है।

व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय की नवीन पहल

- भारत के चुनाव आयोग के लिए देश भर में फैले डाकघरों के द्वारा मतदाता सूचियों में सुधार का कार्य किया गया।
- स्पीड पोस्ट द्वारा जाने वाले पार्सलों के भार को भारतीय वायु सेना, जिसके साथ स्पीड पोस्ट पार्सलों के रूप में स्पेयर पार्ट ले जाने के लिए विभाग का करार है, के पार्सलों के लिए वर्तमान 35 कि.ग्रा. से बढ़ाकर 50 कि.ग्रा. कर दिया गया।
- भारत के महापंजीयक के लिए सभी बड़े आकार के गांवों का ढाँचागत सर्वेक्षण किया गया।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्डों के प्रेषण के लिए उनके साथ किये गए करार को एक और वर्ष के लिए नवीकृत किया गया। इस राष्ट्रीय खाते से वर्ष 2004-05 के दौरान 180 मिलियन रुपये से भी अधिक का राजस्व सृजित हुआ।

e-Post to be a quick and inexpensive means of issuing bills, statements, notices, etc. A corporate version of e-Post, to be called Corporate e-Post, would be launched soon to enable sending of e-Post messages from a PC in the office to up to 9999 addresses simultaneously.

Retail Post

5.18 Through its vast network of more than 1,55,000 Post Offices across the country, India Post offers the facility to collect consumers' bills for service industries like telephone/electricity/mobile phone users, etc. for Govt. and private organizations through Retail Post. Post Offices also sell forms for public bodies over the counter of Post Offices. Besides this, Cellular companies also use Post Office outlets to sale cash cards and recharge coupons. The product registered a growth of 50% during 2004-05.

Bill Mail Service

5.19 This service was launched nationwide on 15th September, 2003 for booking of communications in the nature of financial statement, bill, monthly account bills or other such items of similar nature, which may be posted by service providers to their customers. The service is meant for the articles to be delivered locally or within a district on regular basis. The periodicity prescribed for the service is 45 days. The charges for Bill Mail Service are Rs. 3/- for first 20 gms. and Rs. 1.60 for additional

20 gms. or part thereof. This Service generated revenue of Rs. 193.50 Million in 2004-05. A National Bill Mail Service was launched this year, where the service was packaged with other services like Speed Post, EPP, etc. to deliver bills all over India.

New initiatives of Business Development and Marketing Directorate

- The work of correction of Electoral Rolls was taken up by the Post Offices across the country for the Election Commission of India.
- The weight of parcels carried by Speed Post was increased from the present 35 Kgs. to 50 Kgs. for parcels of Indian Air Force with whom the Department has a contract to carry spare parts as Speed Post Parcels.
- Infrastructure survey of all large sized villages was carried out for the Registrar General of India.
- The contract with the State Bank of India for dispatch of their debit cards was renewed for another year. This National Account has generated revenue of more than Rs. 180 Million in the year 2004-05.

अध्याय 6

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

6.1 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की 23वीं कांग्रेस 15 सितंबर से 05 अक्टूबर, 2004 तक बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित की गई। श्री दयानिधि मारन, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के दौरान भारत को डाक प्रचालन परिषद में पुनः चुना गया। 40 सदस्यीय डाक प्रचालन परिषद (पीओसी) अपने सदस्य डाक प्रशासनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालनों के महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक, वाणिज्यिक, आर्थिक तथा तकनीकी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। भारत को डाक प्रचालन परिषद की समिति 3 के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया। समिति प्रचालनात्मक मुद्दों से वास्ता रखती है। भारत को टर्मिनल शुल्क परियोजना दल के नीतिगत प्रश्न कार्यदल के सह-अध्यक्ष के तौर पर भी नामित किया गया। यह परिषद के कार्यकरण एवं सतत विकास परियोजना दल का भी सदस्य बना।

भारतीय डाक-सेवा गुणवत्ता निधि न्यासी बोर्ड का सदस्य

6.2 सचिव, डाक विभाग ने यू पी यू की सेवा गुणवत्ता निधि (क्यू एस एफ) के न्यासी बोर्ड की बैठक में भारतीय डाक का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक लिस्बन, पुर्तगाल में 27 से 28 अप्रैल, 2004 तक आयोजित हुई। यू पी यू द्वारा स्थापित सेवा गुणवत्ता निधि का उद्देश्य विकासशील देशों में सेवा की गुणवत्ता में बेहतरी लाने के लिए अभिकल्पित परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने हेतु निधियों को औद्योगिकीकृत देशों से लेकर विकासशील देशों को देना है। न्यासी बोर्ड में भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के नौ निर्वाचित सदस्य होते हैं जो क्यू एस एफ के कार्य की देखरेख करते हैं। भारत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य है। भारतीय डाक के लिए इस बैठक का विशेष महत्व था क्योंकि सचिव (डाक) वर्ष जुलाई, 2004-जून, 2005 के लिए न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किए गए थे। बोर्ड की 05-08

जुलाई, 2004 तक वाशिंगटन, यूएसए में बैठकें आयोजित की गईं तथा जनवरी, 2005 में डाक प्रचालन परिषद सत्र के दौरान सचिव (डाक) द्वारा अध्यक्षता की गई। अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने कांग्रेस में क्यूएसएफ के न्यासी बोर्ड की रिपोर्ट को पेश किया। एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सचिव(डाक) और उपमहानिदेशक (आईआर) सम्मिलित थे, ने बर्न में 17 से 28 जनवरी, 2005 तक आयोजित डाक प्रचालन परिषद के वार्षिक सत्र में भी भाग लिया। परिषद में पत्र डाक विनियमों और पार्सल डाक विनियमों के मानकों और प्रक्रियाओं से संबंधित कई प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। सचिव, डाक ने प्रचालनात्मक मुद्दों पर डाक प्रचालन परिषद की समिति 3 की बैठकों के साथ-साथ गुणवत्ता सेवा निधि के न्यासी बोर्ड की बैठकों की भी अध्यक्षता की।

6.3 उपमहानिदेशक (आई आर) ने डाक प्रचालन परिषद के टर्मिनल शुल्क परियोजना दल की रबात, मोरक्को में 10 और 11 मार्च, 2005 को आयोजित हुई बैठक में भाग लिया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत परियोजना दल में नीतिगत प्रश्नों पर कार्यदल 13 का सह-अध्यक्ष है। वर्ष 2005 से 2008 तक की अवधि की कार्य-योजना को वैध ठहराना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था।

एशिया प्रशांत डाक यूनियन (एपीपीयू)

6.4 भारत एशिया प्रशांत डाक संघ के कामकाज में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 29 देशों का सीमित संघ है। एपीपीयू कांग्रेस संघ का सर्वोच्च निकाय है और इसकी पांच वर्षों में एक बार बैठक होती है। कार्यकारी परिषद (ई सी) की सिद्धांत रूप में वर्ष में एक बार बैठक होती है और यह दो कांग्रेसों के बीच संघ के कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करती है। एपीपीयू- ईसी-1 शासी बोर्ड की बैठक 09 से 14 मई, 2004 तक क्वीन्सटाउन, न्यूजीलैण्ड में आयोजित की गई। सचिव (डाक) और उपमहानिदेशक (आई आर) ने बैठक में भारतीय डाक का प्रतिनिधित्व किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र से संदर्भित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और मुद्दों जैसे टर्मिनल शुल्क, तकनीकी सदस्यता, डाक वित्तीय सेवाएं आदि पर विचार-विमर्श किया गया।



Chapter 6

INTERNATIONAL RELATIONS

Universal Postal Union

6.1 The 23rd Congress of the Universal Postal Union (UPU) was held at Bucharest, Romania from 15th September to 05th October, 2004. A high level Indian delegation led by Shri Dayanidhi Maran, Hon'ble Minister of Communications and IT represented India at the Congress. During the Congress, India was re-elected to the Postal Operations Council. The 40-Member Postal Operations Council (POC) is responsible for important operational, commercial, economic and technical aspects of international postal operations among member postal administrations. India was nominated as Chairman of Committee 3 of Postal Operations Council, which deals with operational issues. India was also nominated as Co-Chair of the Policy Questions Working Group of the Terminal Dues Project Team. It also became a member of Environment and Sustainable Development Project Group of the Council.

India Post – a Member of Quality of Service Fund Board of Trustees

6.2 Secretary, Department of Posts represented India Post in the meeting of Board of Trustees of Quality of Service Fund (QSF) of the UPU held in Lisbon, Portugal from 27th to 28th April, 2004. The Quality of Service Fund established by UPU seeks to channelise funds from the industrialized countries to the developing countries for financing projects designed to improve the quality of service in the developing countries. The Board of Trustees, comprising nine elected members from different geographical regions, manages the work of QSF. India is an elected member of the Board. This meeting was specially important for India Post as Secretary (Posts) was elected Chairman of the Board of Trustees for the year July, 2004 – June, 2005. The meetings of the Board held in Washington, USA from 05th – 08th July, 2004 and

during the POC Session in January, 2005 were chaired by Secretary (Posts). In the capacity of Chairman, India presented the report of the Board of Trustees of the QSF at the Congress. A two member delegation comprising Secretary (Posts) and Deputy Director General (IR) also attended the annual session of the POC held in Berne from 17th to 28th January, 2005. The Council considered many proposals relating to standards and procedures of the Letter Post Regulations and the Parcel Post Regulations. Secretary (Posts) chaired the meetings of Committee 3 of the POC on Operational Issues as also the meeting of the Board of Trustees of the Quality of Service Fund.

6.3 Deputy Director General (IR) attended the meeting of the Terminal Dues Project Group of the Postal Operations Council (POC) held in Rabat, Morocco on 10th and 11th March, 2005 as India, along with Great Britain is a Co-Chairman of the Working Group 13 on Policy Questions within the Project Group. This meeting was mainly aimed at validation of the action programme during the period from 2005 to 2008.

Asia Pacific Postal Union (APPU)

6.4 India plays a significant role in the affairs of the Asia Pacific Postal Union (APPU), a Restricted Union comprising 29 countries of the Asia-Pacific Region. The APPU Congress is the supreme organ of the Union and meets every five years. The Executive Council (EC) meets once in a year, in principle, and ensures the continuity of the work of the Union between Congresses. The APPU-EC/Governing Board meeting was held from 09th to 14th May, 2004 in Queenstown, New Zealand. Secretary (Posts) and Deputy Director General (IR) represented India Post in the meeting. Several important proposals and issues in the context of the Asian Pacific Region such as Terminal Dues, Technical Assistance, Postal Financial Services, etc., were discussed.

एशिया प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड

6.5 भारतीय डाक एशिया प्रशांत डाक सहयोग के सात सदस्यीय सहयोग प्रबंधन बोर्ड (एपीपी-सीएमबी) का सदस्य भी है। एपीपी-सीएमबी एशिया प्रशांत डाक सहयोग (कोआपरेटिव) के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए बनाई गई है। भारत बोर्ड सदस्य की अपनी हैसियत से कोआपरेटिव के कामकाज की देखरेख करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सिंगापुर में 19 नवंबर, 2004 को आयोजित हुई इसकी बैठक में सहायक महानिदेशक (आई आर) ने भारतीय डाक का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान यूपीयू बुखारेस्ट कांग्रेस में उत्पन्न हुए क्षेत्रीय डाक मुद्दों, एपीपी 2004-05 की प्रगति, बिजनेस प्लान कार्यकलापों और वर्ष 2004-05 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सहयोग केन्द्र (आरएससीएपी) की गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया गया। सहायक महानिदेशक (आई आर) ने एशिया प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड (एपीपी-सीएमबी) की सिडनी, आस्ट्रेलिया में 17 और 18 मार्च, 2005 को आयोजित हुई बैठक में भी भाग लिया। बैठक में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें एपीपी/एपीपीयू विलयन प्रस्ताव, एपीपी बिजनेस प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट, एपीपी 2005 बिजनेस प्लान का प्रतिपादन, कोआपरेटिव के भविष्य और आगामी एपीपीयू कांग्रेस की तैयारी करना शामिल थे।

परियोजनाएं

6.6 डाक विभाग ने बंगलादेश, म्यांमार और नेपाल में जनरल डाकघरों के डाकघर काउंटर्स का कम्प्यूटरीकरण करने की परियोजनाएं अपने हाथ में ली हैं। इसके लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। कम्प्यूटरीकरण और साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को मान्यता देते हुए यूपीयू भारतीय डाक के माध्यम से इन कार्यकलापों को पूरे करवा रहा है। यूपीयू की ओर से हाथ में ली गई अन्य परियोजनाओं में कम्बोडिया के लिए कन्सल्टेंसी मिशन सम्मिलित थी। तंजानिया और बहामास में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करने के लिए भी एक कन्सल्टेंट भेजा गया था।

सार्क पत्र लेखन प्रतियोगिता

6.7 पाकिस्तान डाक द्वारा 26 सितंबर, 2004 को 19वीं सार्क पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केरल सर्किल के एर्नाकुलम (जिला) की सुश्री अस्वाति गोपालकृष्णन ने

सार्क प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय डाक ने सुश्री अस्वाति गोपालकृष्णन की प्रविष्टि को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ठहराया था तथा प्रविष्टि प्रतियोगिता की आयोजक पाकिस्तान डाक को अग्रेषित की गई थी।

प्रतिनिधिमंडल

6.8 तंजानिया डाक निगम के एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने काउंटर स्वचालन साफ्टवेयर तथा भारतीय डाक द्वारा विकसित अन्य साफ्टवेयरों से अवगत होने के लिए 24 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2004 तक भारत का दौरा किया। इस टीम ने न केवल काउंटर स्वचालन साफ्टवेयर में वरन मेघदूत साफ्टवेयर के अन्य माड्यूलों के साथ-साथ ई-पोस्ट और वी-सेट मनीआर्डर सिस्टम में गहरी रुचि दिखलाई। इस प्रतिनिधिमंडल ने दो देशों के बीच आपसी सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु भारतीय डाक के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रतिभागिता

6.9 इस अवधि के दौरान उपमहानिदेशक (सीपी) और सहायक महानिदेशक (आईआर) ने एशिया प्रशांत रीजन में महानिदेशकों तथा वरिष्ठ डाक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण गठजोड़ पर बैंकाक में 08 से 10 जून, 2004 तक आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया जिसकी मेजबानी ला पोस्ट, फ्रांस ने की थी। विनियामक और प्रचालक की भूमिकाओं, संरचना, विश्व सेवा दायित्व आदि के सहित डाक सुधारों के माडलों पर विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और व्यापार एवं सेवाओं पर सामान्य करार (गैट्स) से संबंधित मुद्दों पर एक सत्र आयोजित किया गया।

6.10 डा. उ. श्रीनिवासराघवन, तत्कालीन सदस्य, डाक सेवा बोर्ड ने एशिया प्रशांत डाक कालेज, बैंकाक में 09 से 11 फरवरी, 2005 तक आयोजित डाक वित्तीय सेवाएं कार्यशाला में भाग लिया। डाक वित्तीय सेवाओं के विकास पर 23वीं यूपीयू कांग्रेस द्वारा पारित संकल्प के आधार पर यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन और जापान डाक द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। एशिया और प्रशांत रीजन में डाक प्रशासनों को डाक वित्तीय सेवाओं में सुधार लाने के लिए संभव क्षेत्रीय कार्यवाहियों का अवसर प्रदान करना कार्यशाला का उद्देश्य था।

Asia-Pacific Post Co-operative Management Board

6.5 India Post is also a member of the seven-member Co-operative Management Board of Asia Pacific Post Co-operative (APP – CMB). The APP – CMB is the body designated to supervise the activities of the Asia Pacific Post Co-operative. India has been playing an active role in its capacity as a Board Member in managing the affairs of the Co-operative. In its meeting held at Singapore on 19th November, 2004, Assistant Director General (IR) represented India Post. During the meeting regional postal issues arising from the UPU Bucharest Congress, progress on the APP 2004-05, Business Plan activities and Regional Support Centre for Asia Pacific (RSCAP) activities for 2004-05 were discussed. Assistant Director General (IR) also attended the Asia Pacific Post Co-operative Management Board (APP – CMB) meeting held on 17th and 18th March, 2005 in Sydney, Australia. The issues discussed in the meeting included APP/APPU Merger Proposal, APP Business Plan Progress Report, formulation of APP 2005 Business Plan, future of the Co-operative, and preparations for the forthcoming APPU Congress.

Projects

6.6 The Department of Posts has undertaken projects for computerizing Post Office Counters at General Post Offices in Bangladesh, Myanmar and Nepal with funds being provided by the Universal Postal Union. These activities are being taken up by the UPU through India Post in recognition of our capabilities in the area of computerization and software development. Other projects taken up on behalf of UPU were a consultancy mission to Cambodia. A consultant was also sent for holding a training workshop in Tanzania and Bahamas.

SAARC Letter Writing Competition

6.7 The 19th SAARC Letter Writing Competition was organized by Pakistan Post on 26th September, 2004. Miss Aswathy Gopalakrishnan of Ernakulam (District) in Kerala Circle stood first in the SAARC Competition.

The entry of Miss Aswathy Gopalakrishnan was adjudged best at the National level by India Post and was forwarded to Pakistan Post, the organiser of the competition.

Delegations

6.8 A four-member delegation from Tanzania Posts Corporation visited India from 24th October to 2nd November, 2004, to familiarize themselves with the software of counter automation and other software developed by India Post. The team evinced keen interest in not only the counter automation software but other modules of Meghdoot Software as well as e-Post and the V-SAT Money Order System. The delegation also met Senior Officers of India Post to discuss matters of mutual co-operation between the two countries.

Participation in International Meetings

6.9 During the period, Deputy Director General (CP) and Assistant Director General (IR) attended a Seminar on Strategic Alliances for Directors General and Senior Postal Management in Asia Pacific Region held at Bangkok from 08th to 10th June, 2004, which was hosted by La Poste, France. Apart from discussions on models for postal reforms including regulation and operator roles, structure, Universal Service Obligation (USO), etc., there was a session on issues concerning World Trade Organisation (WTO) and General Agreement on Trade and Services (GATS)

6.10 Dr. U. Srinivasa Raghavan, the then Member, Postal Services Board participated in the Postal Financial Services Workshop held at Asian Pacific Postal College, Bangkok from 09th to 11th February, 2005. The Workshop was organized by Universal Postal Union (UPU) and Japan Post on the basis of a Resolution passed by the 23rd UPU Congress on the development of Postal Financial Services. The objective of the workshop was to provide postal administrations the opportunity to discuss possible regional actions to improve postal financial services in the Asia and Pacific Region.

6.11 सचिव (डाक) और उपमहानिदेशक (आईआर) ने भूटान के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को सहयोग देने, मेघदूत साफ्टवेयर को अद्यतन करने से संबंधित मुद्दों तथा परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 08 से 11 नवंबर, 2004 तक भूटान का दौरा किया। इन मुद्दों पर आगे और विचार-विमर्श करने हेतु एक भूटानी प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अध्यक्षता वहां के प्रबंध निदेशक कर रहे थे, ने भी 27 से 31 मार्च, 2005 तक भारत का दौरा किया।

अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली (आईपीएस) को अद्यतन करना

6.12 अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट संकेन्द्रण केन्द्रों तथा विनिमय कार्यालयों में स्थापित की गई है। आईपीएस के लिए साफ्टवेयर और नेटवर्क समर्थन यूपीयू के डाक प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा दिया जाता है तथा प्रणाली को निरंतर अद्यतन किया जाता है। भारतीय डाक ने इस वर्ष चार स्थानों में आईपीएस का रूप (वर्सन) 4.21 संस्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, आईपीएस एकाउंट माड्यूल और वेब ग्राहक माड्यूल को सम्मिलित करने के लिए हम आईपीएस प्रणाली के स्तरोन्नयन पर काम कर रहे हैं ताकि यह इंटरनेट के अनुकूल बन सके। इसके ग्राहक इंटरनेट के जरिए सिस्टम पर लॉग ऑन कर पाएंगे तथा ट्रेक एवं ट्रेस सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस के लिए वितरण मानकों का मान्यकरण

6.13 यूपीयू की ईएमएस इकाई प्रत्येक देश में ईएमएस यूनिट के वितरण मानकों का मान्यकरण करती है। भारत में

आवक ईएमएस के वितरण के लिए वितरण मानदंड तैयार कर लिए गए हैं। ईएमएस इकाई द्वारा इसका मान्यकरण भी कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय लेखादेय वस्तुओं के लिए बार कोडों को प्रयोग में लाना

6.14 बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित 23वीं यूपीयू कांग्रेस 2004 ने पार्सल वितरण अदायगियों के लिए एक पृथक वितरण प्रणाली को शुरू किया है। अतिरिक्त सेवा विशिष्टताओं के आधार पर कुछ निश्चित प्रोत्साहन-राशि/बोनस की अदायगियां शुरू की गई हैं। बोनस भुगतान का दावा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पार्सलों पर बार कोडों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। भारतीय डाक ने भारत से उद्भूत सभी लेखा देय अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं पर बार कोड चिपकाने की प्रणाली शुरू की है। इससे आंकड़ों तथा डाक वस्तुओं के ट्रैक एवं ट्रेस का त्वरित समावेशन होने की उम्मीद की जाती है।

विदेश डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

6.15 विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालनों की क्वालिटी में सुधार लाने तथा बेहतर ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए विनिमय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने की परियोजना हाथ में ली है। पांच उप-विदेश डाकघर (श्रीनगर, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलूर तथा कोच्चि) तथा दो विदेश डाकघर (नई दिल्ली और मुंबई) कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। कोलकाता और चेन्नई स्थित अन्य दो विदेश डाक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का काम चल रहा है।

6.11 Secretary (Posts) and Deputy Director General (IR) visited Bhutan from 08th to 11th November, 2004 to discuss issues relating to support to Bhutan's HRD programme, updation of the Meghdoot Software and other matters of mutual interest. A Bhutanese delegation, led by their Managing Director also visited India from 27th to 31st March, 2005 for further discussions on these issues.

Updation of International Postal System (IPS)

6.12 The International Postal System (IPS) is installed at the four international Speed Post Concentration Centres and Offices of Exchange at New Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. The software and network support for the IPS is provided by the Postal Technology Centre of the UPU and the system is continuously updated. This year, India Post has installed Version 4.21 of the IPS at the four sites. In addition, we are working on upgrading the IPS System to include the IPS Accounts Module, Web Module and Web Client Module to make it compatible with the internet. This would enable the customer to log on into the system through Internet and access track and trace services.

Validation of Delivery Standards for International EMS

6.13 The EMS Unit of the UPU validates delivery standards of EMS in each country. The periodical report cards generated by the UPU on the basis of the

Electronic Data Interchange (EDI) are measured against the delivery standards. The delivery standards for delivery of Inward EMS in India have been prepared. The same have been validated by the EMS Unit.

Introduction of Bar Codes for International Accountable Items

6.14 The 23rd UPU Congress 2004 held at Bucharest, Romania has introduced a different system for parcel delivery payments. Certain incentives/bonus payments have been introduced based on additional service features. Use of bar codes on international parcels is mandatory to claim the bonus payment. India Post has introduced the system of affixing bar codes to all accountable international mail items originating from India. It is expected to enable faster assimilation of data and track and trace of postal articles.

Computerization of Foreign Post Offices

6.15 The Department has undertaken a project to computerize the Offices of Exchange in order to improve the quality of International Mail Operations and ensure better customer satisfaction. Five Sub-Foreign Post Offices (Srinagar, Jaipur, Ahmedabad, Bangalore and Kochi) and two Foreign Post Offices (New Delhi and Mumbai) have been computerized. The computerization of the other two Foreign Post Offices at Kolkata and Chennai is underway.

अध्याय 7

प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

7.1 योजना आयोग ने अप्रैल, 2001 में डाक क्षेत्र पर एक कार्यदल का गठन किया है जिसमें डाक विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग, दूरसंचार विभाग, एन आई आर डी, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि हैं। इसका कार्य दसवीं योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय डाक सेवा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए संगत सिफारिशें देना था। कार्यदल ने वर्ष 2001 तक कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का अध्ययन किया और सिफारिश की, कि पहले शुरू की गई कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए और दसवीं योजना के दौरान सभी प्रधान डाकघरों और महत्वपूर्ण विभागीय उपडाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करना चाहिए। कार्यदल ने विभाग के लिए अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने हेतु नई सेवाओं/उत्पादों को शुरू करने का भी सुझाव दिया।

10वीं पंचवर्षीय योजना में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग

7.2 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति ने जनवरी, 2004 में डाकघरों, प्रशासनिक एवं लेखा कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना अनुमोदित की। यह एक वृहत् योजना स्कीम है जिसका परिचय 8362.7 मिलियन रुपये है। इसका उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता में दक्षता और वास्तविक समय आधार पर सुधार लाना है।

7.3 विभाग का लक्ष्य दसवीं योजना के दौरान 839 प्रधान डाकघरों, 6861 बड़े उपडाकघरों, 22 डाक लेखा कार्यालयों तथा 264 प्रशासनिक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत और नेटवर्क करने का लक्ष्य था। विभाग 2004-05 के दौरान 839 प्रधान डाकघरों और 1533 उपडाकघरों को कम्प्यूटरीकृत कर सका है। वित्त

मंत्रालय से विशेष अनुमति प्राप्त करके विभाग ने 2005-06 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2860 और उप डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए 2004-05 में कम्प्यूटर तथा हार्डवेयर की प्राप्ति के लिए आर्डर दिए। विभाग दसवीं योजना की बाकी बची अवधि में दसवीं योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शेष उप डाकघरों को भी कम्प्यूटरीकृत कर देगा। विभाग इस योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करके भी डाकघरों की नेटवर्किंग करने के लिए कार्य कर रहा है।

वीएसएटी नेटवर्क के माध्यम से मनीआर्डर पारेषण

7.4 मनीआर्डरों के पारेषण के लिए प्रेषण समय को कम करने के प्रयास में भारतीय डाक ने नौवीं योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान देशभर में 150 टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (टी डी एम ए) हाई स्पीड वीएसएटी सैटेलाइट मनीआर्डर (एस एम ओ) स्टेशनों की स्थापना की है। ये 150 एस एम ओ केन्द्र 1486 विस्तारित सैटेलाइट मनीआर्डर (ई एस एम ओ) स्टेशनों के साथ डायल-अप कनेक्शन से जुड़े हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान इस वी-सैट नेटवर्क के माध्यम से 15.10 मिलियन मनीआर्डर पारेषित किए गए। डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर में स्थित साफ्टवेयर विकास केन्द्र ने मनीआर्डरों के पारेषण के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर विकसित किया है।

स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केन्द्र

7.5 वर्तमान में मुंबई और चेन्नई में दो स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केन्द्र (ए एम पी सी) कार्य कर रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजनागत कार्यकलापों के रूप में भारतीय डाक ने दिल्ली और कोलकाता में दो और स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों (ए एम पी सी) की स्थापना के लिए कार्रवाई की जिसका परिचय 710.50 मिलियन रुपये है और यह कार्य 2006-07 में पूरा हो जाएगा। डाक छंटाई प्रक्रिया में स्वचालन के परिणामस्वरूप पारेषण और डाक का वितरण अधिक तीव्रता से हो सकेगा।

Chapter 7

TECHNOLOGY

Introduction

7.1 The Planning Commission had constituted a Working Group on Postal Sector comprising representatives from Department of Posts, Delhi University, Indian Institute of Technology, New Delhi, Indian Institute of Management, Ahmedabad, Department of Information Technology, Planning Commission, Department of Telecom, NIRD, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Rural Development, etc., in April, 2001 to recommend for modernization of the postal sector relevant to formulate the Tenth Plan proposal. The Working Group studied the computerization initiatives carried up to the year 2001 and recommended that the process of computerization initiated earlier should be continued and all the Head Post Offices and important Departmental Sub Post Offices should be computerized during the Tenth Plan. The Working Group also suggested introducing new services/products for generating additional resources for the Department.

Computerization and Networking of Post Offices in 10th Five Year Plan

7.2 For the 10th Five Year Plan (2002-07), the Cabinet Committee on Economic Affairs approved an ambitious project for computerization and networking of Post Offices, Administrative and Account Offices, in January, 2004. This is a major Plan Scheme and has an outlay of Rs. 8,362.7 Million. The objective is to improve quality of service in an efficient and real time basis.

7.3 The Department has the target to computerize and network 839 Head Post Offices, 6,861 large Sub-Post Offices, 22 Postal Accounts Offices and 264 Administrative Offices during the Tenth Plan. The Department has been able to computerize 839 Head Post Offices and 1,533 Sub-Post Offices during 2004-05. By

obtaining special permission from the Ministry of Finance, the Department has also placed orders for computers and hardware in 2004-05 to computerize 2,860 more Sub-Post Offices against the target of 2005-06. The Department will computerize the remaining Sub-Post Offices as targeted in the Tenth Plan during the remaining period of Tenth Plan. The Department is also working towards networking of Post Offices by setting up a National Data Centre in National Informatics Centre during this plan period.

Money Order transmission through VSAT Network

7.4 India Post, in its endeavour to reduce the transit time for transmission of Money Orders, set up a network of 150 Time Division Multiple Access (TDMA) High Speed VSAT Satellite Money Order (SMO) stations across the country during the Ninth Five Year Plan. These 150 SMO Centres are in turn connected to 1,486 Extended Satellite Money Order (ESMO) Stations over dial-up connection. 15.10 Million Money Orders were transmitted through this VSAT network during 2004-05. The Software Development Centre located in Postal Training Centre, Mysore, developed the application software for transmission of Money Orders.

Automated Mail Processing Centres

7.5 At present two Automated Mail Processing Centres (AMPCs) are functioning at Mumbai and Chennai. As a part of the Plan activities approved by the Planning Commission for the Tenth Five Year Plan, the India Post has initiated action for setting up of two more Automatic Mail Processing Centres (AMPCs) at Delhi and Kolkata with an outlay of Rs. 710.50 Million to be completed by 2006-07. Automation in mail sorting process will result faster transmission and delivery of mails.

डाकघरों का आधुनिकीकरण

7.6 डाकघरों के आधुनिकीकरण की योजना स्कीम के अंतर्गत भारतीय डाक ने डाकघरों की प्रचालन व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करने, कार्यात्मक दक्षता में सुधार लाने और ग्राहकों को बेहतर वातावरण देने की योजना बनाई है। दसवीं योजनावधि

में 1500 डाकघरों के 'कार्य-वातावरण में सुधार' और 1600 डाकघरों को 'नए यांत्रिकी उपस्करों की आपूर्ति' करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2004-05 तक योजना कार्यकलाप- 'कार्य-वातावरण में सुधार' के अंतर्गत 342 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया और 858 डाकघरों को 'नए यांत्रिकी उपस्करों' की आपूर्ति की गई।



Modernisation of Post Offices

7.6 Under the Plan Scheme of Modernisation of Post Offices, India Post planned to make a qualitative change in the operative systems of the Post Offices, to improve the functional efficiency and to provide a better environment for the customers. A target was laid down

for “Improving Ergonomics” for 1,500 Post Offices and for “Supply of new Mechanical Equipments” to 1,600 Post Offices during the Tenth Plan period. Till 2004-05, under the Plan activity – “Improving Ergonomics”, 342 Post Offices have been modernized and further 858 Post Offices have been supplied with new “Mechanical Equipments”.

अध्याय 8

वित्तीय सेवाएं

8.1 डाकघर बचत बैंक देश के सबसे पुराने एवं सबसे बड़े बैंकिंग संस्थानों में से है। यह लगभग 140 मिलियन बचत खातों का प्रचालन करता है। डाकघर बचत बैंक योजना एक एजेंसी कार्य है जो डाक विभाग द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से निष्पादित किया जाता है। डाकघर बचत बैंक 1,54,000 डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से समूचे देश के लोगों को आठ स्कीमों में अपनी बचत-राशि जमा करने का अवसर प्रदान करता है। इसकी पहुंच और सेवा की देश की किसी भी अन्य बैंकिंग एजेंसी से तुलना नहीं की जा सकती। वित्त मंत्रालय इस एजेंसी कार्य के लिए डाक विभाग को समय-समय पर नियत दर से पारिश्रमिक देता है। वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने बचत बैंक कार्य के लिए, पारिश्रमिक के रूप में लगभग 20,300 मिलियन रुपये अर्जित किये।

8.2 डाकघर बचत बैंक की ग्राहक संख्या 140 मिलियन है

तथा वार्षिक जमा राशि 10,00,000 मिलियन रु. से अधिक है। बचत बैंक सुविधा 1,54,000 डाकघरों के नेटवर्क की मार्फत उपलब्ध करवाई जाती है जो देश में सभी बैंकिंग इकाइयों को मिलाने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या से भी दुगुनी है। आठ सेवाओं को देशभर में डाकघरों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ये बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय स्कीम, लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र एवं वरिष्ठ नागरिक स्कीम है। डाकघरों में सभी राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अंतर्गत बकाया शेष 3,750,000 मिलियन रुपये है। वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम बुजुर्ग लोगों को राहत प्रदान करने और निवेश एवं प्रतिलाभ का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 02 अगस्त, 2004 से लागू की गई है। इसमें 9% की विशेष दर से ब्याज दिया जाता है। सात बचत योजनाओं के विवरण तालिका 4 में दिए गए हैं:-

तालिका 4 बचत योजना: विवरण (31.3.2005 को)		
स्कीम का नाम	खातों की संख्या	जमा की गई कुल राशि (मिलियन रु. में)
बचत खाते (बचत बैंक)	61,990,467	152,981.0
आवर्ती जमा खाते	64,475,526	412,931.2
सावधि जमा खाते	7,892,478	320,607.3
मासिक आय योजना खाते	22,599,857	1,515,735.7
राष्ट्रीय बचत पत्र खाते (87 एवं 92)	808,666	42,332.8
लोक भविष्य निधि खाते	1,873,726	148,298.1
वरिष्ठ नागरिक	164,257	87,839.2

डाक वित्त मार्ट

8.3 पिछले दशक में वित्तीय सेक्टर का उदारीकरण होने के साथ ही डाकघर लघु बचत के सहित वन-स्टॉप-पोस्ट फाइनांस-शॉप के तौर पर अनन्य खुदरा-बिक्री केन्द्र मुहैया करने की दुनियाभर में डाकघर की प्रवृत्ति के अनुरूप तरह-तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित डाकघरों की व्यवस्था

करके वित्तीय सेवाओं में अपने ग्राहकों की निरंतर बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने की मंशा रखता है। इस बात की जरूरत का आकलन किया गया था कि डाक वित्तीय सेवाएं जिस परिवेश में उपलब्ध कराई जा रही हैं उनमें सुधार लाया जाए तथा इन्हें नेटवर्क वाली और कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं के साथ वित्तीय सुपर मार्ट के तौर पर एक छत के नीचे लाया जाए जिसमें बचत बैंक



Chapter 8

FINANCIAL SERVICES

8.1 The Post Office Savings Bank is one of the oldest and largest banking institution in the country. It operates about 140 Million Savings Accounts. The Post Office Savings Bank Scheme is an agency function performed by the Department of Posts on behalf of the Ministry of Finance, Government of India. The Post Office Savings Bank provides an avenue through the network of 1,54,000 Post Offices and reach to people all over the country to deposit their savings in eight Schemes. Its reach and service is unparalleled by any other banking agency in the country. The Ministry of Finance remunerates the Department of Posts for the Savings Bank work at a rate fixed from time-to-time. During the financial year 2004-05, the Department earned approximately Rs. 20,300 Million as remuneration for Savings Bank work.

8.2 Post Office Savings Bank has a customer base

of 140 Million account holders with annual deposits exceeding Rs. 1,000,000 Million and a branch network of 1,54,000 branches, which is double the size of all banks in the country, put together. Eight products are retailed from the post offices across the country. These are Savings Account, Recurring Deposit, Time Deposit, Monthly Income Scheme, Public Provident Fund, Kisan Vikas Patras, National Savings Certificate and Senior Citizens Savings Scheme. The outstanding balance under all national savings schemes in Post Offices is over Rs. 3,750,000 Million. The Senior Citizens Savings Scheme has been introduced w.e.f. 2nd August, 2004 with a view to provide relief and new avenue of investment and return to Senior Citizens and provides a special rate of interest of 9%. Profile of the seven Savings Schemes are given in Table 4 :-

TABLE 4
SAVINGS SCHEME :PROFILE (AS ON 31.03.2005)

Name of Scheme	Number of Accounts	Total Amount Deposited (Rs. in Million)
Saving Accounts(SB)	61,990,467	152,981.0
RD Accounts	64,475,526	412,931.2
TD Accounts	7,892,478	320,607.3
MIS Accounts	22,599,857	1,515,735.7
NSS Accounts(87 & 92)	808,666	42,332.8
PPF Accounts	1,873,726	148,298.1
Sr. Citizen	164,257	87,839.2

Postal Finance Mart

8.3 With the ushering in of the liberalization of the financial sector in the last decade, the Post Office proposes to meet the rising expectations of its customers in financial services by providing dedicated offices rendering a basket of financial services including small

savings in line with world over trend of the post office providing exclusive retailing outlets as a One-Stop – Post Finance-Shop. There was an assessed need to improve the ambience in which Postal Financial Services are offered and bring under one roof as a Financial Super Market, with networked and computerized facilities providing all postal financial products like Savings Bank

और बचत पत्र, डाक जीवन बीमा, ओरिएंटल जीवन बीमा (गैर-जीवन पार्टनर), अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण, म्युचुअल फंड और बांड, सरकारी प्रतिभूतियों, घरेलू धन अंतरण, आदि जैसे सभी डाक वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं। जमाकर्ताओं को सलाह देने के लिए डाक वित्त मार्ट में एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (एएमएफआई) के कर्मचारी और बीमा अर्हता प्राप्त स्टाफ तैनात रहेंगे। कुछ डाकघरों को डाक वित्त मार्ट के रूप में पुनर्व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है जिससे कि वित्तीय सेवाओं की दृष्टि से मौजूदा डाक नेटवर्क के ब्रांड इमेज आउटलेट का मूल्यवर्धन किया जा सके। प्रारंभिक पहल के रूप में कुछेक डाक वित्त मार्टों ने तमिलनाडु में पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि देशभर के कम से कम 300 अधिक महत्वपूर्ण और अधिक क्षमतावान डाकघरों को दो चरणों में डाक वित्त मार्टों के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। डाकघरों के नेटवर्क और पहुंच को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए भारतीय डाक विभिन्न सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से नई वित्तीय सेवाओं को शुरू करने करने का प्रयास कर रहा है।

डाक विभाग द्वारा प्रारंभ किये गए नये उत्पाद एवं सेवाएं म्युचुअल फंड एवं बांड्स

8.4 म्युचुअल फंड उद्योग में खूब प्रगति कर रहा है तथा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें लगभग 1,550,000 मिलियन रुपये की संपत्ति है। यह उद्योग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के प्रबंधन के तहत है। भारतीय डाक ने म्युचुअल फंडों की खुदरा-बिक्री करने के बिजनेस में प्रवेश किया है ताकि म्युचुअल फंड को चुने हुए डाकघरों के ऐसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाए जो अपने निवेश के लिए तीव्रतर विकास (बढ़ोतरी) के अवसरों की तलाश में रहते हैं। वित्त अधिनियम, 2005 में संशोधन होने के परिणामस्वरूप हिन्दू अविभाज्य परिवारों और अन्य गैर-न्यायिक अस्तित्वों द्वारा डाकघर लघु बचत स्कीमों से अपनी निवेश-राशि निकाल लेने के साथ ही अब धार्मिक, धर्मार्थ, शैक्षणिक संस्थाओं और न्यासों को डाकघरों के माध्यम से यूटीआई धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षणिक सोसायटी एवं न्यास स्कीम (यूटीआई सीआरटीएस) में निवेश करने का ऑफर दिया जाता है।

8.5 पहले से ही 250 से अधिक डाकघरों का बढ़ता हुआ नेटवर्क है जिनमें प्रिंसिपल-पीएनबी/प्रूडेंशियलआईसीआईसीआई/एसबीआई/आईसीआईसीआईकैपिटल/आईडीबीआई/आरबीआई बांडों के चुने हुए म्युचुअल फंडों और बांडों का वितरण किया जा

रहा है। आज भारतीय डाक के वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो में आरबीआई इंडिया रिलीफ बांडों, आईडीबीआई फ्लेक्सी बांड, आईडीबीआई गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज, आईसीआईसीआई पेंशन फंड आदि जैसे अनेकों अन्य संगत वित्तीय उत्पाद हैं। विभाग ने चुने हुए डाकघरों से 17 म्युचुअल फंड स्कीमों की खुदरा बिक्री करने के लिए सितंबर, 2004 में यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। यह देश के म्युचुअल फंड मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है। इस सेवा से न केवल देश के पूंजी बाजार की पहुंच का विस्तार हुआ है वरन इसने आम आदमी के लिए बाजार आधारित निवेश विकल्प भी सुलभ कराया है।

अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा

8.6 भारतीय डाक-वेस्टर्न यूनियन गठबंधन ग्राहकों को वास्तविक समय आधार पर 196 से अधिक देशों से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। फिलहाल यह सेवा 6,800 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध है। अप्रैल 2001 से इस सेवा के द्वारा 298 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की डिलीवरी की जा चुकी है। इसके द्वारा अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक 170 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान प्राप्त किया गया है तथा इससे 110 मिलियन रु. का राजस्व सृजित हुआ है। भारतीय डाक ने "अंतरणों में सबसे अधिक बढ़ोतरी" के लिए वर्ष 2004 और 2005 में पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय डाक ने वेस्टर्न यूनियन अंतरणों की अपनी बाजार हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी की है। यह वर्ष 2004 में 22% थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 30.9% हो गई।

सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा-बिक्री

8.7 आईडीबीआई कैपिटल मार्केट के गठबंधन में डाक विभाग ने तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सिक्यु.) की खुदरा बिक्री शुरू की है और इसे दिल्ली और महाराष्ट्र तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विभाग की नई पहलों का जोर (फोकस) इस तरह की सेवाएं प्रदान करता है जिनसे नेटवर्क की रिटेलिंग (खुदरा-बिक्री) विस्तार-क्षमता के इस्तेमाल से ग्राहकों की जरूरतें पूरी हो सकें और डाकघर न केवल बचत बैंक स्कीमों के लए वरन सार्वजनिक निजी अस्तित्वों (संस्थानों), जो इस विस्तार क्षमता के सहारे उन क्षेत्रों तक पहुंचना चाहते हैं जो अन्यथा उनकी पहुंच से बाहर हैं, के लिए भी वन-स्टॉप शॉप बन सके। भागीदारी की सफलता डाकघर तक ग्राहकों को लाने में सार्वजनिक/निजी भागीदारों के विपणन प्रयासों तथा उन स्थानों में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डाकघर, जो भारत का कोना-कोना कवर करते हैं, की उपस्थिति पर निर्भर करती है।

and Saving Certificates, Postal Life Insurance, Oriental Life Insurance (non-life partner), International Money Transfer, Mutual Fund and Bonds, Government Securities, Domestic Money Transmission, etc. The Postal Finance Mart will be manned by Association of Mutual Funds of India (AMFI) and Insurance qualified staff for providing advice on value addition to depositors. Some post offices are proposed to be remodeled into Postal Finance Marts, so that the value addition of a brand image outlet for financial services can be provided to the existing postal network. Some Postal Finance Marts have already been started in Tamilnadu as an original initiative. It is proposed to re-model, in two phases, at least 300 high worth and high potential post offices in the country into Postal Finance Marts. In order to better utilise the network and reach of the Post Offices, India Post is attempting to introduce new financial services through various public-private partnership.

New Products and Services introduced by Department of Posts

Mutual Funds & Bonds

8.4 The Mutual Funds industry is making rapid strides and growing at a fast pace in the country, with nearly Rs. 1,550,000 Million of assets under the management of Asset Management Companies. India Post has entered into the business of retailing of Mutual Funds so as to bring mutual fund within the reach of a select post office clientele, who are looking for a faster growth avenue for their investment. With the withdrawal of investments by HUF and other non-juridical entities in post office small savings schemes as a result of an amendment to the Finance Act, 2005, the religious, charitable, educational institutions and trusts are today offered investment in UTI Charitable, Religious, Educational Societies and Trusts Scheme(UTICRTS) through post offices.

8.5 There is already a growing network of over 250 post offices distributing select Mutual Funds and Bonds of Principal-PNB/Prudential-ICICI/SBI/ICICI Capital/IDBI/RBI Bonds. The financial services portfolio of India Post, today, has a large number of other relevant financial

products like RBI India Relief Bonds, IDBI Flexi Bond, IDBI Government Securities, ICICI Pension Fund etc. The Department has tied-up in September, 2004 with UTI Asset Management Company Limited, which is the largest player in the Mutual Fund market in the country to retail 17 Mutual Fund Schemes from select post offices. This service while extending the reach of the capital market of the country, also provides the common man easy access to market based investment options.

International Money Transfer Service

8.6 The India Post – Western Union tie-up provides the customer the facility of receiving remittances from more than 196 countries on a real time basis. The service is currently available from more than 6,800 post offices. Remittances in excess of US Dollars 298 Million have been delivered through this service since April 2001. The service has brought in remittances worth 170 Million US Dollars from April 2004 to March 2005 and has generated revenue of Rs. 110 Million. India Post received the award in the years 2004 and 2005 for “Highest Growth in Transactions”. India Post has increased its market share of Western Union transactions from 22% in 2004 to 30.9% in 2005.

Retailing of Government Securities

8.7 In a tie-up with IDBI Capital Market, the Department of Posts has launched the retailing of Government Securities (G-Secs) in Tamilnadu and Andhra Pradesh and it is proposed to be extended to Delhi and Maharashtra. The focus of the Department's initiatives in the area of financial services is to provide a bouquet of services that will cater to the needs of the customer by leveraging the retailing outreach of the network, so that post offices gradually become a one-stop shop not only for Saving Bank Schemes but for public-private entities, who want to ride the outreach to reach areas, which are otherwise inaccessible to them. The partnership success depends on the marketing efforts of the public/private partners to bring the customer to the post office and the presence of the post office as a representative of the Government of India in locations, which covers the length and breadth of the country.

डाक जीवन बीमा

8.8 सन 1884 में प्रारंभ की गई डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई) सरकारी कर्मचारियों के हितलाभ के लिए शुरू की गई सबसे पुरानी डाक जीवन बीमा योजना है। प्रारंभ में यह केवल डाक कर्मचारियों के लिए ही शुरू की गई थी। आज यह स्कीम केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सिविल तथा मिलिट्री कर्मियों, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों,

विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनेकों स्वायत्त तथा वित्तीय संस्थानों और केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवा प्रदान कर रही है। एक अभिनव परिवर्तन के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के हितलाभ के लिए वर्ष 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना (आरपीएलआई) शुरू की गई है।

8.9 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि की स्थिति और वर्ष 2004-05 के दौरान अधिप्राप्त कारोबार की स्थिति नीचे तालिका 5 में दी गई है:-

तालिका 5 डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा द्वारा किया गया कार्य-निष्पादन				
योजना का नाम	अधिप्राप्त पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (मिलियन रु. में)	क्रियाशील (सक्रिय) पालिसियों की कुल संख्या	31.03.2005 तक बीमित सकल राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	344,403	38,306.40	2,391,662	191,054.30
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	1,335,847	72,079.60	3,738,798	185,209.30

8.10 डाक जीवन बीमा निम्नलिखित प्रकार की पालिसियों की सुविधा प्रदान करती है:-

- (i) आजीवन बीमा (सुरक्षा)
- (ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा (सुविधा)
- (iii) बंदोबस्ती बीमा (संतोष)
- (iv) 15 एवं 20 वर्षों के लिए प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (सुमंगल)
- (v) संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा (युगल सुरक्षा)

8.11 ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत पहली चार योजना **उभयनिष्ठ** हैं और एक अतिरिक्त योजना "10 वर्षीय

ग्रामीण डाक जीवन बीमा" भी उपलब्ध है। उनका व्यापारिक (ट्रेड) नाम निम्नानुसार है :

- (i) आजीवन बीमा (ग्राम सुरक्षा)
- (ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा (ग्राम सुविधा)
- (iii) बंदोबस्ती बीमा (ग्राम संतोष)
- (iv) 15 एवं 20 वर्षों के लिए प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (ग्राम सुमंगल)
- (v) 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय)

8.12 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसियों को चालू रखने के लिए पिछली बार बोनस निम्न दरों पर घोषित किया गया था :-

Postal Life Insurance

8.8 Postal Life Insurance (PLI), introduced in 1884, is the oldest life insurance scheme for benefit of Government employees. Initially meant only for the Postal employees, today it caters to employees of the civil and military personnel of the central and state governments, local bodies, Government aided educational institutions, universities, nationalized banks, many

autonomous and financial institutions, public sector undertakings of the central and state Governments. In a major innovation, Rural Postal Life Insurance (RPLI) scheme was also introduced in 1995 for the benefit of the rural populace.

8.9 The status of PLI/RPLI funds as on 31.03.2005, and the business procured during the year 2004-2005 is as given in Table 5.

TABLE 5
PERFORMANCE OF PLI/RPLI

Name of Plan	No of Policies Procured	Sum Assured (Rs. in Million)	Aggregate No. of Active Policies	Aggregate Sum Assured up to 31.03.2005 (Rs. in Million)
PLI	344,403	38,306.40	2,391,662	191,054.30
RPLI	1,335,847	72,079.60	3,738,798	185,209.30

8.10 PLI offers the following types of policies: -

- (i) Whole Life Assurance (Suraksha)
- (ii) Convertible Whole Life Assurance (Suvidha)
- (iii) Endowment Assurance (Santosh)
- (iv) Anticipated Endowment Assurance for 15 & 20 years (Sumangal)
- (v) Joint Life Endowment Assurance (Yugal Suraksha)

trade names are as indicated below: -

- (i) Whole Life Assurance (Gram Suraksha)
- (ii) Convertible Whole Life Assurance (Gram Suvidha)
- (iii) Endowment Assurance (Gram Santosh)
- (iv) Anticipated Endowment Assurance for 15 & 20 years (Gram Sumangal)
- (v) 10 year RPLI (Gram Priya)

8.11 Under RPLI, first four plans are common and one additional plan "10 year RPLI" is also available. Their

8.12 The bonus for continuing PLI and RPLI policies were last declared at the following rates :-

तालिका 6 बोनस की दर			
प्रकार	प्रति 1000/-रुपये की बीमित राशि पर बोनस की दर (रुपये में)		
	आजीवन बीमा	बंदोबस्ती बीमा	प्रत्याशित बीमा
31.3.2002 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा	95	77	70
31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण डाक जीवन बीमा	60	50	50

8.13 वर्ष 2004-2005 के दौरान डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के संबंध में निपटाए गए दावे इस प्रकार हैं:

तालिका 7 निपटाए गए दावे		
विवरण	डाक जीवन बीमा	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
दावों की संख्या	107,357	8,852
भुगतान की गई राशि (मिलियन रु. में)	3310.20	166.40

TABLE 6 RATE OF BONUS			
Type	Rates of bonus per Rupees 1000/- sum assured (in Rs.)		
	Whole Life Assurance	Endowment Assurance	Anticipated Assurance
PLI as on 31.03.2002	95	77	70
RPLI as on 31.03.2001	60	50	50

8.13 Details of claim under PLI and RPLI policies, settled during the year 2004-2005, are as given below : -

TABLE 7 CLAIMS SETTLED		
Details	PLI	RPLI
No. of Claims	107,357	8,852
Amount Paid (Rs. in Million)	3310.20	166.40

अध्याय 9

वित्तीय प्रबंधन

प्रस्तावना

9.1 डाक विभाग जनता को डाकघरों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा विभिन्न डाक सेवाएं उपलब्ध कराता है। पूर्णतया डाक सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संगठनों की ओर से बचत बैंक, पेंशन का भुगतान, बचत पत्रों की बिक्री आदि जैसी एजेन्सी कार्य भी करते हैं।

9.2 वर्ष 2004-05 के दौरान बचत बैंक और बचत पत्र कार्य के पारिश्रमिक सहित कुल अर्जित राजस्व 44,318.47 मिलियन रुपये था और अन्य मंत्रालयों/विभागों से एजेंसी प्रभार के रूप में प्राप्त हुई राशि 1,508.45 मिलियन रु. थी। पिछले वर्ष में 57,360.61 मिलियन रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 2004-05 में कुल कार्यकारी-व्यय 59,645.37 मिलियन रुपये है (लगभग 3.98% की वृद्धि)। व्यय में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत तथा संबंधित पेंशनरी प्रभार के भुगतान और

तालिका 8 राजस्व और व्यय (वर्ष 2004-05 के लिए)			
व्यौरा	वास्तविक आंकड़े 2003-04	वास्तविक आंकड़े 2004-05	(रुपये मिलियन में) पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ प्रतिशत कमी (-)
राजस्व			
डाक-टिकटों की बिक्री	8,946.62	7,986.58	(-)10.73
नकदी के रूप में प्राप्त डाक शुल्क	11,559.31	12,971.13	12.21
मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर आदि पर कमीशन	3,181.34	3,268.94	2.75
बचत बैंक/बचत पत्र कार्य के लिए पारिश्रमिक	17,625.00	18,610.00	5.59
* अन्य प्राप्तियां	1,257.02	1,481.82	17.88
कुल	42,569.29	44,318.47	4.11
व्यय			
सामान्य प्रशासन	3,306.95	3,448.69	4.29
प्रचालन	37,838.19	38,833.25	2.63
एजेंसी सेवाएं	1,967.95	2,042.15	3.77
** अन्य	14,247.52	15,321.28	7.54
कुल सकल व्यय	57,360.61	59,645.37	3.98
घटाएं-वसूलियां	1,039.09	1,508.45	45.17
निवल व्यय	56,321.52	58,136.92	3.22
घाटा (निवल व्यय-राजस्व)	13,752.23	13,818.45	0.48

* इसमें डाक विभाग द्वारा बिक्री किए गए पासपोर्ट आवेदन फार्म, पासपोर्ट शुल्क टिकट एवं केन्द्रीय भर्ती फीस टिकट के सेवा प्रभार तथा अन्य डाक प्रशासनों आदि से हुई आय शामिल है।

** इसमें मजदूरी, कार्यालय व्यय, समयोपरि भत्ता, किराया एवं कर, व्यावसायिक सेवाएं, अनुरक्षण, स्टाफ को सुविधाएं, पेंशन संबंधी प्रभार, आपूर्ति और सामग्री, यांत्रिक एवं उपस्कर तथा अन्य प्रशासनिक व्यय आदि शामिल हैं।

Chapter 9

FINANCIAL MANAGEMENT

Introduction

9.1 The Department of Post provides postal services to the public through a large nation wide network of Post Offices. Besides providing purely postal services, Post Offices perform agency functions like Savings Bank, Payment of Pension, Sale of Cash Certificates, etc., on behalf of other Ministries/Departments of the Government of India/other organisations.

9.2 The total revenue earned including remuneration for SB and SC work during the year 2004-05 was Rs. 44,318.47 Million and the amount received from other Ministries/Departments as Agency charges was Rs. 1,508.45 Million. Gross working expenditure for the year 2004-05 was Rs. 59,645.37 Million against the previous year's expenditure of Rs. 57,360.61 Million (i.e. an increase of about 3.98%). The increase was mainly due to

TABLE 8
REVENUE AND EXPENDITURE (FOR THE YEAR 2004-2005)

(Rs. in Million)			
Particulars	Actuals 2003-04	Actuals 2004-05	% age Inc (+)/Dec (-) over previous year
Revenue			
Sale of Stamps	8,946.62	7,986.58	(-) 10.73
Postage Realised in Cash	11,559.31	12,971.13	12.21
Commission on Money Orders and Indian Postal Orders etc.	3,181.34	3,268.94	2.75
Remuneration for Saving Bank/Saving Certificates Work	17,625.00	18,610.00	5.59
*Other Receipts	1,257.02	1,481.82	17.88
Total	42,569.29	44,318.47	4.11
Expenditure			
General Administration	3,306.95	3,448.69	4.29
Operation	37,838.19	38,833.25	2.63
Agency Services	1,967.95	2,042.15	3.77
**Others	14,247.52	15,321.28	7.54
Total Gross Expenditure	57,360.61	59,645.37	3.98
Less Recoveries	1,039.09	1,508.45	45.17
Net Expenditure	56,321.52	58,136.92	3.22
Deficit (Net Expenditure-Revenue)	13,752.23	13,818.45	0.48

* This includes service charges retained by the Department of Posts from sale of Passport Application Form, Passport Fee Stamps, Central Recruitment Fee Stamps, receipts from other Postal Administrations etc.

** This includes Wages, Office Expenses, Overtime Allowance, Rent and Taxes, Professional Services, Maintenance, Amenities to Staff, Pension charges, Supplies and Material, Machinery and Equipment and Other Administrative Expenses, etc.

तालिका 9
2003-04 और 2004-05 में एजेंसी सेवाओं पर कार्यकारी-व्यय की वसूली

(मिलियन रुपये में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	2003-04 वास्तविक आंकड़े	2004-05 वास्तविक आंकड़े
1.	सैनिक पेंशन	0.00	10.74
2.	कोयला खनिकों तथा ईपीएफ/परिवार पेंशन तथा विविध सेवाओं का भुगतान	42.10	40.84
3.	रेलवे पेंशन का भुगतान	111.26	85.52
4.	डाक जीवन बीमा	709.33	1243.75
5.	सीमा शुल्क वसूली	72.79	15.87
6.	महिला समृद्धि योजना	0.00	0.00
7.	अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण खातों पर कमीशन-वेस्टर्न यूनियन स्कीम	38.75	69.55
8.	संयुक्त डाक-तारघरों का टेलीग्राफ हिस्सा	36.06	10.39
9.	अन्य*	28.80	31.79
	कुल	1,039.09	1,508.45

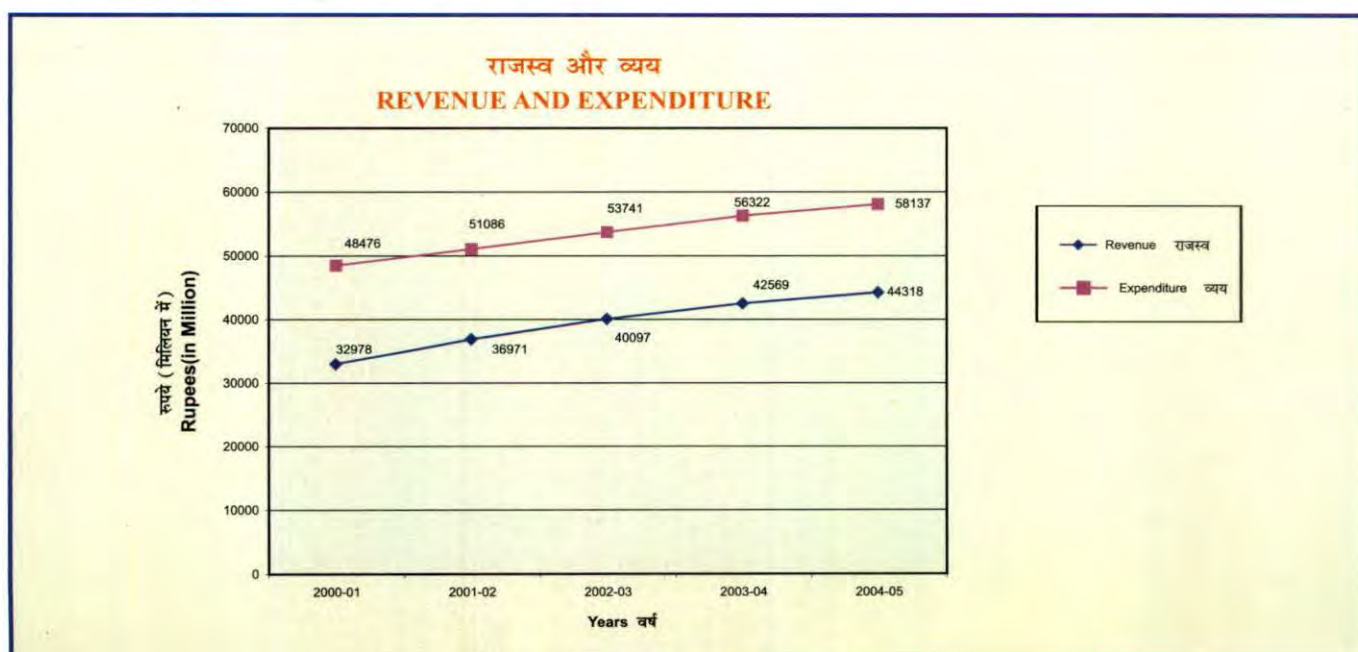
* इसमें दिल्ली प्रशासन के गैर-डाक टिकटों की बिक्री पर कमीशन, सेना डाक सेवा लेखा और अन्य सरकारी विभागों से वसूलियां आदि शामिल हैं।

TABLE-9
RECOVERY OF WORKING EXPENSES ON ACCOUNT OF AGENCY
SERVICES IN 2003-04 AND 2004-05

(Rs. in Million)

Sl. No.	Head of Account	2003-04 Actuals	2004-05 Actuals
1.	Military Pension	0.00	10.74
2.	Payment of Coal Miners and EPF/Family Pension & other Misc. Services	42.10	40.84
3.	Payment of Railway Pension	111.26	85.52
4.	Postal Life Insurance	709.33	1243.75
5.	Custom Duty Realisation	72.79	15.87
6.	Mahila Samridhi Yojna	0.00	0.00
7.	Commission on A/c. of International Money Transfer – Western Union Scheme	38.75	69.55
8.	Telegraph share of Combined Offices	36.06	10.39
9.	*Others	28.80	31.79
Total		1,039.09	1,508.45

* This includes Commission on sale of Non-Postal stamps of Delhi Administration, Recoveries from Army Postal Service Accounts and other Government Departments.



50% दैनिक भत्ते के विलय के कारण है। पिछले पांच वर्षों की भांति, इस वर्ष भी विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीलिंग के अंदर व्यय को रखने में सफल रहा, ऐसा कड़े बजटीय नियंत्रण और व्यय की सूक्ष्म मानीटरिंग के कारण संभव हुआ। अतः वेतन और पेंशनरी प्रभार में वृद्धि के बावजूद विभाग का घाटा 13,818.45 मिलियन रुपये आंका गया है।

9.3 विभाग की आय "वसूलियां" और "राजस्व" के रूप में होती हैं तथा तालिका 9 में दी गई "वसूलियां" अन्य विभागों एवं संगठनों की ओर से किए गए एजेंसी कार्यों के लिए विभाग द्वारा अर्जित कमीशन की राशि है और "राजस्व" में आय, डाक सामग्री की बिक्री, मनीआर्डर तथा भारतीय पोस्टल आर्डर पर कमीशन, अन्य प्रीमियम सेवाओं से प्राप्तियां, बचत बैंक तथा बचत पत्रों से प्राप्त पारिश्रमिक से होती है। कार्यकारी-व्यय की तुलना में विभाग की आय कम है। इससे घाटे और वित्त मंत्रालय

से मिलने वाली बजट सहायता में क्रमिक वृद्धि हुई है। तथापि डाक घाटे में क्रमिक वृद्धि की इस प्रवृत्ति को विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न नई सेवाओं के माध्यम से अधिक राजस्व अर्जित करके और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर व्यय को नियंत्रित रखकर रोका गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग का घाटा 13,818.45 मिलियन रु. था जो पिछले वर्ष के 13752.23 मिलियन रु. के घाटे से 0.48% अधिक है। इस प्रकार राजस्व प्राप्ति की 4.11% सराहनीय वृद्धि के कारण कार्यकारी-व्यय में 3.22% की वृद्धि के बावजूद घाटे में वृद्धि केवल 0.48% रही।

9.4 वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान "कार्यकारी-व्यय" और "पूंजीगत परिव्यय" के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष के दौरान समुचित रूप से उपयोग कर लिया गया था। अधिशेष निधि को समय पर वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित कर

तालिका 10

2004-05 के दौरान अभ्यर्पित निधियां तथा बचत

(मिलियन रुपये में)

व्यय की प्रकृति	बजट प्राक्कलन	पुनः विनियोजित अनुपूरक अनुदान	कुल	वास्तविक व्यय	अधिक (+)/ बचत (-)	अभ्यर्पित/ पुनः विनियोजित राशि	बचत
3201 कार्यकारी-व्यय	60273.10	140.60	60413.70	59645.37	-768.33	180.07	-588.26
2552 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान	30.60	0.00	30.60	0.00	-30.60	30.60	0.00
कुल कार्यकारी-व्यय	60303.70	140.60	60444.30	59645.37	-798.93	210.67	-588.26
5201 पूंजीगत परिव्यय	1718.40	69.10	1787.50	1262.85	-524.65	390.30	-134.35
4552 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान	69.00	0.00	69.00	0.00	-69.00	69.00	0.00
कुल कार्यकारी-व्यय	1787.40	69.10	1856.50	1262.85	-593.65	459.30	-134.35
कुल कार्यकारी व्यय+पूंजीगत व्यय	62091.10	209.70	62300.80	60908.22	-1392.58	669.97	-722.61

payment of Dearness Allowance/Dearness Relief, Pensionary charges and impact of 50% merger of D.A. Like last five years, this year also the Department was able to keep the expenditure within the ceiling fixed by the Ministry of Finance through strict budgetary control and close monitoring of expenditure. Despite the increase in salaries and Pensionary charges, the deficit of the Department was pegged at Rs. 13,818.45 Million.

9.3 The earnings of the Department are in the form of 'Recoveries' and 'Revenue'. The item 'Recoveries' mentioned in Table 9 represents the amount of commission earned by the Department for Agency Functions done on behalf of other Departments and organisations and 'Revenue' is on account of sale of Postal Articles, commission on money orders and Indian Postal Orders, receipts from other premium services, remuneration for Savings Bank and Savings Certificates

work etc. The earnings of the Department are on the lower side in comparison to the working expenses incurred. This results in gradual increase in deficit and corresponding budgetary support from the Ministry of Finance. However, this trend of gradual increase in deficit has been arrested by generating more revenue through different new services introduced by the Department and containing the expenditure within the ceiling fixed by the Ministry of Finance. During the financial year 2004-05, the deficit of the Department was Rs. 13,818.45 Million, which is 0.48% more than previous year's deficit of Rs. 13,752.23 Million. Thus despite increase in Working Expenses of 3.22%, the deficit increase was only 0.48% due to appreciable increase in Revenue Receipts of 4.11%.

9.4 The funds made available by the Ministry of Finance for 'Working Expenses' and 'Capital Outlay' during the year, were appropriately utilized. Surplus funds were surrendered in time to the Ministry of Finance. This

TABLE 10
FUNDS SURRENDERED AND SAVINGS DURING 2004-05

(Rs. in Million)

Nature of Expenditure	Budget Est.	Suppl. Grant/ Re-app.	Total	Actual Expd.	Excess(+)/ Saving(-)	Amount Surrendered/ Re-app.	Savings
3201 Working Exp	60273.10	140.60	60413.70	59645.37	-768.33	180.07	-588.26
2552 Prov. For the Development of North East Region	30.60	0.00	30.60	0.00	-30.60	30.60	0.00
Total working Exp.	60303.70	140.60	60444.30	59645.37	-798.93	210.67	-588.26
5201 Capital Exp.	1718.40	69.10	1787.50	1262.85	-524.65	390.30	-134.35
4552 Prov. for the Development of North East Region	69.00	0.00	69.00	0.00	-69.00	69.00	0.00
Total Capital Exp:	1787.40	69.10	1856.50	1262.85	-593.65	459.30	-134.35
Total Working Exp. + Capital Exp.	62091.10	209.70	62300.80	60908.22	-1392.58	669.97	-722.61

दिया गया था। ऐसा प्रभावपूर्ण बजटीय नियंत्रण और व्यय की माहवार प्रगति की मानीटरिंग के कारण संभव हो सका।

पूँजीगत परिव्यय

9.5 वर्ष 2004-05 में नियत परिसम्पत्तियों पर 1279.77 मिलियन रुपये का व्यय हुआ जिसमें से 12.04% भूमि और भवनों पर और 86.00% डाक सेवाओं के

यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण पर, 0.00% रेल डाक वाहनों और 1.96% मेल मोटर वाहनों और अन्य पर हुआ। वर्ष के अंत में नियत परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत मूल्य बढ़कर 12,841.31 मिलियन रुपये हो गया। वर्ष के अंत तक निवल प्रगामी नियत परिसम्पत्ति मूल्य 11,106.27 मिलियन रुपये हो गया।

तालिका 11
सेवाओं की लागत

(रूपयों में)

क्र. सं.	सेवा का नाम	2002-03 (वास्तविक)		2004-05 (अनुमान)	
		औसत लागत	औसत राजस्व	औसत लागत	औसत राजस्व
1.	पोस्टकार्ड	7.06	0.50	6.96	0.50
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	7.08	5.50	6.88	6.00
3.	प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	5.12	9.17	5.09	10.00
4.	पत्र कार्ड (अंतर्देशीय पत्र)	7.00	2.42	6.97	2.50
5.	पत्र	7.92	9.46	8.43	10.04
6.	पंजीकृत समाचार पत्र -एकल	9.03	0.39	9.72	0.39
7.	पंजीकृत समाचार पत्र - बंडल	14.54	0.88	17.03	0.79
8.	बुक पोस्ट -बुक, पैटर्न एवं सैम्पल पैकेट	9.05	7.67	10.78	7.27
9.	बुक पोस्ट - मुद्रित पुस्तकें	14.55	3.85	14.95	4.37
10.	बुक पोस्ट - अन्य पत्रिकाएं	14.59	14.15	14.97	9.44
11.	पावती	6.23	3.00	6.17	3.00
12.	पार्सल	66.79	55.28	66.47	57.17
13.	पंजीकरण	33.69	17.00	33.57	17.00
14.	स्पीड पोस्ट	44.73	38.33	45.88	36.08
15.	मूल्यदेय डाक	19.78	3.98	23.55	4.07
16.	बीमा	44.21	53.47	45.06	53.21
17.	मनीआर्डर	53.86	26.89	57.61	27.37
18.	तार मनीआर्डर	69.38	28.89	75.91	29.37
19.	भारतीय पोस्टल आर्डर	21.05	1.66	24.24	2.18
20.	विदेश डाक	15.90	22.42	20.40	35.56

was made possible by effective budgetary control and monitoring the progress of expenditure on a monthly basis.

Capital Outlay

9.5 The expenditure on fixed assets in the year 2004-05 was Rs. 1,279.77 Million, of which 12.04% was on Land and Buildings, 86.00% on Mechanization and

Modernisation of Postal Services, 0.00% on Railway Mail Vans and 1.96% on Mail Motor Vehicles and others. The value of Gross Capital on fixed assets rose to Rs. 12,841.31 Million at the end of the year. The net progressive fixed asset value upto the end of the year was Rs. 11,106.27 Million.

Table 11
COST OF SERVICES

(In Rs.)

Sl. No.	Name of Service	2002-03 (Actual)		2004-05 (Projection)	
		Average Cost	Average Revenue	Average Cost	Average Revenue
1.	Postcard	7.06	0.50	6.96	0.50
2.	Printed Postcard	7.08	5.50	6.88	6.00
3.	Competition Postcard	5.12	9.17	5.09	10.00
4.	Letter Card (Inland Letter)	7.00	2.42	6.97	2.50
5.	Letter	7.92	9.46	8.43	10.04
6.	Regd. Newspaper-Single	9.03	0.39	9.72	0.39
7.	Regd. Newspaper-Bundle	14.54	0.88	17.03	0.79
8.	Book Post-Book, Pattern & S.Pkts.	9.05	7.67	10.78	7.27
9.	Book Post-Printed Books	14.55	3.85	14.95	4.37
10.	Book Post-Other Periodicals	14.59	14.15	14.97	9.44
11.	Acknowledgement	6.23	3.00	6.17	3.00
12.	Parcel	66.79	55.28	66.47	57.17
13.	Registration	33.69	17.00	33.57	17.00
14.	Speed Post	44.73	38.33	45.88	36.08
15.	Value Payable Post	19.78	3.98	23.55	4.07
16.	Insurance	44.21	53.47	45.06	53.21
17.	Money Order	53.86	26.89	57.61	27.37
18.	Telegraphic Money Order	69.38	28.89	75.91	29.37
19.	Indian Postal Order	21.05	1.66	24.24	2.18
20.	Foreign Mail	15.90	22.42	20.40	35.56

अध्याय 10

मानव संसाधन विकास

10.1 किसी भी संगठन की शक्ति उससे जुड़े व्यक्तियों में निहित होती है। इस 2,46,678 नियमित कर्मचारियों और 2,93,656 ग्रामीण डाक सेवकों की जनशक्ति वाले विभाग के पास सुविकसित आधारभूत प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध है। विभाग मानव संसाधन विकास पर निरंतर सर्वाधिक ध्यान देता है जिसे डाक प्रचालनों में प्रौद्योगिकी के समावेश, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विपणन पर जोर देने तथा वित्तीय सेवाओं और व्यवसाय विकास कार्यक्रमों में परिवर्तनों के कारण हाल के वर्षों में और अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। इसने प्रबंधक एवं प्रचालक तथा अन्य कर्मचारियों की दक्षता के निरंतर उन्नयन और उनका व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन से ऑन द जॉब और संस्थागत प्रशिक्षण, दोनों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।

प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचा

10.2 निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान विभाग की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं

- भारतीय पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद समूह 'क' और 'ख', अधिकारियों तथा लेखा क्षेत्र के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए।
- दरभंगा, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर, वडोदरा और गुवाहाटी स्थित डाक प्रशिक्षण केन्द्र;
- सर्किल/क्षेत्रीय मुख्यालय में 60 कार्य-स्थल कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (डब्ल्यूसीटीसी)।
- कार्य-स्थल शिक्षण जिसके अंतर्गत डाकियों, ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर्स और डाक वितरकों को कुछ विशेष डाक प्रचालनों पर डिवीजनल/सब डिवीजनल स्तर जैसे नोडल बिन्दुओं में एक सप्ताह से कम की लघु अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पोस्टल स्टाफ कालेज

10.3 भारतीय पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद, विभाग के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शीर्ष प्रशिक्षण संस्था है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य प्रवेश तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा भारतीय डाक सेवा और डाक सेवा समूह "ख" के अधिकारियों में अपेक्षित ज्ञान, दक्षता और आचार-व्यवहार का विकास करना है ताकि वे डाक प्रणाली को अधिक कार्यकुशल और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना सकें।

डाक प्रशिक्षण केन्द्र

10.4 कुल छह डाक प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनकी स्थापना डाक सर्किलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई।

10.5 डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं:

- डाक निरीक्षकों और डाक सहायकों एवं छंटाई सहायकों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना ;
- डाक एवं छंटाई सहायकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर्स आदि को सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर प्रणालियों को समझने, उनका प्रचालन करने के लिए अपेक्षित दक्षता और जानकारी प्रदान करना।

10.6 वर्ष 2004-05 के दौरान पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, छह डाक प्रशिक्षण केन्द्रों और कार्य-स्थल कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया:-

Chapter 10

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

10.1 The strength of an organization lies in its people. The Department with a manpower of 2,46,678 regular employees and 2,93,656 Gramin Dak Sewaks has a well-developed training infrastructure. Priority has been accorded to human resource development, which in recent years received added stimulus in view of induction of technology in postal operations, thrust on marketing of varieties of products in collaboration with Public and Private sectors, bringing changes in the Financial Services and Business Development Activities. Extensive training programmes have been prepared for both on the job as well as institutional training for the managers, operatives and other functionaries, for continually upgrading skills and professional competence.

Training Infrastructure

10.2 Following training institutes take care of the training needs of the Department:-

- Postal Staff College India at Ghaziabad (PSCI) for training Group 'A' and 'B' officers and officers from the Accounts Line;
- Postal Training Centres (PTCs) at Saharanpur, Mysore, Vadodara, Darbhanga, Madurai and Guwahati;
- 60 Workplace Computer Training Centres (WCTCs) at the Headquarter of Circles/Regions;
- Workplace learning whereby short duration training of less than one week is organized at nodal points like Divisional/Sub-Divisional level on selected Postal Operations to Postmen, Gramin Dak Sewak Branch Postmasters and Mail Deliverers.

Postal Staff College

10.3 The Postal Staff College India, Ghaziabad is the apex training institution catering to the training needs of the managerial cadres of the Department. The primary objective of the College is to impart induction as well as in-service training to the officers of the Indian Postal Service and Postal Service Group "B" with a view to inculcating requisite knowledge, skills and attitude to enable them to make the postal system effective and responsive to customers' needs.

Postal Training Centres

10.4 The six Postal Training Centres have been established taking into account the requirement of the Postal Circles.

10.5 The main objectives of the Postal Training Centres are :-

- To impart induction training to Inspectors of Posts and Postal & Sorting Assistants;
- To impart in-service and refresher training to Postal and Sorting Assistants, Supervisors, Inspector Posts, Assistant Superintendent Posts, Postmasters, etc; and
- To impart the skills and knowledge required for understanding and operating computer hardware and software systems relevant to the needs of the Department.

10.6 During the year 2004-05, the Postal Staff College India, six Postal Training Centres and the Workplace Computer Training Centres have trained the following number of officers/staff :-

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यकलाप	डाक प्रशिक्षण संस्थाएं			
		पोस्टल स्टाफ कालेज	डाक प्रशिक्षण केन्द्र	नोडल बिन्दु/ कार्य-स्थल प्रशिक्षण केन्द्र	कुल
1.	प्रवेश प्रशिक्षण	193	2,502	-	2,695
2.	सेवाकालीन प्रशिक्षण	238	6,102	-	6,340
3.	जीडीएसबीपीएम वितरण स्टाफ आदि को सेवाकालीन प्रशिक्षण	-	-	33,718	33,718
4.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	315	10,637	23,218	34,170
5.	विदेशों के अधिकारियों/स्टाफ को प्रशिक्षण	13	23	-	36
6.	विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अधिकारी	8	-	-	8
	कुल	767	19,264	56,936	76,967

S.No.	Training Activity	Postal Training Institutions			
		Postal Staff College	Postal Training Centres	Nodal points/ Workplace Training Centres	Total
1.	Induction Training	193	2,502	-	2,695
2.	In-service Training	238	6,102	-	6,340
3.	In-service Training to GDSBPMs, Delivery Staff, etc.	-	-	33,718	33,718
4.	Computer Training	315	10,637	23,218	34,170
5.	Training of officers/staff of foreign countries	13	23	-	36
6.	Officers sent for training abroad	8	-	-	8
	Total	767	19,264	56,936	76,967

अध्याय 11

सतर्कता कार्यकलाप

11.1 डाक विभाग में सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से सचिव, डाक विभाग की अध्यक्षता में एक पूर्ण विकसित सतर्कता **सेटअप** है। सचिव, डाक विभाग की सहायता के लिए उप महानिदेशक (सतर्कता) हैं जो कि विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता संबंधी मामलों में सचिव के विशेष सहायक के रूप में कार्य करते हैं और डाक विभाग तथा मुख्य सतर्कता आयोग के बीच कड़ी का काम करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए मुख्यालय में निदेशक (सतर्कता), तीन सहायक महानिदेशक और एक डेस्क अधिकारी हैं।

11.2 सर्किल, क्षेत्रीय और डिवीजनल स्तर पर सतर्कता संबंधी कार्य इनके प्रमुख यानी प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल और डिवीजनल अध्यक्ष द्वारा अपने समग्र कार्यों और उत्तरदायित्वों के ही एक भाग के रूप में किए जाते हैं।

11.3 मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता मामलों को देखने के अलावा निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में संवेदनशील स्थानों का नियमित और अचानक निरीक्षण करने, ऐसी कार्यविधियों की समीक्षा करने और उन्हें दोषरहित बनाने के लिए भी जिम्मेदार है जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की आशंका हो। वे विभाग और इसके फील्ड कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दूसरे प्रकार के अनाचारों

की रोकथाम, इनका पता लगाने और दण्ड देने के लिए भी उत्तरदायी है।

11.4 विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समय-समय पर बैठकें होती हैं और सी बी आई के साथ परामर्श करके संदेहास्पद अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है। इन संदेहास्पद अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। संदेहास्पद निष्ठा वाले राजपत्रित अधिकारियों की एक सूची भी तैयार की जाती है।

11.5 महत्वपूर्ण मामलों में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और जहां आवश्यक हो, मामलों की सूचना पुलिस/सी बी आई को भी दी जाती है।

11.6 राजस्व की चोरी का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता दल द्वारा जांच की जाती है। कदाचार और राजस्व की चोरी रोकने के लिए आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान सतर्कता कार्यकलाप (सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय सहित) इस प्रकार रहे:-

- (i) 7 अधिकारियों और 1416 अन्य कर्मचारियों को बड़ा दण्ड और 46 अधिकारियों और 6580 अन्य कर्मचारियों को छोटा दण्ड दिया गया।
- (ii) 46 रिपोर्टों की जांच हुई और उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया।

Chapter 11

VIGILANCE ACTIVITIES

11.1 The Department of Posts has a full-fledged vigilance set up at its headquarters at New Delhi headed by the Secretary (Posts) for maintenance of integrity and efficiency in the Department. He is assisted by the Deputy Director General (Vigilance), who is the Chief Vigilance Officer (CVO) of the Department. The CVO acts as the Special Assistant to the Secretary in all matters pertaining to vigilance and provides a link between the Department of Posts and the Central Vigilance Commission (CVC). The CVO is assisted by a Director (Vigilance), three Assistant Directors General and one Desk Officer at the Headquarter.

11.2 At the Circle, Regional and Divisional levels, vigilance related functions are discharged by heads of these formations, viz. Principal Chief Postmaster General/Chief Postmaster General, Regional Postmaster General and Divisional Heads, as part of their overall duties and responsibilities.

11.3 Besides, dealing with vigilance cases, as a part of preventive vigilance the CVO arranges regular and surprise inspections of sensitive spots, review and streamlining of procedures, which appear to afford scope for corruption or misconduct, initiate measures for

prevention, detection of corruption and other malpractices in the Department and its field offices.

11.4 Periodical meetings with CBI at various levels are held and Agreed Lists of suspected officers drawn up in consultation with CBI. Close watch is kept on the listed officers. List of Officers of doubtful integrity has also been prepared.

11.5 Investigations by deputing officers from the Directorate are carried out in important cases. The cases are also reported to Police/CBI, where necessary.

11.6 Surprise visits are carried out in offices through the Central Checking Squad to detect leakage of revenue. Appropriate action is taken to prevent malpractices and leakage of revenue. Vigilance activities during the year (including attached and subordinate office) were as follows: -

- (i). 7 Officers and 1,416 other staff were awarded major penalty while 46 Officers and 6,580 other staff were awarded minor penalty.
- (ii). 46 reports were examined and sent to CVC.

अध्याय 12

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

12.1 31.3.2005 को विभाग में कुल 2,46,678 विभागीय कर्मचारी थे जिसमें विभिन्न ग्रेडों में 31,800 महिला कर्मचारी शामिल हैं (देखें तालिका 16)। डाक विभाग के सभी प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग में महिलाएं प्रचालक से लेकर नीति और निर्णय लेने के स्तरों पर कार्यरत हैं। वे सभी दायित्वों का समान रूप से निर्वहन करती हैं, चाहे यह कार्यालय में बैठकर हो या इसके बाहर काम करके।

12.2 लैंगिक समानता, समता और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का सिद्धांत डाक विभाग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनने और उन्नतिशील एवं सहयोगपूर्ण परिवेश सुनिश्चित करने के

लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे वे अपने घर और कार्य की जिम्मेदारियों में संतुलन रखने में सक्षम हो पाएंगी। इसमें महिला कर्मचारियों के लिए अलग से **विश्राम** कक्षों और मनोविनोद कक्षों की व्यवस्था करना और जहां संभव हो, शिशुसदनों की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

12.3 महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निदेशालय में एक समिति स्थापित की गई है। समिति की अध्यक्ष निदेशक रैंक की एक महिला अधिकारी हैं। इसमें चार सदस्य हैं। फील्ड में भी डिवीजन स्तर पर समान प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है। वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

Chapter 12

GENDER ISSUES

12.1 On 31.03.2005 there were 2,46,678 departmental employees, which includes 31,800 women employees in various grades in the Department (see Table 16). Gender sensitization modules have been included in all Induction and In-service Training programmes of the Department of Posts. Women hold positions at all levels in the Department ranging from operative to policy and decision-making levels. They partake equally in all responsibilities, be it office based or outdoor.

12.2 The principles of gender equality, equity and protection of the rights of women are a matter of prime concern of the Department of Posts. Every effort is being made to be sensitive to their needs and ensure a thriving

and supportive environment, which will enable them to balance their responsibilities at work with those at home. This includes providing separate rest rooms and recreation rooms for women employees and providing crèche facilities, where possible.

12.3 To look into the matter of prevention of sexual harassment of women a committee chaired by a lady officer of the rank of Director has been set up in the Directorate with four other members. Similar bodies have been set up at every level up to the Division level in the field. The Committee has not received any complaint during the year.



सेतुपति हायर सेकेंडरी स्कूल, मदुरै, तमिलनाडु
Sethupathy Higher Secondary School, Madurai, Tamil Nadu

डाक सेवाओं पर कोलाज।
Collage on Postal Services.

अध्याय 13

अन्य कार्यकलाप

कर्मचारी संबंध

13.1 अवधि के दौरान विभाग ने अपने कर्मचारियों के परिसंघों और यूनियनों/संघों से आत्मीय और सार्थक संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया। डाक कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार हेतु दिनांक 17 नवम्बर, 2004 को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ और उससे संबद्ध यूनियनों की माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई। माननीय मंत्री की यूनियन के नेताओं के साथ बैठक संक्षिप्त रही तथापि, ब्यौरेवार परिचर्चा नहीं हो सकी। अवधि के दौरान सचिव (डाक) ने सभी तीनों परिसंघों और उनसे संबद्ध यूनियनों से विभिन्न कर्मचारी समस्याओं पर विचार के लिए आवधिक बैठकें कीं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ (एनएफपीई) और राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ (एफएनपीओ) के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन 17 नवम्बर, 2004 को किया गया। सचिव (डाक) ने 19 नवम्बर, 2004 को भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ (बीपीईएफ) के साथ भी एक अनौपचारिक बैठक की।

13.2 विभागीय परिषद (जेसीएम) की बैठक 18 फरवरी, 2005 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई जिसमें कार्य-सूची के सभी मुद्दों पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया गया और कर्मचारी पक्ष की परस्पर सहमति भी ली गई जो कि स्कीम का मूल आधार है। बैठक में हुई सहमतियों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

13.3 19 और 20 अक्टूबर, 2004 को पोस्टल स्टाफ कॉलेज में यूनियन के मामलों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डाक विभाग में सभी तीनों परिसंघों से संबद्ध यूनियनों के नेताओं ने संगोष्ठी में भाग लिया।

13.4 राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ (एनएफपीई) और राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ (एफएनपीओ) ने अपने मांग-पत्र के साथ 15 मार्च, 2005 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एक नोटिस दिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐसा ही एक

नोटिस भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ (बीपीईएफ) द्वारा भी दिया गया। नोटिस के मिलते ही, विभाग की पहल पर मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार परिसंघ के साथ समाधान कार्यवाहियां प्रारंभ कर दीं। सचिव (डाक) ने 28 फरवरी, 09 मार्च और 14 मार्च, 2005 को परिसंघों/यूनियनों के नेताओं के साथ भी बैठकें आयोजित कीं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ और राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ की 14 मार्च, 2005 को माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ बैठक के बाद, परिसंघों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया गया। उक्त समझौते के अनुसार मांग-पत्र पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई/की जा रही है।

13.5 18 नवंबर, 2003 को आयोजित विभागीय परिषद की बैठक में हुई परिचर्चाओं की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने दिनांक 12 जुलाई, 2004 को डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर का दौरा किया और प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में संतोष व्यक्त किया।

13.6 जहां तक जन शिकायत निवारण कार्य का संबंध है यह उल्लेख किया जाता है कि डाक विभाग में परिसंघों/यूनियनों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के रूप में पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। इसके अलावा, सरकारी कामकाज में अधिक खुलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में हो रहे परिवर्तनों से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को विशेष बैठकों और मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों के दौरान अवगत कराया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, सेवा संघों/यूनियनों को ग्राह्य ट्रेड यूनियन सुविधाओं से संबंधित अनुदेशों का एक संकलन 25 जून, 2004 को जारी किया गया।

कर्मचारी कल्याण

13.7 डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कल्याण, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलापों

Chapter 13

OTHER ACTIVITIES

Staff Relation

13.1 During the period, the Department endeavoured to maintain harmonious and meaningful relations with the Federations and Unions/Association of its employees. A meeting of National Federation of Postal Employees and its affiliated Unions with the Hon'ble Minister of Communications & IT was held on 17th November, 2004 to discuss the grievances of the Postal Employees. The Hon'ble Minister had a brief meeting with the Union leaders, however, detailed discussions could not take place. Secretary (Posts) had Periodical meetings with all the three Federations and their affiliated unions during the period, to discuss various staff problems. The periodical meetings with National Federation of Postal Employees (NFPE) and with the Federation of National Postal Organisations (FNPO) were held on 17th November, 2004. Secretary (Posts) also held an informal meeting with Bharatiya Postal Employees Federation (BPEF) on 19th November, 2004

13.2 The meeting of Departmental Council (JCM) in the Department of Posts was held on 18th February, 2005 in a congenial atmosphere wherein all agenda items were discussed threadbare and in mutual agreement with the staff-side as per the spirit of the scheme. Necessary follow-up action is being taken on the agreements reached in the meeting.

13.3 A Seminar on Union matters was organised in the Postal Staff College, India on 19th and 20th October, 2004. The leaders from the Unions affiliated to all the three Federations in the Department of Posts attended the Seminar.

13.4 A notice for indefinite strike w.e.f. 15th March, 2005 along with a Charter of Demands was served by National Federation of Postal Employees (NFPE) and Federation of National Postal Organisations (FNPO). A similar notice for indefinite strike was also given by

Bharatiya Postal Employees Federation(BPEF). As soon as the notice was received, with the initiative of the Department, the Office of the Chief Labour Commissioner initiated conciliation proceedings with the federations as per provisions of the Industrial Disputes Act, 1947. Secretary (Posts) also held meetings with the leaders of federations/unions on 28th February, 09th March, and 14th March, 2005. After a meeting of National Federation of Postal Employees and Federation of National Postal Organisations with the Hon'ble Minister of Communications and IT on 14th March, 2005, an agreement was signed with the Federations and the strike notice was withdrawn. Necessary follow-up action on the charter of demands has been/is being taken as per the aforesaid agreement.

13.5 As a follow up action of discussions held in the meeting of the Departmental Council held on 18th November, 2003, the members of the staff side visited Postal Training Centre, Mysore on 12th July, 2004 and expressed satisfaction regarding training process.

13.6 In so far as Public Grievances Redressal work is concerned, it is to mention that in the Department of Posts, the Federations/Unions have been provided with enough opportunities in the form of formal as well as informal meetings to redress their grievances. Further, with a view to ensuring greater openness in the government functioning, the staff representatives are kept apprised about the new developments taking place in the Department by way of granting special meetings as well as during periodical meetings with Minister/Sr. Officers. In addition to above, a compilation of instructions relating to Trade Union Facilities admissible to Service Associations/Unions was issued on 25th June, 2004.

Staff Welfare

13.7 The objective of the Postal Services Staff Welfare Board is to promote, develop and organise

को आयोजित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है। बोर्ड को इसके लिए भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। सांस्कृतिक कार्यकलापों तथा खेलकूद के माध्यम से धन प्राप्त होता है और कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान भी दिया जाता है।

13.8 कल्याण बोर्ड के कोषों का उपयोग खेलकूद, मनोरंजन क्लबों, बीमारी, मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करने, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, पर्यटन यात्राओं के लिए सब्सिडी, विकलांग कर्मचारियों तथा उनके बच्चों की सहायता करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, क्लेशों (शिशुगृहों) आदि के लिए किया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 55 मिलियन रु. आवंटित किए गए थे।

दौरान इस प्रकार का एक मामला हुआ और इसके लिए मृतक कर्मचारी के परिवार को मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सर्किल कल्याण निधियों से संस्वीकृत 7000/- रु. के अलावा केन्द्रीय कल्याण निधि से 43,000/-रु. भुगतान के लिए संस्वीकृत किए गए।

13.11 सदस्य (विकास) की अध्यक्षता में अनुकंपा आधार पर वित्तीय सहायता के अनुदान निर्धारण के लिए गठित समिति ने नीचे दी गई तालिका के अनुसार 09 दिसंबर, 2004 को आयोजित बैठक में वित्तीय सहायता के अनुदान संबंधी 3 प्रस्ताव समाशोधित किए:-

हॉलिडे होम

13.12 कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित के लिए देश के विभिन्न स्थानों में 30 हॉलिडे होम काम कर रहे हैं।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	प्रयोजन/कारण	राशि
(i)	श्री पी. उन्नी, समूह 'घ' (केरल सर्किल)	स्वयं के इलाज हेतु	20,000 रु.
(ii)	श्री एन. सुरेश, जीडीएसएमसी (कर्नाटक सर्किल)	ट्राई-साइकिल खरीदने और साथ ही स्वयं के इलाज हेतु	32,000 रु.
(iii)	श्री सैयद सलीम, जीडीएसबीपीएम (आंध्र प्रदेश सर्किल)	स्वयं के इलाज हेतु	10,000 रु.

13.9 वर्ष 2004-05 के दौरान, 55 मिलियन रु. के कुल बजट अनुदान में से विभाग के कल्याण और खेलकूद कार्यकलापों पर और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित कर्मचारियों को राहत/ वित्तीय सहायता के अनुदान पर हुआ कुल व्यय 53.8 मिलियन रुपये था। निदेशालय कल्याण निधि सहित सर्किल कल्याण निधि, डाक प्रशिक्षण केन्द्र और पोस्टल स्टाफ कालेज को संवितरित राशि 26.25 मिलियन रु. थी। सर्किल खेल निधि को संवितरित राशि 8.99 मिलियन रु. थी। इसके अलावा, विभाग के बाढ़/ सुनामी प्रभावित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पांच सर्किल कल्याण निधियों को 18.53 मिलियन रु. की राशि आवंटित की गई थी।

ड्यूटी पर डकैती, आतंकवादी हमलों, दंगों आदि के कारण मारे गए विभागीय कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय कल्याण निधि से वित्तीय सहायता।

13.10 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 की अवधि के

खेल

13.13 01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान 12 खेलों के लिए जैसे कि टेबल टेनिस, बास्केटबाल, हॉकी, फुटबाल, बैडमिंटन, कबड्डी, वालीबाल, कुश्ती, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग तथा सर्वश्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव, एथलेटिक्स और साइक्लिंग क्रिकेट, शतरंज और कैरम के लिए भारतीय डाक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सचिव (डाक) की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 को बेंगलूर में 17वीं डाक खेलकूद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

13.14 पुनरीक्षा अवधि के दौरान भारतीय डाक टीमों ने कई विभिन्न राष्ट्रीय समारोहों में भाग लिया। 2 से 5 दिसम्बर, 2004 के दौरान, विभाग के दो कर्मचारियों ने क्लीवलैंड, सं.रा. अमरीका में आयोजित वर्ल्ड बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भाग लिया।

welfare, sports and cultural activities for the employees of the Department. The Board receives grant-in-aid for this purpose from the Consolidated Fund of India. Voluntary contributions from the staff and collections through sports and cultural activities are also arranged.

13.8 The funds of the Welfare Board are utilised for activities like sports, recreation clubs, financial assistance in cases of illness, death and natural calamities, educational scholarships, subsidy for excursion trips, grants to help handicapped staff and their children, Vocational Training Centres and Crèches, etc. During the year 2004-2005 an amount of Rs. 55 Million was allocated for the purpose.

has been sanctioned for payment to the family of the deceased official from Central Welfare Fund besides Rs. 7,000/- sanctioned from Circle Welfare Fund, as per existing instructions.

13.11 The Committee constituted for deciding grant of financial assistance on compassionate grounds headed by Member (D), cleared 3 proposals relating to grant of financial assistance in a meeting held on 09th December, 2004 as detailed below: -

Holiday Homes

13.12 30 Holiday Homes are functioning at various

S.No.	Name & Designation	Purpose/reason	Amount
(i).	Shri P. Unni, Group 'D' (Kerala Circle)	For his own treatment	Rs. 20,000/-
(ii).	Shri N. Suresh, GDSMC (Karnataka Circle)	To purchase Tricycle and also for his own treatment	Rs. 32,000/-
(iii).	Shri Syed Saleem, GDSBPM (Andhra Pradesh Circle)	For his own treatment	Rs. 10,000/-

13.9 During the year 2004-05, out of the total Budget Grant of Rs. 55 Million the total expenditure on Welfare/ Sports activities of the Department as well as on grant of relief/financial assistance to employees affected by natural calamities was Rs. 53.8 Million. The amount disbursed to Circle Welfare Funds including Directorate Welfare Fund, Postal Training Centres and Postal Staff College was Rs. 26.25 Million. An amount of Rs. 8.99 Million was disbursed to Circle Sports Funds. Besides this, an amount of Rs. 18.53 Million was allocated to five Circle Welfare Funds for providing financial assistance to flood/Tsunami affected employees of the Department.

Financial assistance from Central Welfare Fund in case of Departmental Officials' death due to attack by robbers/ terrorists/riots etc., on duty

13.10 During the period from 1st April, 2004 to 31st March, 2005 one such case occurred in which Rs. 43,000/-

places of the country for the benefit of the employees and their families.

Sports

13.13 During the period from 01st April, 2004 to 31st March, 2005, All India Postal Sports Tournaments for 12 events viz. Table Tennis, Basketball, Hockey, Football, Badminton, Kabaddi, Volleyball, Wrestling, Weightlifting/ Powerlifting & Best Physique, Athletics & Cycling, Cricket, Chess & Carrom, were organised. In addition, a Cultural Meet was also organised. 17th Postal Sports Board Meeting was held on 28th October, 2004 at Bangalore under the Chairmanship of Secretary (Posts).

13.14 During the period under review India Post Teams participated in various National Events. Two officials of the Department participated in the World Bench Press Powerlifting Tournament held at Cleveland, U.S.A., during 2nd to 5th December, 2004.

चिकित्सा

13.15 कल्याण स्कीम के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों में डाक विभाग द्वारा 48 शहरों/कस्बों में लगभग 56 डाक औषधालय चलाए जा रहे हैं। डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी और पेंशनभोगी डाक औषधालयों की सुविधा, जहां भी उपलब्ध हो, का लाभ उठाने के पात्र हैं। पात्र लाभार्थियों को इन औषधालयों से आउटडोर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है। 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार 2,27,000 लाभार्थियों को कवर करने वाले लगभग 56,000 कार्डधारक हैं जिसमें कर्मचारियों तथा पेंशनरों सहित उन पर आश्रित उनके परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं। सेवारत कर्मचारियों को यह सुविधा सी एस (एमए) नियम के एवज में, बिना किसी शुल्क/अंशदान के प्रदान की जाती है जबकि पेंशनरों से 9/- रु. प्रति माह का नाममात्र का अंशदान लिया जाता है। ये औषधालय भारत सरकार के परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी अपना योगदान देते हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान इन औषधालयों पर लगभग 212 मिलियन रुपये खर्च किए गए। अन्य स्थानों पर जहां डाक औषधालय मौजूद नहीं हैं, वहां विभाग के कर्मचारी के.स.स्वा.यो. (सीजीएचएस) औषधालयों या प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंटों की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

डाक विभाग में भवन निर्माण

13.16 वर्ष के दौरान, 29 डाकघर भवन, 4 प्रशासनिक कार्यालय भवन और 16 कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

समाचार पत्र

13.17 महानिदेशक के समाचार पत्र जिसमें विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा नीतिगत निर्णयों से संबंधित सूचना मौजूद होती है, का डाक भवन, नई दिल्ली से तिमाही आधार पर प्रकाशन किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

13.18 वर्ष के दौरान (क) केरल, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल सर्किल (ख) निदेशक डाक लेखा का कार्यालय, बेंगलूर (ग) पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, कोच्चि; (घ) डाक प्रशिक्षण केंद्र मैसूर; (ङ) मेल मोटर सेवा एर्नाकुलम; (च) सेवा अधीक्षक, डाकघर, अमृतसर के कार्यालय के आरक्षण रोस्टर्स का निरीक्षण

किया गया तथा उनमें पाई गई कमियों/चूक का निपटान सर्किल द्वारा किया गया। अनु.जाति/अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी विभाग के सेवारत कर्मचारियों के बारे में सांख्यिकीय सूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को दी गई। एससीटी सेल के दल ने भी सर्किल द्वारा बनाए गए शिकायत रजिस्टर की जांच की। सर्किलों को सभी लंबित शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया। सर्किलों की विभागीय पदोन्नति समिति संरचना की समीक्षा की जांच की गई तथा पाया गया कि नियमों के अधीन यथापेक्षित बहुत से सर्किलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को भी शामिल किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व

13.19 31.03.2005 तक विभाग में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति के 44,765, अनुसूचित जनजाति के 16774, भूतपूर्व सैनिक 1,963, विकलांग भूतपूर्व सैनिक 52 तथा 31,800 महिला कर्मचारी हैं (देखें तालिका 15 व 16)।

कार्य-अध्ययन

13.20 वर्ष के दौरान (क) मेघदूत लोकल एरिया नेटवर्क का महाराष्ट्र और कर्नाटक सर्किल में (ख) वीएसएटी का हरियाणा और आंध्र प्रदेश सर्किल में मानदंड तैयार करने संबंधी अध्ययन किए गए। कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्र (सी आर सी) के मानदंड तैयार करने संबंधी कार्य-अध्ययन भी पूरा किया गया। इसके अलावा, कार्पोरेट प्लानिंग, एसटीटी, डी (मेल), जीडीएस, लागत निर्धारण एवं दरें, डीए और सीएफ अनुभागों के कार्य आकलन संबंधी अध्ययन भी जारी किए गए।

राजभाषा

13.21 केन्द्र सरकार की नीति के अनुसरण में विभाग, सरकारी पत्राचार में हिन्दी के इष्टतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों तथा द्विभाषी रूप या केवल हिन्दी में जारी होने वाले सभी अपेक्षित दस्तावेजों के अनुवाद का दायित्व राजभाषा शाखा पर है।

13.22 वार्षिक रिपोर्ट, बजट, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठकों से संबंधित सामग्री, फिलैटलिक विवरणिकाओं व फिलैटलिक समाचार बुलेटिन, संसदीय

Medical

13.15 Under the Welfare Scheme, Department of Posts is running 56 Postal Dispensaries in 48 cities/towns in various parts of the country. These Dispensaries extend out door treatment facilities to the eligible beneficiaries. Employees as well as pensioners of Department of Posts and Department of Telecom are entitled to Postal Dispensary facilities, wherever such facilities are available. As on 31.03.2005 there are about 56,000 Card holders covering approximately 2,27,000 beneficiaries, which include the dependant family members of the employees as well as Pensioners. Serving employees are being provided these facilities free of cost/contribution in lieu of CS (MA) Rules but a nominal contribution of Rs. 9/- per month is being charged from the Pensioners. These Dispensaries also help in implementation of the family welfare programmes of the Government of India. During the year 2004-2005, an expenditure of about Rs. 212 Million was incurred on these dispensaries. In other places where Postal Dispensaries are not available, the employees of the Department can avail comprehensive health care facilities from CGHS Dispensaries wherever available or from the authorised medical attendant.

Postal Buildings

13.16 During the year, the construction of 29 post office buildings, 4 administrative office buildings and 16 staff quarters was completed.

Newsletter

13.17 Director General's Newsletter containing information relating to important activities of the Department as well as policy decisions is being published from Dak Bhawan, New Delhi on quarterly basis.

Scheduled Castes/Scheduled Tribes

13.18 The reservation rosters in respect of a). Kerala, Karnataka, Punjab and West Bengal Circles; b). Office of the Director of Accounts, Bangalore; c). Postmaster General, Kochi; d). Postal Training Centre, Mysore; e). Mail Motor Service, Ernakulam; f). Office of the Supdt. Services of Post Offices, Amritsar were inspected during the year and the shortcomings/lapses noticed were settled by the Circles. Statistical information in respect of SC/

ST/OBC employees in service in the Department were supplied to DOP&T. The team of SCT Cell also checked the grievance register maintained by the Circles. The Circles were directed to settle all the pending grievances. A review of composition of the Departmental Promotion Committees (DPCs) of the Circles revealed that one Member belonging to SC/ST was also included in most of the Circles, as required under rules.

Representation of SC, ST, Ex-Serviceman and Women

13.19 As on 31.03.2005, there were 44,765 SC; 16,774 ST; 1,963 Ex-Servicemen, 52 Disabled Ex-servicemen and 31,800 Women employees in various grades in the Department (see Table 15 & 16).

Work Study

13.20 During the year the studies of evolution of norms of for (a) Meghdoot LAN in Maharashtra and Karnataka Circle (b) VSAT in Haryana and Andhra Pradesh Circle were conducted. The study of evolution of norms for CRC was also completed. Besides, the Work Measurement Study of Corporate Planning, STT, D(Mails), GDS, Costing & Rates, DA and CF sections were issued.

Official Language

13.21 In pursuance of the policy of the Central Government, the Department has been making sustained effort to ensure optimum use of Hindi in official correspondence. The Official Language Branch is responsible for the implementation of Official Languages Act, 1963 and the Rules made thereunder as well as translation of all kinds of documents required to be issued either in bilingual form or in Hindi only.

13.22 The translation of the Annual Report, Budget, material in connection with the meetings of the Standing Committee of the Ministry of Communications and IT, Philatelic Brochures/ Philatelic News Bulletin, Parliament Questions, Assurances, VIP references are some of the major works accomplished during the period under review. In addition to the translation work generated in the Postal Directorate, translation support has also been provided to the Business Development

प्रश्नों, आश्वासनों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भों आदि का अनुवाद कुछ ऐसे मुख्य कार्य हैं जिन्हें पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान पूरा किया गया। डाक निदेशालय में किए जाने वाले कार्यों के अनुवाद कार्य के अतिरिक्त विभाग के व्यवसाय विकास निदेशालय तथा डाक जीवन बीमा निदेशालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुवाद भी राजभाषा अनुभाग द्वारा ही किया जाता है।

13.23 विभाग के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुचारु रूप से मॉनीटर करने के लिए मुख्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं।

13.24 राजभाषा अनुभाग ने डाक विभाग के सभी अनुभागों, सर्किल मुख्यालयों तथा डाक विभाग के अन्य संबंधित कार्यालयों को राजभाषा अधिनियम तथा पुनरीक्षाधीन वर्ष में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुपालनार्थ जारी संबंधित नियमों एवं निर्देशों से भी अवगत कराया है।

13.25 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में डाक विभाग के सभी अनुभागों, सर्किल मुख्यालयों, डाक प्रशिक्षण केंद्रों, पोस्टल स्टॉफ कालेज, डाक जीवन बीमा निदेशालय तथा व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की पुनरीक्षा भी राजभाषा अनुभाग में की जाती है तथा जहां कहीं भी त्रुटियां पाई गईं उनमें सुधार लाने के लिए आवश्यक उचित उपाय किए गए।

13.26 राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की द्वितीय उप समिति भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को मॉनीटर करती है। अवधि के दौरान समिति ने तीन कार्यालयों का निरीक्षण किया।

13.27 राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में दिए निर्देशों का अनुपालन करते हुए सत्ताईस कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। अवधि के दौरान हिन्दी के सरकारी प्रयोग के संबंध में निदेशालय के 23 अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया।

13.28 दिनांक 14 सितंबर, 2004 को विभाग में हिन्दी दिवस आयोजित किया गया तथा 14 से 28 सितंबर, 2004 को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे गए। पखवाड़े के दौरान एक दो दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

जन शिकायतें

13.29 वर्ष 2004-05 के दौरान, विभाग में 9,89,060 जन

शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 9,25,041 मामलों का निपटान किया गया। वरीयता आधार पर शिकायतों का निवारण करने के लिए पूरे वर्ष उपाय किए गए हैं। डाक अदालत तथा पोस्ट फोरम की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

13.30 विभाग ने अपने ग्राहकों को डाकघर में आए बिना ही अपनी वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंडियापोस्ट.गवर्नमेंट.इन/एडमिनलॉगइन.एचटीएमएल) पर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है। शिकायतों के तीव्र निपटान के लिए इंडियापोस्ट.गॉव.इन/सीसीसी लॉगइन.एसपी पर ऑनलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करके उसकी सूचना ग्राहकों के ई-मेल पते पर भेज दी जाती है। वीआईपी से प्राप्त होने वाली शिकायत, उसके तीव्र निपटान तथा उनको भेजे जाने वाले जवाब को विभाग ऑन लाइन पर (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंडियापोस्ट.गॉव.इन)/वीआईपीलॉगइन.एसपी. पर प्रोसेस करता है।

13.31 डाकघर के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने, ग्राहकों को लेन-देन संबंधी मानदंडों से परिचित कराने तथा शिकायतों के निवारण के साथ में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नागरिक घोषणापत्र का क्रियान्वयन 5,513 से अधिक महत्वपूर्ण डाकघरों में किया गया है।

पदनाम में परिवर्तन

13.32 परीक्षा श्रेणी "घ" पद अर्थात् पैकर के पदनाम को (क) प्रशासनिक कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों (ख) विदेशी डाकघरों में क्रमशः चपरासी और डाक चपरासी में पुनः पदनामित किया गया।

स्थापना

13.33 01.12.2004 को श्री आर. गणेशन को बतौर सचिव (डाक) पदोन्नत किया गया। वर्ष 2004-05 के दौरान एक अधिकारी की पदोन्नति बतौर सदस्य के की गई। प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में दो अधिकारी, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में चार अधिकारियों को तथा दो अधिकारियों को पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। एसटीएस ग्रेड में ग्यारह अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। 56 समूह "ख" अधिकारियों को जेटीएस में पदोन्नत किया गया और सीएसई (मुख्य), 2003 के द्वारा चार भारतीय डाक सेवा समूह "क" परीक्षाधीन अधिकारियों को नियुक्त किया गया।

and Marketing Directorate and PLI Directorate of the Department.

13.23 In order to effectively monitor the progressive use of Hindi in the Offices of the Department, Official Language Implementation Committees are functioning in the headquarters as well as in all the Subordinate Offices.

13.24 OL Branch acquainted all the Sections of the Directorate, Circle Headquarters and other concerned Offices of the Department of Posts with the OL Act, Rules and instructions issued thereunder for their compliance for achieving the targets fixed by the Department of Official Language in their Annual Programme for the year under review.

13.25 The Quarterly Progress Reports received from all the Sections of the Directorate, Circle Headquarters, Postal Training Centres, Postal Staff College, PLI Directorate and Business Development & Marketing Directorate regarding the progressive use of Hindi was also reviewed by the OL Branch and necessary corrective measures were taken in respect of the discrepancies noticed.

13.26 The Second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language also monitors the implementation of Official Language Policy. During the period, the Committee inspected three offices.

13.27 In pursuance of the directives laid down in the annual programme 2004-05 issued by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), twenty-seven offices were inspected. 23 Sections of the Directorate have also been inspected in connection with the official use of Hindi during the period.

13.28 Hindi Diwas was observed in the Department on 14th September, 2004 and Hindi Fortnight was observed from 14th to 28th September, 2004. Prizes were distributed to the winners of various competitions held during the Hindi Fortnight. A two-day Hindi Workshop was also organised during the fortnight.

Public Grievances

13.29 During the year 2004-2005, the Department

handled 9,89,060 cases of public grievances and a total of 9,25,041 cases were settled during the same period. Measures to resolve grievances on priority basis continued throughout the year. Quarterly meetings of Dak Adalat and Post Forum were held.

13.30 The Department has offered its valued customers the facility to register complaints on-line on our Web site (www.indiapost.govt.in/adminlogin.html), without visiting any post office. Further they also got their reply on their e-mail address. In order to settle all complaints expeditiously by processing them on-line, the Department has started handling of complaints on-line (www.indiapost.govt.in/cccllogin.asp). In the interest of handling VIP cases on-line for their prompt settlement, the Department has started processing VIP cases on-line (www.indiapost.govt.in/viplogin.asp).

13.31 With a view to sensitize the staff of post offices, orient the customers about norms of transactions and redressal of grievances as well as obligations on their part for improving the quality of service, the implementation of Citizen's Charter has been carried out in more than 5,513 important post offices.

Change in Designation

13.32 The designation of the test category 'D' Post i.e. Packer in (a) Administrative Offices and Subordinate Offices (b) Foreign Post Offices has been re-designated as Peon and Mail Peon respectively.

Establishment

13.33 Shri R. Ganesan was promoted as Secretary (Posts) on 01.12.2004. During 2004-05, One Officer was promoted to the post of Member. Two Officers were promoted in the grade of Principal Chief Postmaster General, Four Officers were promoted in the grade of Chief Postmaster General, and Two Officers were promoted in the grade of Postmaster General. Eleven Officers were given promotion in STS grade. 56 Group 'B' Officers were promoted to JTS and Four Indian Postal Service Group 'A' Probationers have been appointed through CSE (Main), 2003.

अध्याय 14

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलाप

14.1 भारतीय डाक ने, सरकार के नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के लिए विशेष पहल की है।

14.2 पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल एक डाक सर्किल द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। तथापि, इस क्षेत्र के सामरिक महत्व पर विचार करते हुए एवं विकासात्मक कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से तत्कालीन सर्किल को दो स्वतंत्र डाक सर्किलों में विभाजित कर दिया गया। इसमें एक असम सर्किल है जो असम राज्य के साथ कोटमिनस है तथा दूसरा पूर्वोत्तर डाक सर्किल है, जिसमें छः राज्य-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम का कुछ भाग आते हैं। हर सर्किल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

14.3 असम डाक सर्किल में 4,008 डाकघर हैं, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। प्रत्येक डाकघर औसतन 6647 की जनसंख्या को तथा 19.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। पूर्वोत्तर डाक सर्किल का मुख्यालय शिलांग में है और इसके अधिकार क्षेत्र में कुल 2945 डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर औसतन क्रमशः 58.45 वर्ग किलोमीटर और 3,885 की जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराता है।

योजना कार्यकलाप

14.4 पिछले वर्षों में शुरु किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों को दसवीं योजना के दौरान जारी रखा गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान समूचे देश भर में योजना कार्यकलापों पर किए गए कुल व्यय के दृष्टिगत पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया व्यय निम्नवत् है :

तालिका 12 पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनागत व्यय (मिलियन रु. में)			
वार्षिक योजना	अखिल भारतीय	पूर्वोत्तर में व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2002-03	459.10	25.30	5.51%
2003-04	633.04	39.13	6.18%
2004-05	1421.60	42.40	2.98%

14.5 मानव संसाधन विकास हेतु प्रौद्योगिकी के समावेश से उत्पन्न आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राहकोन्मुख सेवाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को विभिन्न

क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:-

Chapter 14

DEVELOPMENT ACTIVITIES IN NORTH-EASTERN REGION

14.1 India Post has taken up special initiatives for developmental activities in the North-Eastern Region, in accordance with the policy guidelines of the Government.

14.2 The North Eastern Region was previously served only by one Postal Circle. However, considering the strategic importance of the region, and to ensure focussed attention on developmental activities, the erstwhile Circle was bifurcated into two independent Postal Circles namely – Assam Circle, co-terminus with the State of Assam, and the North-Eastern Postal Circle, covering the six states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and some part of Sikkim. Each Circle is under the administrative control of a Chief Postmaster General.

14.3 Assam Postal Circle, with its headquarters at Guwahati, has a network of 4,008 Post Offices. On an average, each Post Office serves a population of 6,647 persons and an area of 19.56 Sq. Kms. North-Eastern Postal Circle has its headquarters at Shillong. It has within its jurisdiction a total of 2,945 Post Offices. On an average, each Post Office serves an area and population of 58.45 Sq. Kms. and 3885 persons respectively.

Plan Activities

14.4 The developmental programmes initiated in previous years were continued in the Tenth Plan. The expenditure in the North-Eastern region vis-a-vis the total expenditure on plan activities throughout the country during the last three years is given below: -

Table 12			
PLAN EXPENDITURE IN NORTH EASTERN REGION			
(Rs. in Million)			
Annual Plan	All India	Expenditure in North-East	% age over total expenditure
2002-03	459.10	25.30	5.51%
2003-04	633.04	39.13	6.18%
2004-05	1421.60	42.40	2.98%

14.5 In order to develop human resources, in line with emerging needs of technology induction and provision of customer centric services, officials in the North

Eastern Region were imparted training in various fields. The details are as given below:

तालिका 13						
क्र. सं.	राज्य	समूह 'क' और 'ख' कर्मचारियों को प्रशिक्षण	समूह "ग" कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण	कंप्यूटर प्रशिक्षण	डाकिए के लिए प्रशिक्षण	ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के लिए प्रशिक्षण
1.	असम	8	81	373	215	595
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	7	37	10	36
3.	मणिपुर	-	11	39	37	70
4.	मेघालय	-	16	67	14	65
5.	मिजोरम	-	4	62	10	25
6.	नागालैंड	-	9	53	8	24
7.	त्रिपुरा	-	19	99	20	80

14.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में 2004-05 के दौरान की गई अन्य मुख्य विकास गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

असम

14.7 वर्ष के दौरान 5 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालय, 110 डाकघर/प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 4 स्पीड पोस्ट केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया गया। गुवाहाटी में डाक लेखा कार्यालय का भी कम्प्यूटरीकृत किया गया, तीन फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं और 2 यूनिटों को औजार एवं उपस्कर प्रदान किए गए। इसके अलावा, निम्नलिखित फिलैटलिक कार्यक्रम भी किए गए :-

- 5 डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिताएं;
- 5 फिलैटलिक कार्यशालाएं;
- 2 फिलैटलिक समारोह और 2 संगोष्ठियां;

राज्य में वर्ष के दौरान 1 डाकघर भवन तथा 14 कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

अरुणाचल प्रदेश

14.8 वर्ष के दौरान, 5 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों, 12 डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और 2 स्पीड पोस्ट केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया गया। ट्रैक एवं ट्रेस

स्पीड नेट वाले दो स्पीड पोस्ट केन्द्रों का स्पीड पोस्ट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उन्नयन किया गया।

मणिपुर

14.9 वर्ष के दौरान, 6 डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। 9 शाखा डाकघरों को ढांचागत उपस्कर प्रदान किए गए। इसके अलावा 5 फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

मेघालय

14.10 वर्ष के दौरान, शिलांग में 3 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों, 12 डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों, शिलांग में एक डाक लेखा कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया। एक स्पीड पोस्ट केन्द्र का आधुनिकीकरण और स्पीड पोस्ट व्यवसाय बढ़ाने के लिए ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले दो केन्द्रों का उन्नयन किया गया। इसके अलावा, क्षेत्र में फिलैटलिक कार्यक्रम बढ़ाने के लिए 5 डाक-टिकट डिजाइनिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

मिजोरम

14.11 वर्ष के दौरान, 5 डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, एक स्पीड पोस्ट केन्द्र का आधुनिकीकरण, स्पीड पोस्ट व्यवसाय बढ़ाने के लिए ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले चार केन्द्रों का उन्नयन किया गया। इसके अलावा, क्षेत्र में फिलैटलिक

Table 13

S. No.	State	Training to Group 'A' & 'B' officials	In-Service Training to Group 'C' Officials	Computer Training	Training For Post man	Training for GDSBPMs
1.	Assam	8	81	373	215	595
2.	Arunchal Pradesh	- -	7	37	10	36
3.	Manipur	- -	11	39	37	70
4.	Meghalaya	- -	16	67	14	65
5.	Mizoram	- -	4	62	10	25
6.	Nagaland	- -	9	53	8	24
7.	Tripura	- -	19	99	20	80

14.6 The other major developmental activities undertaken during 2004-05 in each of the States of the North Eastern Region are given below:-

Assam

14.7 During the year 5 Speed Post booking/delivery offices, 110 Post Offices/Administrative Offices were computerized and 4 Speed Post Centres were modernised. The Postal Accounts Offices at Guwahati has also been computerised. Three Philatelic Exhibitions were held and 2 Units were provided with tools and equipments. Further, the following philatelic activities were also undertaken:-

- 5 Stamp Designing Competitions;
- 5 Philatelic Workshops;
- 2 Philatelic Festivals and 2 Seminars;

Construction of 1 Post Office building and 14 staff quarters was completed during the year in the State.

Arunachal Pradesh

14.8 During the year, 5 Speed Post booking/delivery offices, 12 Post Offices/Administrative Offices were computerized and 2 Speed Post Centres were modernised. Two Speed Post Centres were upgraded

with Track and Trace on Speed net to promote Speed Post facilities.

Manipur

14.9 During the year, 6 Post Offices/Administrative Offices were computerized. 9 Branch Post Offices were provided with infrastructural equipment. Further, 5 Philatelic Exhibitions were also held.

Meghalaya

14.10 During the year, 3 Speed Post booking/delivery offices, 12 Post Offices/Administrative Offices, one Postal Accounts Office in Shillong were computerized, one Speed Post Centre was modernized, two Centres were upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post business. Further, 5 Stamp Designing Competitions were also held to promote philatelic activities in the area.

Mizoram

14.11 During the year, 5 Post Offices/Administrative Offices were computerized, one Speed Post Centre was modernized, four Speed Post Centres were upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post business. Further, 5 Stamp Designing Competitions were also held to promote philatelic activities in the area.

कार्यकलाप बढ़ाने के लिए 5 डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान एक डाकघर पुनर्स्थापन द्वारा खोला गया।

नागालैंड

14.12 वर्ष के दौरान, 5 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों, 7 डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, एक स्पीड पोस्ट केन्द्र का आधुनिकीकरण और स्पीड पोस्ट व्यवसाय बढ़ाने के लिए ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले दो स्पीड पोस्ट केन्द्रों का उन्नयन किया गया। इसके अलावा, क्षेत्र में फिलैटलिक कार्यकलाप बढ़ाने के लिए एक संगोष्ठी तथा एक समारोह का आयोजन किया गया।

त्रिपुरा

14.13 वर्ष के दौरान, 13 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों, 23 डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, एक स्पीड पोस्ट केन्द्र का आधुनिकीकरण, स्पीड पोस्ट व्यवसाय बढ़ाने के लिए ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले दो स्पीड पोस्ट केन्द्रों का उन्नयन किया गया। इसके अलावा, क्षेत्र में फिलैटलिक कार्यकलाप बढ़ाने के लिए 5 फिलैटलिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान दो डाकघर पुनर्स्थापन द्वारा खोले गए।

सिक्किम

14.14 वर्ष के दौरान एक डाकघर का कम्प्यूटरीकरण किया गया तथा 5 फिलैटलिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

One Post Office has been opened by relocation during the year.

Nagaland

14.12 During the year, 5 Speed Post booking/delivery offices, 7 Post Offices/Administrative Offices were computerized, one Speed Post Centre was modernized, and two Speed Post Centres were upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post business. Further, one Seminar and one festival were also held to promote philatelic activities in the area.

Tripura

14.13 During the year, 13 Speed Post booking/delivery Offices, 23 Post Offices/Administrative Offices were computerized, one Speed Post Centre was modernised and two Speed Post Centres were upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post business. Further, 5 philatelic workshops were also held to promote philatelic activities in the area. Two Post Offices have been opened by relocation during the year.

Sikkim

14.14 During the year, 1 Post Office was computerized. Further 5 philatelic workshops were held.



डा. उ. श्रीनिवासराघवन द्वारा 17 अप्रैल, 2005 को चेन्नई में लॉजिस्टिक पोस्ट का शुभारम्भ।
Launch of Logistics Post on 17-April, 2005 by Dr. U. Srinivasa Raghvan at Chennai.

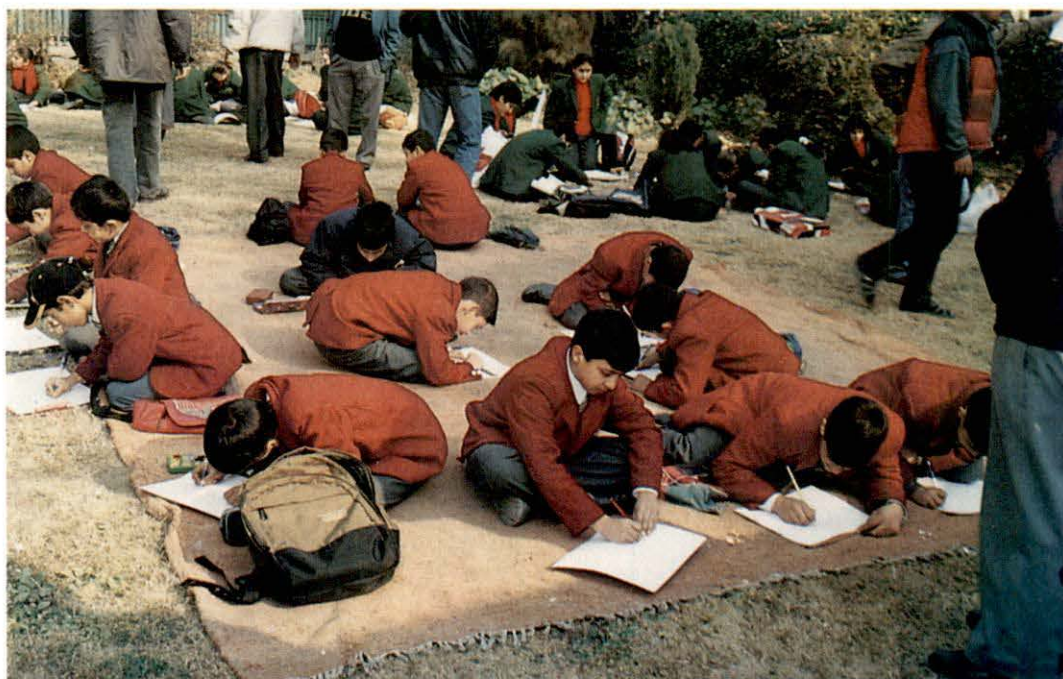


डाक भवन, नई दिल्ली में हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह-2005।
Hindi Fortnight Prize Distribution Function -2005 at Dak Bhavan, New Delhi.



लुधियाना (पंजाब सर्किल) में अक्टूबर, 2005 के दौरान आयोजित 19वां अखिल भारतीय डाक बास्केटबॉल टूर्नामेंट।

19th All India Postal Basketball Tournament held at Ludhiana (Punjab Circle) during October, 2005.



जम्मू एवं कश्मीर सर्किल में आयोजित ऑन द स्पॉट डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिता।

On the spot Stamp Design Competition in Jammu and Kashmir Circle.

भाग - II

कार्यकलाप

(अप्रैल-दिसम्बर 2005)

डाक नेटवर्क का विस्तार

1.1 इस अवधि के दौरान, 10वी. योजना के अंतर्गत नीतिगत पहल के अनुरूप, डाक नेटवर्क के यौक्तिकीकरण और सुधार के लिए प्रयास किए गए। तदनुसार, जब भी आवश्यक समझा गया, अनुमोदित नीति के अनुसार, डाक सेवाओं की पहुंच को कम किए बिना मानवशक्ति और संसाधनों की पुनर्तैनाती द्वारा नेटवर्क का विस्तार किया गया। वर्ष 2005-06 में, दिसंबर तक, विभिन्न सर्किलों में 86 डाकघरों का विलय किया गया और 69 डाकघर पुनः अवस्थित किए गए।

मेल प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण

1.2 वर्ष 2005-06 के दौरान, 12 मिलियन रुपये और 26.6 मिलियन रुपये के वित्तीय परिव्यय से क्रमशः 18 प्रधान रिकार्ड कार्यालयों और 34 पंजीकरण छंटाई केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य है। 0.5 मिलियन रुपये के कुल परिव्यय वाले 4 मेल कार्यालयों का भी आधुनिकीकरण (एगोनोमिक्स में सुधार) किया जाना है।

मेल मोटर सेवा

1.3 मेल मोटर सेवा, मुंबई यूनिट के पास कुल 175 वाहन हैं। इनमें से अधिकतर हल्के व्यवसायिक वाहन (एल सी वी) हैं। इन वाहनों को कंप्रेसर नैचुरल गैस (सी एन जी) पर चलाने के अभियान के अंतर्गत इस वर्ष स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाहनों को बढ़ाकर 111 कर दिया गया है। इस प्रकार, देश में, डाक विभाग सी एन जी पर चलने वाले एल सी वी वाहनों को सबसे अधिक संख्या में रखने वालों में से एक है।

फिलैटली

1.4 इस अवधि के दौरान, 31 स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए गए हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सुन्दर डाक-टिकटों में कुछ का उल्लेख इस प्रकार है, डांडी मार्च (मिनियेचर शीट सहित), बांडुंग सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस (हरित शहर), भारतीय स्टेट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, लेटर बॉक्स (मिनियेचर शीट सहित),

सूचना समिति पर विश्व सम्मेलन, कोलकाता पुलिस कमिश्नरी, भारत में नवजात शिशु स्वास्थ्य। नई दिल्ली में 17 मई, 2005 को फिलैटली सलाहकार समिति (पीएसी) की एक बैठक आयोजित की गई। विचार-विमर्श और सुझावों के आधार पर वर्ष 2005-06 के दौरान, डाक-टिकट जारी करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 18 जुलाई, 2005 को चेन्नई में सर्किल प्रमुखों के सम्मेलन में एक नया 220 X 110 (ए-4 साइज के कागज के लिए) उत्कीर्ण लिफाफा प्रारंभ किया गया। 18 जुलाई, 2005 को सर्किल प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने डाकिए के माध्यम से बेची जाने वाली 100/200 रु. की डाक-टिकटों के स्टाम्प पाउच का भी शुभारंभ किया। भारत की पत्र-पेटियों पर चार डाक-टिकटों के एक सेट के साथ, 18 अक्टूबर, 2005 को, भारतीय डाक के 150 वर्षों के समापन समारोह में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा आधुनिक भारतीय डाक के प्रतिबिम्ब का प्रतीक दर्शाने के लिए एक विशेष डिजाइन वाली उत्कीर्ण डाक-टिकट के साथ एक सफेद ए-4 साइज लिफाफा प्रारंभ किया गया। डाक-टिकटों के सेट को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष प्रस्तुतीकरण फोल्डर भी जारी किया गया।

1.5 इस अवधि के दौरान, पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। गंगटोक (गंगटोक '05) और कोलकाता (स्टांप शो '05) में सर्किल स्तर तथा मसूरी में (हिमालयन एडवेंचर '05) और तांबरम (तांमपेक्स '05) में कुछ क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। इसके अलावा जिला स्तर और डिवीजनल स्तर पर पूरे देश में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। भारतीय डाक ने 19 से 24 अगस्त, 2005 तक ताईपे में आयोजित 'ताईपे 2005' अंतर्राष्ट्रीय फिलैटलिक प्रदर्शनी में भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय डाक-सेवा गुणवत्ता निधि के न्यासी बोर्ड का एक सदस्य

1.6 सचिव (डाक) और उप महानिदेशक (आईआर) ने टोक्यो, जापान में 5 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2005 तक सेवा गुणवत्ता निधि (क्यू



PART-II

ACTIVITIES

(April - December 2005)

Expansion of Postal Network

1.1 During the period, efforts were made to rationalise and right size the postal network in consonance with the policy initiatives under the 10th Plan. Accordingly, the network was expanded whenever essential by redeploying manpower and resources without reducing the access to postal services, as per approved policy. This right sizing is a continuing process. In 2005-06 in various Circles, up to December, 86 Post Offices were merged and 69 Post Offices were relocated.

Computerization and Modernization of Mail Operations

1.2 During the year 2005-06, 18 Head Record Offices and 34 Registration Sorting Centres with financial outlay of Rs. 12 Million and Rs. 26.6 Million respectively are targeted to be computerized. Also 4 Mail Offices are to be modernized (improving ergonomics) with a total financial outlay of Rs. 0.5 Million.

Mail Motor Service

1.3 The Mail Motor Service, Mumbai Unit has a fleet strength of 175 vehicles. Majority of these vehicles are Light Commercial Vehicles (LCVs). In a drive to operate these vehicles on Compressed Natural Gas (CNG), this year number of vehicles operated on clean fuel has been increased to 111. Thus Department of Posts maintains one of the biggest fleet of CNG propelled LCVs in the country.

PHILATELY

1.4 During the period, 31 issues comprising of commemorative/special postage stamps have been issued. Among the more significant and beautiful stamps issued, mention may be made of sets on Dandi March (with miniature sheet), Bandung Conference, World Environment Day (Green Cities), State Bank of India,

International Day of Peace, Letter boxes (with miniature sheet), World Summit on the Information Society, Kolkata Police Commissionerate and New born Health in India. A meeting of the Philatelic Advisory Committee (PAC) was held on 17th May, 2005 at New Delhi. Based on the discussions and recommendations a programme for release of stamps during 2005-06 was decided. A new 220 x 110 embossed envelope (for A-4 size paper) was launched at the Heads of Circles Conference in Chennai by the Hon'ble MOC&IT on 18th July, 2005. In course of the Heads of Circles Conference on 18th July, 2005, the Hon'ble MOC&IT also launched a Stamp Pouch containing stamps amounting to Rs. 100/200 to be sold through Postmen. A white A-4 size envelope with a specially designed embossed postage symbolizing modern India Post brand image was launched by Hon'ble MOC&IT, in the concluding function of the sesquicentennial celebrations of India Post on 18th October, 2005, along with a set of four stamps on Letter Boxes of India. A special presentation folder to showcase the set of stamps was also released.

1.5 Philatelic Exhibitions were held at different levels around the country during the period. Circle level exhibitions were held in Gangtok (Gangtok'05) and Kolkata (Stampshow'05) and some of the regional level exhibitions were held in Mussourie (Himalayan Adventure'05) and Tambaram (Tampex'05). Besides, district level and divisional level, exhibitions were also held all over the country. India Post participated in the 'Taipei 2005' International Philatelic Exhibition held at Taipei from 19th – 24th August, 2005.

INTERNATIONAL RELATIONS

India Post – a Member of Quality of Service Fund Board of Trustees

1.6 Secretary (Posts) and Deputy Director General (IR) attended the meeting of the Board of Trustees (BoT) of Quality of Service Fund (QSF) held in Tokyo, Japan

एस एफ) के न्यासी बोर्ड (बी ओ टी) की बैठक में भाग लिया। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नौ निर्वाचित सदस्यों वाला न्यासी बोर्ड क्यू एस एफ का कार्यभार संभालता है। विकासशील एवं कम विकसित देशों में डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लक्ष्य से 1999 में, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सेवा के 22वें सम्मेलन द्वारा सेवा गुणवत्ता निधि की स्थापना की गई थी। भारतीय डाक की मेजबानी में बी ओ टी की अगली बैठक 20 से 22 जुलाई, 2005 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

1.7 क्षेत्र में अग्रणी डाक प्रशासन और सेवा गुणवत्ता निधि के न्यासी बोर्ड के सदस्य के तौर पर भारतीय डाक ने 18 जुलाई से 20 जुलाई, 2005 तक नई दिल्ली में यूपीयू की सेवा गुणवत्ता निधि पर एक कार्यशाला और एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए टर्मिनल शुल्क की नई प्रणाली का आयोजन किया। कार्यशाला का लक्ष्य एशियाई प्रशांत देशों के भागीदारों को सेवा गुणवत्ता निधि में बदलाव की प्रक्रियाओं और टर्मिनल शुल्क के लिए नई लेखादेय प्रक्रियाओं के साथ अवगत कराना है जो 1 जनवरी, 2006 से लागू हुए हैं। इस कार्यशाला में करीब 20 देशों से 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारतीय डाक और जापान डाक ने संयुक्त रूप से विकासशील देशों के सभी प्रतिभागियों को फैलोशिप प्रदान की।

एशिया-प्रशांत डाक यूनियन

1.8 सिओल, कोरिया में 30 मई से 4 जून, 2005 तक एशिया प्रशांत डाक यूनियन (एपीपीयू) के 9वें सम्मेलन में सचिव (डाक), उप महानिदेशक (आई आर) और सहायक महानिदेशक (आई आर) के तीन सदस्यों वाले प्रतिनिधि-मंडल ने भाग लिया। एपीपीयू एक सीमित प्रकार की यूनियन है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से सम्बद्ध है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। एपीपीयू के भारत सहित 29 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच डाक सेवाओं में सहयोग बढ़ाना है।

एशिया प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड (एपीपीसीएमबी)

1.9 एपीपीयू के कार्यों में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एशिया प्रशांत डाक प्रशिक्षण केन्द्र और एपीपीसीएमबी के शासी निकाय का सदस्य होने के अलावा, भारत तकनीकी सहायता और सेवा गुणवत्ता पर एपीपीयू स्थायी समिति का अध्यक्ष है। एपीपीयू कांग्रेस, जो प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित

की जाती है, में भारत एपीपीयू कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। यह निकाय दोनों कांग्रेसों के बीच कार्य करता है और एपीपीयू के कार्य प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

परियोजनाएं

1.10 विभाग ने ढाका, काठमांडू और यनगांव में जनरल डाकघरों में डाकघर काउंटरों को कंप्यूटरीकृत करने की परियोजना का भार अपने ऊपर लिया। ये परियोजनाएं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मल्टी ईयर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ली गई जिसमें यूनियन द्वारा फंड प्रदान किए गए। कंप्यूटरीकरण और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारतीय डाक की कार्यक्षमता को पहचानते हुए इन कार्यकलापों को यूपीयू द्वारा लिया गया। ये परियोजनाएं जनवरी, 2004 में प्रारंभ की गईं और इसे तीन चरणों में बांटा गया। पहला चरण साइट सर्वेक्षण और सिस्टम अध्ययन से संबंधित था जबकि दूसरा सॉफ्टवेयर संस्थापन और संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित था। तीसरे और अंतिम चरण में संस्थापन की पुनरीक्षा एवं जांच शामिल हैं तृतीय और अंतिम चरण के लिए देश में भारतीय टीम के दौरे के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

1.11 भारतीय डाक ने भी अगस्त, 2005 में मालदीव में चार डाकघरों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को पूरा कर लिया है। यह परियोजना डाक विभाग और टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टैन्ट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2003 में संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। यू एस \$ 75,000/- की यह परियोजना 65:35 के अनुपात से विदेश मंत्रालय और मालदीव डाक द्वारा निधिबद्ध की गई। इस परियोजना में मुख्यतः भारतीय डाक द्वारा विकसित मेघदूत सॉफ्टवेयर का ग्राहकोनुकूल और संस्थापन शामिल था।

प्रतिनिधिमण्डल

1.12 सचिव (डाक), उप महानिदेशक (आई आर) और निदेशक (प्रौद्योगिकी) के तीन-सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ने पेरिस में 3 से 5 अक्टूबर, 2005 तक आयोजित विश्व डाक व्यवसाय फोरम और पोस्ट एक्सपो 2005 में भाग लिया। सचिव (डाक) ने अध्यक्ष, लॉ पोस्ट, फ्रांस से भी भेंट की और आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया।

1.13 सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड, उप महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और सहायक महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय मेल)

from 05th to 08th April, 2005. The Board of Trustees comprising nine elected members from different geographical regions manages the work of QSF. India is an elected member of the Board of Trustees. The Quality of Service Fund was set up by 22nd Congress of Universal Postal Union, a specialized agency of the United Nations, in 1999, with the aim of improving the quality of postal services in developing and least developed countries. The next meeting of the BoT was hosted by India Post in New Delhi from 20th to 22nd July, 2005.

1.7. As a leading postal administration in the region and as a member of the Board of Trustees of the Quality of Service Fund, India Post organized a workshop on Quality of Service Fund of the UPU and new system of Terminal Dues for the Asia Pacific region from 18th to 20th July, 2005 in New Delhi. The aim of the workshop was to familiarize participants from the Asia Pacific countries with the changes in the Quality of Service Fund procedures and with the new accounting procedures for Terminal Dues that became applicable from 1st January, 2006. As many as 28 participants from 20 countries participated in the workshop. India Post and Japan Post jointly granted fellowships to all participants from least developed countries.

Asia – Pacific Postal Union

1.8 A three member delegation comprising Secretary (Posts), Deputy Director General (IR) and Assistant Director General (IR) participated in the 9th Congress of Asia Pacific Postal Union (APPU) held in Seoul, Korea from 30th May to 4th June, 2005. The APPU is a restricted Union, which is affiliated to the Universal Postal Union, a specialized agency of the United Nations. The APPU, having a membership of 29 countries, including India, has been formed with the objective of promoting cooperation in postal services among member countries.

Asia-Pacific Post Cooperative Management Board (APPCMB)

1.9 India plays an active role in the affairs of APPU. Besides being a member of the Governing Board of the Asia Pacific Postal Training Centre and of the APPCMB, India is Chairing the APPU Standing

Committee on Technical Assistance and Quality of Service. During the APPU Congress which is held every four years, India was elected the Vice-Chair of the APPU Executive Council, a body which functions between two Congresses and is responsible for managing the affairs of the APPU.

Projects

1.10 The Department undertook projects for computerizing Post Office Counters at General Post Offices in Dhaka, Kathmandu and Yangon. The projects were taken under the Multi Year Integrated projects of the Universal Postal Union with funds provided by the Union. These activities were taken up by the UPU through India Post in recognition of its capabilities in the area of computerization and software development. The projects were started in January, 2004 and divided into three phases. The first phase related to site survey and system study while the second related to installation of software and imparting training to the concerned staff. Review and checking of installation and application comprise the third and final phase. The projects have successfully been completed in the current financial year with the visit of the India team to the country for the third and final phase.

1.11. India Post also completed the project of computerization of four Post Offices in Maldives in August, 2005. The project was started in 2003 jointly by the Department of Posts and Telecommunications Consultants India Limited. The project costing US \$ 75,000/-, was funded by Ministry of External Affairs and Maldives Post in the ratio 65:35. The project mainly involved customization and installation of the Meghdoot Software developed by India Post.

Delegations

1.12 A three-member delegation comprising Secretary (Posts), Deputy Director General (IR) and Director (Technology) attended the World Postal Business Forum and Post Expo 2005 held in Paris from 3rd to 5th October, 2005. Secretary (Posts) also met the Chairman, La Poste, France and discussed the various areas of mutual cooperation.

1.13 A three-member delegation comprising Member (Operations), Postal Services Board, Deputy

के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बर्न, स्विट्जरलैण्ड में 5 से 21 अक्टूबर, 2005 को प्रशासन परिषद के सत्र के दौरान आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की डाक प्रचालन परिषद की बैठक में भाग लिया। भारत 40 सदस्यों वाली डाक प्रचालन परिषद का सदस्य है और प्रचालन मामलों की समिति 3 का अध्यक्ष है। परिषद सभी सदस्य डाक प्रशासनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन के महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक, वाणिज्यिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। भारतीय डाक दो डाक प्रशासनों (दूसरा चीन है) में से एक है जिसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा भारत में डाक सेवाओं के विकास पर प्रस्तुति पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। सदस्य (प्रचालन) ने यह प्रस्तुति पेश की जिसकी खूब सराहना की गई।

1.14 सचिव (डाक) ने 14 से 18 नवम्बर, 2005 को आयोजित सूचना समिति पर विश्व सम्मेलन (डब्ल्यू एस आई एस) में भाग लेने के लिए ट्यूनिंस, ट्यूनिशिया का दौरा किया। सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी, व्यावसायिक तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठे होकर एक ऐसी सूचना समिति का निर्माण करने के लिए शामिल हुए जिसकी पहुंच सब तक हो। सचिव (डाक) ने भारतीय डाक तथा आई सी टी डिजिटल विभाजन को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण "क्षेत्रीय पोस्ट एण्ड आई सी टी : ए रीजनल अप्रोच टू ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड" विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

1.15 रॉयल मेल के श्री कार्ल गेरोल्ड मेंडे जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के ईएमएस सहकारी बोर्ड के भी सदस्य हैं, ने 21 से 24 जून, 2005 में भारत का दौरा किया। श्री मेंडे के साथ रायल मेल के उत्पाद ग्रुप के पार्सल फोर्स के श्री डेविड ग्रेगरी भी आए थे। प्रतिनिधिमंडल ने डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की तथा अंतर्राष्ट्रीय ई एम एस सेवा में सुधार लाने व यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के ई एम एस सहकारी बोर्ड की व्यवसाय योजना को कार्यान्वित करने पर विचार-विमर्श किया।

1.16 श्री रॉबर्ट लैंगटन, टर्मिनल शुल्क प्रबंधक, रॉयल मेल, ग्रेट ब्रिटेन ने 28 से 30 जुलाई, 2005 तक भारत का दौरा किया। भारत तथा ग्रेट ब्रिटेन ने टर्मिनल शुल्क पर नीतिगत प्रश्न कार्य दल के सह-अध्यक्ष (डब्ल्यू जी-13) के तौर पर चर्चा की। बैठक में कार्य आरंभ करने की योजना बनाने पर विचार विमर्श किया गया।

1.17 मंगोलिया डाक के एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25 अगस्त से 3 सितम्बर, 2005 तक भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने अपने देश में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण पर सहायता मांगी। भारतीय डाक ने काउंटर स्वचालन पर सहायता प्रदान करने की पेशकश इस तथ्य के मद्देनजर की, कि उसके पास इस प्रयोजन के लिए एक बहुत ही सुविकसित साफ्टवेयर है तथा उसने कई देशों में ऐसी परियोजनाएं स्थापित की हैं।

1.18 स्विस् पोस्ट से एक दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल श्री पीटर स्टूप तथा श्री थामस गट ने 13 से 15 सितम्बर, 2005 को भारत का दौरा किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों के विकास पर चर्चा की। उन्होंने रीडिजाइन मेल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट (आर ई एम ए) पर अपनी प्रस्तुति पेश की, जो अपने आप में स्विस् पोस्ट द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी व सबसे अधिक जटिल परियोजना है। उन्होंने भारत में, डाक मर्दों की प्रोसेसिंग, विशेष रूप से पत्र-डाक पर जानकारी प्राप्त की।

1.19 श्री एलन लेटन, अध्यक्ष, रायल मेल, ग्रेट ब्रिटेन ने 5 जनवरी, 2006 को भारत का दौरा किया। सचिव (डाक) से अपनी बैठक के दौरान दोनों डाक प्रशासनों के बीच सुधार एवं सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई।

टर्मिनल शुल्क परियोजना

1.20 भारतीय डाक ने 12-13 जनवरी, 2006 को जयपुर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के डाक प्रचालन परिषद के टर्मिनल शुल्क परियोजना दल (टीडीपीजी) की विषय-निर्वाचन समिति की बैठक आयोजित की टर्मिनल शुल्क परियोजना दल यूपीयू के डाक प्रचालन परिषद की एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से है तथा टर्मिनल शुल्क की एक नई प्रणाली तैयार की जा रही है। भारतीय डाक, ग्रेट ब्रिटेन के साथ टीडीपीजी के नीतिगत प्रश्न कार्यकारी दल में सह अध्यक्ष है। 12 देशों से 16 भागीदारों तथा यूपीयू ने बैठक में भाग लिया।

पत्र-लेखन प्रतियोगिता

1.21 डाक विभाग पिछले कई वर्षों से, स्कूली बच्चों की साहित्यिक सृजन में क्षमता बढ़ाने तथा संचार सुविधा उपलब्ध कराने में डाक विभाग की भूमिका से अवगत कराने के उद्देश्य से यूपीयू पत्र-लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में 8 जनवरी, 2006 को देशभर में 35वीं यूपीयू पत्र-लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

Director General (International Relations) and Assistant Director General (International Mails) attended the meeting of Postal Operations Council of Universal Postal Union held during the session of Council of Administration from 5th to 21st October, 2005 in Berne, Switzerland. India is a member of the 40 member Postal Operations Council (POC) and chairs Committee 3 on Operational Issues. The Council is responsible for important operational, commercial, economic and technical aspects of international postal operations among member postal administrations. India Post was one of the two postal administrations (the other being China) invited by the Universal Postal Union to make a presentation on the development of postal services in India. As such, Member (Operations) made a presentation that was received very well.

1.14 Secretary (Posts) visited Tunis, Tunisia to attend the World Summit on the Information Society (WSIS) held from 14th to 18th November, 2005. The Summit brought together international organizations, governments, businesses and civil society representatives involved in building an information society accessible to all. Secretary (Posts) made a presentation on the topic "India Post and ICTs: A regional approach to bridging the digital divide".

Visits of Foreign Delegations

1.15 Mr. Carl Gerold Mende of Royal Mail, who is also member of the EMS Cooperative Board of Universal Postal Union, visited India from 21st to 24th June, 2005. Mr. Mende was accompanied by Mr. David Gregory of Parcel Force, a product Group of Royal Mail. The delegation met with the senior offices of India Post and discussions were held for improvement of the international EMS Service and implementation of the Business Plan of the EMS Cooperative Board of the Universal Postal Union.

1.16 Mr. Robert Langton, Terminal Dues Manager, Royal Mail, Great Britain visited India from 28th to 30th July, 2005. India and Great Britain Co-Chair of Policy Questions Working Group (WG-13) on Terminal Dues. The meeting was held to plan the work being undertaken.

1.17 A two member delegation from Mongolia Post visited India from 25th August to 3rd September, 2005. The delegation sought assistance in modernisation of postal services in that country. India Post offered assistance in counter automation based on the fact that it has well developed software for the purpose and has undertaken similar projects in several countries.

1.18 A two-member delegation from Swiss Post comprising Mr. Peter Stoop and Mr. Thomas Gut visited India from 13th to 15th September, 2005. They discussed development of business activities between the two countries. They also made presentation on their 'Redesign Mail Processing (REMA) Project' which, purportedly, is the biggest and most complex project ever run by Swiss Post. They also familiarized themselves with the methods of processing postal items, mainly letter mail in India.

1.19 Mr. Allan Leighton, Chairman, Royal Mail, Great Britain visited India on 5th January, 2006. During his meetings with Secretary (Posts), various issues of reforms and cooperation between the two postal administrations were discussed.

Terminal Dues Project

1.20 India Post hosted the meeting of the Steering Committee of the Terminal Dues Project Group (TDPG) of the Postal Operations Council of the Universal Postal Union in Jaipur on 12th – 13th January, 2006. The Terminal Dues Project Group is one of the most important activities taken up by the Postal Operations Council of UPU and a new system of Terminal Dues is in the process of being evolved. India Post Co-Chairs the Working Group on Policy Questions within the TDPG along with Great Britain. 16 participants from 12 countries and UPU participated in the meeting.

Letter Writing Competition

1.21 Department of Posts has been conducting UPU Letter Writing Competition over the years in order to enhance the capability of school going children in literary composition and to improve their awareness about the role of Post Office in providing communication facilities. In this series 35th UPU letter-writing competition was held on 8th January, 2006 throughout the country.

प्रौद्योगिकी

1.22 952 उप डाकघरों के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा अन्य सहायक उपकरणों की खरीद के आदेश दे दिए गए हैं। वी-सैट के माध्यम से मनीआर्डर पारेषण औसत प्रतिदिन 50,000 से बढ़कर 70,000 हो गया है। कार्य वातावरण में सुधार करके प्रचालन/कार्यकारी प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना स्कीम के अंतर्गत 205 डाकघरों को कवर करने के लिए 41 मिलियन रु. की राशि जारी की गई है और 772 डाकघरों को नए उपकरणों की आपूर्ति करने के उद्देश्य से 19.3 मिलियन रु. की राशि जारी की गई है। वर्ष के दौरान 1000 उप डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है।

व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय

प्रचार एवं संवर्द्धन

1.23 प्रीमियम उत्पादों के संवर्द्धन के लिए बजटीय आबंटन में इस वर्ष पर्याप्त वृद्धि की गई है। वर्ष 2004-05 में 20 मिलियन की तुलना में यह 45 मिलियन रु. था। इस आबंटन को मुख्य विशिष्ट गतिविधियों/अभियानों सहित प्रचार व विपणन प्रयासों पर खर्च किया गया जो कि निम्नानुसार है :-

- भारत के युवाओं के मन में भारतीय डाक का महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के उद्देश्य से 'मेरा दोस्त इंडिया पोस्ट' नाम से सतत व केन्द्रीकृत अभियान चलाया गया। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 14 नवम्बर, 2005 को बाल दिवस के उपलक्ष्य पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका प्रचार भारत के सभी अग्रणी समाचार पत्रों में किया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर 16.12.2005, 23.12.2005 तथा 30.12.2005 को मुख्य समाचार पत्रों में आगे एक विज्ञापन और दिया गया। इसके जवाब में कुल 2174 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय डाक की 150वीं वर्षगांठ पर युवाओं को डाक सेवाओं से परिचित कराने के लिए देशभर के स्कूलों में डाक सेवाओं पर सर्वश्रेष्ठ कोलाज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला-2005 में डाक विभाग के पवेलियन का विमोचन 14 नवम्बर, 2005 को

माननीय राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा किया गया। पवेलियन का मूल विषय 'भावी डाक-माध्यम व संदेश' था। संचार विषय से संबंधित प्रस्तुतीकरण में सर्वश्रेष्ठता के लिए पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया।

- भारतीय डाक की 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह की मीडिया कवरेज का दायित्व व्यवसाय विकास तथा विपणन निदेशालय को दिया गया जिसे सभी प्रमुख टी. वी. चैनलों व अग्रणी समाचार पत्रों द्वारा कवर किया गया।
- भारतीय डाक की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जानकारी देने व एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने की भावना को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय डाक को लेकर एक ध्यानाकर्षक पंक्ति तथा लोगो पर आम जनता से सुझाव आमंत्रित करते हुए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो भारतीय डाक की यूएसपी और विशिष्ट प्रकृति को प्रदर्शित करता है।

सीधी डाक

1.24 एक नया उत्पाद सीधी डाक 2 जून, 2005 को शुरू की गई जो कि वस्तुतः कुछ चयनित उपभोक्ताओं को असंबोधित सीधी डाक है जिसके द्वारा उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। सीधी डाक सीधी मेल का असंबोधित भाग है तथा इसमें असंबोधित डाक मर्दे जैसे कि पत्र, कार्ड विवरणिकाएं, प्रश्नावलियां, पैम्फलेट्स, नमूने, प्रचार-प्रसार वाली मर्दे जैसे सीडी/फ्लापी, कैसेट इत्यादि, कूपन, पोस्टर, मेलर या मुद्रित संचार का कोई भी अन्य भाग सम्मिलित है जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 अथवा भारतीय डाकघर नियमावली 1933 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

1.25 सुश्री रैकल फेरारी, परियोजना प्रबंधक, सीधी मेल परामर्श बोर्ड (डीएमएबी) यूपीयू, ने भारत में सीधी मेल विपणन विकास पर एक यूपीयू कार्यशाला आयोजित कराने की तैयारी के संबंध में सितम्बर, 2005 के मास में भारतीय डाक का एक दौरा किया। मुम्बई एवं दिल्ली में डाक विभाग के अधिकारियों तथा सभी संबंधित व्यक्ति एवं संगठनों जैसे डायरेक्ट मेल संघ, मुद्रकों, विज्ञापन एजेंसियों, प्रकाशकों, इत्यादि के साथ बैठकें आयोजित की गईं। एक तीन दिवसीय सीधी मेल विपणन विकास कार्यशाला को 01 से 03 फरवरी, 2006 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

Technology

1.22 Orders have been placed for purchase of computer hardware and other peripherals for 952 Sub Post Offices. Money Order transmission through V-SAT increased on an average from 50,000 per day to 70,000 per day. Under the Plan Scheme of modernization of operative/working systems by improving ergonomics, funds amounting to Rs. 41 Million have been released to cover 205 Post Offices. Further, funds amounting to Rs. 19.3 Million have been released to cover 772 Post Offices for supply of new equipments. Another 1,000 Sub Post Offices are likely to be computerized during the year.

BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING DIRECTORATE

Publicity and Promotion

1.23 The budgetary allocation for promotion of premium products was considerably enhanced this year. It was Rs. 45 Million compared to Rs. 20 Million in 2004-05. The allocation was utilized in the year for publicity and marketing efforts, along with some major specific activities / campaigns, as follows :-

- To get an important share of the mind space of younger citizens of India for India Post, a sustained and focused campaign titled **"Mera Dost India Post"** was launched. A full-page colour advertisement on **"Mera Dost India Post"** was carried in all the leading national newspapers on 14th November, 2005 on the occasion of Children's Day, announcing a contest for children below 15 years of age. As a follow up, further advertisements were issued in the major newspapers on 16.12.2005, 23.12.2005 and 30.12.2005. A total of 2,174 entries were received in its response.
- In addition, a contest for the Best Collage on Postal Services by schools all over India was held to increase the familiarity of younger people with postal services in the Sesquicentennial Year of India Post.
- The IITF – 2005 pavilion on Department of Posts was inaugurated by Hon'ble

Minister of State (Communications & IT) on 14th November, 2005. The theme of the pavilion was "Future Post – Medium and the Message". The pavilion was awarded a Gold Medal for excellence in presentation of theme on communication.

- Business Development and Marketing Directorate was entrusted with the responsibility of media coverage of the Closing Function of Sesquicentennial Year of India Post, which was very well covered by the major TV Channels as well as by all the leading newspapers.
- To increase awareness in all walks of life about India Post, and to strengthen the sense of being an important stakeholder, a national competition was also held inviting suggestions from members of the public on a catch 'line and logo that reflects the USP and unique character of India Post.

Direct Post

1.24 A new product called "Direct Post" was introduced on 2nd June, 2005, which is basically unaddressed direct mail sent to select consumers to elicit a response from them. Direct Post is the unaddressed component of Direct Mail, and would comprise of unaddressed postal articles like letters, cards, brochures, questionnaires, pamphlets, samples, promotional items like CDs / floppies and cassettes, etc., coupons, posters, mailers or any other form of printed communication that is not prohibited by the Indian Post Office Act, 1898 or Indian Post Office Rules, 1933.

1.25 Ms. Raquel Ferrari, Project Manager, Direct Mail Advisor Board(DMAB), UPU made a preparatory visit to India Post in the month of September, 2005 in connection with organizing a UPU Workshop on Direct Mail Market Development in India. Meetings were held at Mumbai and Delhi with officers from the Department of Posts as well as with stakeholders like Direct Mail Association, printers, advertising agencies, publishers, etc. It has been decided to hold a three days Direct Mail Market Development Workshop from 1st – 3rd February, 2006.

कारपोरेट ई-पोस्ट

1.26 ई-पोस्ट का कारपोरेट संस्करण माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारतीय डाक के 150 वर्षों के समापन समारोह के दौरान 18 अक्टूबर, 2005 को शुरू किया गया। ई-पोस्ट के कारपोरेट संस्करण से निम्नलिखित संभव हो पाएगा:-

- एक साथ 9,999 पत्तों पर संदेश भेजना।
- प्रेषक के परिसर में संदेशों की स्कैनिंग। इससे कारपोरेट ग्राहक अपनी कार्यालय स्टेशनरी में संदेशों को तैयार एवं स्कैन करके अपने कम्प्यूटरों से भेज पाएंगे।

पिक-अप सेवा

1.27 डाकियों द्वारा पिक-अप सेवा का माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 17 एवं 18 जुलाई, 2005 को चेन्नई में सर्किल अध्यक्षों की गोष्ठी के दौरान शुभारंभ किया गया था। डाकिए पत्र वितरण के दौरान न केवल स्पीड-पोस्ट मर्दें बल्कि साधारण डाक भी एकत्रित करेंगे।

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा

1.28 स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा को सेना डाक सेवा के फील्ड डाकघरों (एफपीओ) तक विस्तारित किया गया।

ई-कॉमर्स

1.29 भारतीय उद्योग संघ ने भारतीय डाक की सहभागिता में होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में 22 जुलाई, 2005 को एक ई-बिजनेस गोष्ठी 2005 का आयोजन किया। इस गोष्ठी में देश में ई-कॉमर्स से संबंधित सभी मुख्य व्यक्तियों एवं संगठनों ने भाग लिया। विभाग इस गोष्ठी के आयोजन में काफी सक्रियता से सम्मिलित था। आरम्भिक सत्र में सदस्य (ओ एण्ड एम) को सदस्य सचिव, योजना आयोग के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक (बीडी एवं एमडी) ने भारतीय डाक द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे व्यापार अवसरों पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया तथा महाप्रबंधक (एम) ने ई-बिल पोस्ट साफ्टवेयर की संभावनाओं का उल्लेख किया। विचारों के इस आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप ई-बिल डाक साफ्टवेयर को एक पूर्ण ई-भुगतान साफ्टवेयर बनाने के लिए इसका संवर्धन किया जा रहा है जिससे वह न केवल ई-बिल

सुविधा उपलब्ध करा सके बल्कि ई-कॉमर्स को अधिक सुविधापूर्ण बनाने हेतु ई-वीपीपी भी उपलब्ध करा सके।

सिटी पोस्ट एवं अंतर-शहरी डाक

1.30 स्थानीय एवं अंतर-शहरी डाक के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर डाक के दो विभिन्न प्रकारों को शुरू करने का निर्णय किया गया है -सिटी पोस्ट एवं अंतर-शहरी डाक। ये साधारण डाक सेवा के अधिक सक्षम प्रकार होंगे तथा यह कुछ मूल्यवर्धन चीजें भी प्रदान करेंगे जैसे कि (i) समय की दृष्टि से संवेदनशील वितरण का विशेष रूप से निपटान (ii) वितरण सूचना की सुविधा (iii) एमआईएस सुविधा। इस उत्पाद का लक्ष्य व्यवसाय समुदाय होगा तथा एक समय पर प्राप्त किए जाने वाले मर्दों की न्यूनतम संख्या 50 होगी। सिटी डाक सेवा को प्रायोगिक योजना के बतौर विजयवाड़ा में शुरू किया गया तथा अंतर-शहरी डाक सेवा को प्रायोगिक योजना के बतौर हैदराबाद एवं चेन्नई तथा हैदराबाद एवं विजयवाड़ा जिलों के बीच शुरू किया गया।

स्पीड पोस्ट गोल्ड

1.31 एक अत्यधिक समय संवेदनशील उच्च मूल्य स्पीड पोस्ट उत्पाद की मांग को पूरा करने हेतु एक प्रीमियम उत्पाद सेवा दिल्ली एवं मुंबई के व्यवसाय जिलों के मध्य शुरू की जानी है। यह कुछ सीमित जिलों के बीच एक समय-संवेदनशील, उच्च प्रीमियम मेल होगी जो दूसरे दिवस के दोपहर के भोजन से पूर्व वितरण की जाने वाली मद को गारंटी से वितरित करेगी तथा इसमें पीओडी/आईओडी मांग पर प्राप्त होगी। इसे अन्य महानगरों के व्यवसाय जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

1.32 एक्सप्रेस डाक सेवा को 25 अक्टूबर, 2004 से सेवा को इसकी व्यवहार्यता बनाए रखते हुए इसे समेकित करने तथा ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसे संशोधित किया गया था। चालू वर्ष 2005-06 में दिसम्बर, 2005 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि में अर्जित राजस्व की तुलना में 30% के राजस्व की वृद्धि हुई है।

पार्सल डिवीजन का सृजन

1.33 सभी प्रकार के पार्सल उत्पादों का जिसमें ईपीपी सम्मिलित हैं, एक संकेन्द्रित प्रबंधन करने हेतु व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय में एक पार्सल डिवीजन सृजित किया गया है। इसी

Corporate e-Post

1.26 The corporate version of e-Post service was launched on 18th October, 2005 by Hon'ble Minister for Communications and IT during the closing celebrations of the Sesquicentennial Year of India Post. The corporate version of e-Post would enable:-

- Simultaneous sending of a message to 9,999 addresses.
- Scanning of the message at the premises of the senders. This will enable the corporate customers to prepare their message on their official stationery, scan it and then send it from their own computers.

Pick up Service

1.27 Pick up service by Postmen was launched by Hon'ble Minister for Communications and IT at the Heads of Circles Conference held at Chennai on 17th and 18th July, 2005. Postmen will pick up not only Speed Post articles, but also ordinary letters while moving in their beats to deliver letters.

Speed Post Passport Service

1.28 Speed Post Passport Service was extended to the Field Post Offices (FPOs) of the Army Postal Service.

E-Commerce

1.29 Confederation of Indian Industries in collaboration with India Post organized an e-Business Summit 2005 on 22nd July, 2005 at Hotel Taj Palace, New Delhi. The Summit was attended by all the major e-commerce players in the country. The Department was intimately involved in the organization of the Summit. Member (O&M) was invited in the opening session to give his views along with Member Secretary, Planning Commission. CGM (BD & MD) gave a presentation on business opportunities offered by India Post and GM (M) spoke about the potentialities of the e-Bill Post Software. As a result of the interaction, e-Bill Post Software is being enhanced to become a complete e-

Payment Software, to provide not only e-Bill facility but also e-V.P to facilitate e-Commerce.

City Post and Inter-City Post

1.30 It has been decided to introduce two new competitively priced variants of mail for local and inter-city mails. The City Post and Inter City Post would be more efficient variants of the ordinary mail service and would offer some value additions, such as (i) special handling to ensure time sensitive delivery; (ii) intimation of delivery facility; and (iii) MIS facility. The product would be aimed at business community and the minimum number of articles accepted at a time would be 50. The City Post Service was introduced as a pilot in Vijaywada and the Inter-City Post Service was introduced as a pilot between Hyderabad & Chennai; and between Hyderabad & Vijaywada districts.

Speed Post Gold

1.31 To meet the demand for a highly time sensitive high value Speed Post product, a premium post service called 'Speed Post Gold' is to start between business districts of Delhi and Mumbai. This would be a time sensitive, high premium mail between limited business districts of limited metros for guaranteed delivery before lunch next day with POD/IOD on demand. It will be extended to business districts between other metros also.

Express Parcel Post

1.32 The Express Parcel Post (EPP) rate was revised w.e.f. 25th October, 2004 keeping with the need for consolidation of the Service and to suit customer's requirement while retaining its viability. There has been about 30% increase in revenue in the current financial year 2005-06 till December, 2005 as compared to the revenue earned in the same period last year.

Creation of Parcel Division

1.33 A Parcel Division has been created in Business Development and Marketing Directorate for focused management of all kinds of parcel products, including EPP. Similar Parcel Divisions have been established

प्रकार के पार्सल डिवीजन सर्किल स्तर/क्षेत्रीय स्तर/डिवीजनल स्तर पर पार्सल सेवा तथा लॉजिस्टिक पोस्ट के प्रबंधन हेतु अधिकारियों तथा निष्ठावान टीमों के साथ स्थापित किए गए हैं।

मेल कार्यालयों में पार्सल संकेन्द्रण केन्द्रों तथा प्रमुख पार्सल सेटों का विकास

1.34 पार्सल उत्पादों का परियात बढ़ाने तथा सामान्य रूप से पार्सल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के विभाग के मुख्य ध्येय के भाग के रूप में 22 सर्किलों के अंतर्गत सभी मेल कार्यालयों में 41 मौजूदा पार्सल संकेन्द्रण केन्द्रों तथा 22 प्रमुख पार्सल सेटों के विकास तथा मुम्बई एवं दिल्ली में दो अतिरिक्त पार्सल केन्द्रों की स्थापना तथा उत्तर-पूर्व राज्यों में छः प्रधान डाकघरों को पर्याप्त रूप से मजबूत करने, जिससे ट्रेक एवं ट्रेस सुविधा तथा सभी प्रकार के पार्सल पारिषणों से निपटने के आधुनिक यांत्रिक उपकरणों को उपलब्ध कराया जा सके, हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक परियोजना शुरू की गई है। इस योजना स्कीम का कुल परिव्यय 50 मिलियन रुपये है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए आबंटन 22.5 मिलियन रुपये है।

लॉजिस्टिक पोस्ट

1.35 एक नई सेवा, लॉजिस्टिक पोस्ट, अगस्त, 2004 को अधिसूचित की गई थी। इस सेवा के अंतर्गत बिना किसी अधिकतम भार सीमा के मर्दों को पत्तों पर वितरित करने के लिए बुक किया जा रहा है। मूल्य संवर्धित सेवाएं जैसे पिक-अप/दुलाई/उतराई, दरवाजे पर वितरण, प्रेषण से पूर्व मर्दों का भंडारण तथा/अथवा वितरण एवं बीमा कवर इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह सेवा तब से 16 सर्किलों में शुरू हो गई है।

आंतरिक कार्य अध्ययन

1.36 पोस्टमैन संवर्ग की अध्ययन रिपोर्ट पूरी कर ली गई है तथा इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्र के मानदण्डों के विकास हेतु रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है, मेल डिवीजन ने उपरोक्त हेतु एक नए मॉड्यूल का सुझाव दिया है। ग्राहक सेवा केन्द्रों के मानदण्डों के विकास हेतु अध्ययन के लिए एक कार्य-सूची हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश सर्किलों द्वारा तैयार की गई है। नए मॉड्यूल की शुरुआत के कारण वी-सेट के मानदण्डों के विकास का अध्ययन पुनः शुरू किया जाना है।

डीए (पी) में कम्प्यूटरीकृत नकदी प्रमाणपत्र एवं मनीआर्डर के लिए कार्य-सूची मार्च, 2006 तक तैयार कर ली जाएगी तथा अध्ययन दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल सर्किलों द्वारा किया जाएगा। समूह "घ" विदेश डाक के लिए कार्य-सूची मार्च, 2006 तक तैयार कर ली जाएगी तथा अध्ययन दिल्ली एवं तमिलनाडु सर्किलों द्वारा किया जाएगा। डीए,सीएफ एवं पीओ अनुभागों द्वारा कार्य मापन अध्ययन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। डीएए अनुभाग का कार्य मापन अध्ययन प्रगति पर है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

1.37 झारखण्ड सर्किल से संबंधित आरक्षण रोस्टर का नवम्बर, 2005 के माह में निरीक्षण किया गया था। इस सर्किल के सभी रोस्टरों का निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के दौरान नोट की गई कमियों/चूकों को सर्किल द्वारा निपटा लिया गया है। झारखण्ड सर्किल का शिकायत रजिस्टर भी जांचा गया परंतु कोई शिकायत नहीं पाई गई। डाक विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में सूचनाएं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा मध्य प्रदेश सर्किलों के आरक्षण रोस्टर का वर्ष, 2006 तक निरीक्षण करने की संभावना है।

वित्तीय सेवाएं

तत्काल मनीआर्डर (आईएमओ)

1.38 20 जनवरी, 2006 को देश में अवस्थित 24 डाकघरों से तत्काल मनीआर्डर सेवा शुरू की गई जो कि एक ऑनलाइन घरेलू धन प्रेषण सेवा है जिसका उद्देश्य बाजार आधारित ग्राहकों को सेवा प्रदान करना है जो समयबद्ध सुनिश्चित धन प्रेषण चाहते हैं।

बचत बैंक खाताधारक के लिए दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर

1.39 15 रु. प्रति वर्ष के नाममात्र के प्रीमियम के भुगतान पर 1,00,000 रु. का एक दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर डाकघर बचत बैंक, मासिक आय योजना तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाताधारकों के लिए शुरू किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए मूल्य संवर्धन

1.40 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ग्राहक अब डाकघर की मनीआर्डर सेवा के माध्यम से घर पर त्रैमासिक ब्याज भुगतान

at Circle level / Regional level / Divisional level with dedicated teams and officers for the management of Parcel Service and Logistics Posts.

Development of Parcel Concentration Centres and Major Parcel Sets in Mail Offices

1.34 As a part of Department's core aim to increase the traffic of parcel products and improve the quality of parcel services in general and to bring it to international standard, a project has been taken up under the 10th Five Year Plan, for development of 41 existing Parcel Concentration Centres and 22 Major Parcel Sets in Mail Offices covering all the 22 Circles and for establishment of two additional Parcel Centres in Mumbai and Delhi and for adequately strengthening six HOs in North-Eastern States for providing track and trace facilities and modern mechanical aids to handle all kinds of parcel consignments. The total outlay for the Plan Scheme is Rs. 50 Million, out of which the allocation for the current financial year 2005-06 is Rs. 22.5 Million.

Logistics Post

1.35 A new service "Logistics Post" was notified in August, 2004. Under this service, articles are being booked for delivery to addressees without any maximum weight limit. Value added services such as pick-up, loading / unloading, door delivery, storage of goods before dispatch and / or delivery and facility for insurance cover, etc., are also available. The service has since started in 16 Circles.

Internal Work Study

1.36 The study report of the Postman cadre has been completed and submitted. The report on the evolution of norms for Computerised Registration Centre (CRC) has been taken up, the mail division has suggested for introduction of new module for the same. The job list for evolution of norms for Customer Care Centre has been prepared for conducting the study by Haryana and Andhra Pradesh Circles. The study for evolution of norms for VSAT has to be reinitiated due to introduction of new module. The job list for computerised cash certificate and Money Order in DA (P) will be finalized

by March, 2006 and study will be done by Delhi and West Bengal Circles. The job list for Group D foreign post will be finalized by March 2006, the study will be undertaken by Delhi and Tamilnadu Circles. The work measurement study reports of DA, CF and PO Sections have been issued. The work measurement study of DAA Section is in progress.

Scheduled Castes & Scheduled Tribes

1.37 The reservation rosters in respect of Jharkhand Circle were inspected during the month of November, 2005. All the rosters of this circle were inspected and the shortcomings/lapses noted during the inspection have been settled by the circle. The grievance register of Jharkhand Circle was also checked but there was no complaint. The information in respect of SC/ST/OBC employees of the Department of Posts has been supplied to the Department of Personnel and Training and National Commission for SCs/STs. Reservation Rosters of Bihar, Chhatisgarh, Jammu & Kashmir and Madhya Pradesh Circles are likely to be inspected in the year 2006.

FINANCIAL SERVICES

Instant Money Order (IMO)

1.38 Instant Money Order, an online domestic money transmission service intended for a market clientele which desires assured time related money delivery was introduced on 20th January, 2006 from 24 Post Office locations in the country.

Accidental Death Insurance Cover for Saving Account Holder

1.39 An Accidental Death Insurance Cover of Rs. 1,00,000/- on payment of a nominal premium of Rs. 15/- per annum has been introduced for Post Office Savings Bank, Monthly Income Scheme and Senior Citizen Savings Scheme account holders.

Value Addition to Senior Citizen Savings Scheme

1.40 The Senior Citizen Savings Scheme customers can now receive the quarterly interest payment at home through the Money Order Service of the Post Office.

प्राप्त कर सकते हैं। कई वरिष्ठ नागरिक जो त्रैमासिक ब्याज प्राप्त करने हेतु डाकघर आने के लिए बहुत वृद्ध हैं अथवा चल नहीं पाते हैं वह डाकघर की इस घर पर वितरण-भुगतान की ग्राहक अनुकूल सेवा से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं:

डाक जीवन बीमा

1.41 वर्ष 2005-06 के लिए व्यवसाय लक्ष्य तथा अप्रैल से दिसम्बर, 2005 तक प्राप्त किया गया व्यवसाय नीचे दिया गया है:

तालिका-14 डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा: 2005-06			
श्रेणी	लक्ष्य (मिलियन रु. में)	उपलब्धि (दिसम्बर 2005 तक)	
		पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	60,000	197,841	23487.2
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	1,30,000	514,979	30263.9

1.42 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन बीमा तथा बचत का संग्रहण ग्रामीण डाक जीवन बीमा की विशेषता रही है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यापार की विशाल संभावनाओं का लाभ उठाने हेतु बीमित राशि की मात्रा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रु. कर दी गई है।

स्टाफ संबंध

1.43 इस अवधि के दौरान विभाग ने अपने कर्मचारियों के संघों एवं यूनियनों के साथ सार्थक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रयत्न किया है। 01 अप्रैल, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक विभागीय परिषद (जेसीएम) की स्थायी समिति की बैठक 11 जुलाई, 2005 को आयोजित की गई। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई जिसमें 18 नवम्बर, 2003 के विभागीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा की गई। महासचिव, बीपीईएफ के अनुरोध पर मुख्य इंजीनियर (सिविल) ने 25 अगस्त, 2005 तक संघ द्वारा सूचित लम्बित मामलों पर चर्चा हेतु बीपीईएफ के साथ एक बैठक आयोजित की। इसके अतिरिक्त उप महानिदेशक (पीएएफ) ने 15 अप्रैल,

2005 को अखिल भारतीय डाक लेखा कर्मचारी संघ के साथ संघ द्वारा उठाए गए विषयों पर बहस हेतु एक आवधिक बैठक की।

1.44 सचिव (डाक) की राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ (एनएफपीई) और राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ (एफएनपीओ) तथा उनकी सम्बद्ध यूनियनों और गैर-सम्बद्ध यूनियनों के साथ 4 और 5 जनवरी, 2006 को आवधिक बैठकें हुईं। इसके अलावा सचिव (डाक) ने भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ व उसकी सम्बद्ध यूनियनों के साथ दिनांक 5 जनवरी, 2006 को एक औपचारिक बैठक की। ये बैठकें स्टाफ की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई थीं। इन तीनों फेडरेशनों व गैर-फेडरेशन यूनियनों के साथ अगली आवधिक बैठक मई 2006 में होने की संभावना है। डाक विभाग में विभागीय काउंसिल (जेसीएम) की अगली बैठक मार्च, 2006 में होने की संभावना है। कर्मचारी पक्ष व सरकारी पक्ष से बैठक के लिए कार्य-सूची की मदें आमंत्रित की गई हैं व इनकी प्रक्रिया जारी है।

स्टाफ कल्याण

1.45 वर्ष 2005-06 के दौरान 55 मिलियन रु. के कुल बजटीय अनुदान में से सर्किलों को आबंटन निम्नानुसार किया गया:-

- (i) विभाग में कल्याण कार्यक्रमों पर कुल व्यय में से 27 मिलियन रु. आबंटित किए गए।
- (ii) 9.9 मिलियन रु. की राशि सर्किल खेल-कूद निधि में आबंटित की गई।
- (iii) महाराष्ट्र सर्किल में भारी बाढ़ के कारण, मामले से संबंधित मौजूदा अनुदेशों के अनुसरण में वित्तीय सहायता व अन्य राहत सामग्री के लिए 2.5 मिलियन रु. की राशि अब तक आबंटित हो चुकी है। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर में भूकम्प से प्रभावित डाक विभाग के कर्मचारियों को भी लगभग 2.34 लाख रु. की लागत वाले 30 टैन्ट तथा 1.07 लाख रु. की लागत के 200 कम्बल उपलब्ध कराए गए।

Many senior citizens who are too old or immobile to make visits to Post Office or banks to draw the quarterly interest for their expenses are greatly benefited by this customer friendly service of home delivery payment by the Post Office.

Postal Life Insurance

1.41 The Business targets for the year 2005-06 and business secured from April to December, 2005 are detailed below: -

Table 14 PLI/RPLI BUSINESS : 2005-06			
Category	Target (Rs. in Million)	Achievement (Up to December, 2005)	
		No. of Policies	Sum Assured (Rs. in Million)
PLI	60,000	197,841	23487.2
RPLI	130,000	514,979	30263.9

1.42 The mobilization of savings as well as Life Insurance of the people in Rural Area has been the hallmark of Rural Postal Life Insurance. To tap the vast mine of RPLI business, the sum assured has been enhanced from Rs. one lakh to Rs. two lakh.

Staff Relations

1.43 During the period, the Department endeavoured to maintain harmonious and meaningful relations with the Federations and Unions/Associations of its employees. From 1st April, 2005 to 31st December, 2005, Standing Committee meeting of Departmental Council (JCM) was held on 11th July, 2005. The meeting took place in a congenial atmosphere wherein Action Taken Report on the decisions taken in the meeting of the Departmental Council held on 18th November, 2003 was discussed. On the request of Secretary General, BPEF, Chief Engineer (Civil) held a meeting with the BPEF on 25th August, 2005 to discuss the pending issues reported by the Federation. Besides, DDG (PAF) had a periodical meeting with All India Postal Accounts Employees

Association on 15th April, 2005 to discuss the issues raised by the Association.

1.44 Periodical meetings of Secretary (Posts) with the National Federation of Postal Employees (NFPE) and Federation of National Postal Organisations (FNPO) along with their affiliated unions as well as with non-federated unions were held on 4th and 5th January, 2006. Further, an informal meeting of Secretary (Posts) with Bharatiya Postal Employees Federations and its affiliated unions was held on 5th January, 2006. These meetings were granted to discuss various staff problems. Another periodical meeting with all the three federations as well as non-federated unions is likely to be held in May, 2006. Next meeting of the Departmental Council (JCM) in the Department of Posts is likely to be held by March, 2006. An agenda items for the meeting have been called for from Staff Side as well as from Official Side and it is under process.

Staff Welfare

1.45 During the year 2005-06, out of the Budget Grant of Rs. 55 Million, allocations were made to the Circles as under :-

- (i) Rs.27 Million was granted towards the total expenditure on welfare activities of the Department.
- (ii) An amount of Rs. 9.9 Million was disbursed to Circle Sports Funds.
- (iii) Due to heavy floods in Maharashtra Circle, Rs.2.5 Million has been allocated so far, for providing financial assistance and other relief in accordance with existing instructions in the matter. Also 30 tents costing about Rs. 2.34 lakh and 200 blankets costing about Rs. 1.07 lakh were provided for earthquake affected staff of Department of Posts in Jammu & Kashmir.

लम्बी बीमारी के लिए केन्द्रीय कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करना

1.46 चिकित्सा कारणों से अनुकंपा आधार पर विभागीय कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान निर्धारित करने के लिए गठित समिति की बैठक सदस्य (विकास) की अध्यक्षता में 8 जून, 2005 को आयोजित की गई जिसमें कुल 60,000/-रुपये की राशि के चार प्रस्ताव पारित किए गए।

फील्ड सेवा (डाक) हितकारी निधि से वित्तीय सहायता

1.47 सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी व जिनकी मृत्यु हो गई है ऐसे 10 शोक संतप्त परिवारों व बच्चों को 35,000/-रु. का वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया तथा मृतक कर्मचारियों के 24 बच्चों को 12,000/-रु. की एककलिक राशि छात्रवृत्ति के तौर पर दी गई।

मेघदूत पुरस्कार

1.48 मेघदूत पुरस्कार छह अलग-अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। पुरस्कार में एक स्क्रॉल, 5000/-रु. तक का सोने का सिक्का तथा 11,000/-रु. का नकद पुरस्कार होता है। वर्ष 2005 के पुरस्कार माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 18 अक्टूबर, 2005 को विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में छह कर्मचारियों को प्रदान किए गए।

खेल

1.49 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय डाक खेल-कूद प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगिताओं फुटबाल, कैरम, बास्केटबॉल, वालीबॉल, टेबल-टेनिस, कबड्डी, शतरंज व कुश्ती का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। भारतीय डाक की टीम ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

1.50 31 मार्च, 2006 तक, केन्द्रीय कल्याण निधि में शेष राशि तथा सर्किलों की लम्बित मांगों के मद्देनजर, विभिन्न सर्किलों के बजटीय आबंटन की पुनरीक्षा की जाएगी। वित्तीय सहायता के अनुदान के आगे के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक शीघ्र आयोजित होनी है। डाक खेल बोर्ड की बैठक मार्च, 2006 में आयोजित होगी। अखिल भारतीय डाक प्रतियोगिता हॉकी, क्रिकेट, भारोत्तोलन/पावर लिफ्टिंग/

शारीरिक सौष्ठव व बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय डाक की टीमों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है:

- दिनांक 20.01.2006 से 25.01.2006 तक पुणे में XXXVवीं वरिष्ठ राष्ट्रीय कैरम चैम्पियनशिप; तथा
- जयपुर में दिनांक 21.02.2006 से 26.02.2006 तक आयोजित होने वाली 67वीं वरिष्ठ टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप।

चिकित्सा सुविधाएं

1.51 कल्याण कार्य के तौर पर डाक विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में 48 शहरों/कस्बों में 52 डाक औषधालय चला रहा है। पात्र लाभार्थियों को ये औषधालय बाह्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। जहां-कहीं भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारी व पेंशनर डाक औषधालय सुविधाओं के हकदार हैं। डाक सेवा बोर्ड ने चार औषधालयों, भोपाल तथा वडोदरा प्रत्येक में एक औषधालय को तथा जबलपुर में तीन औषधालयों को एक साथ विलय करने की अनुमति प्रदान कर दी है। डाक व तार औषधालय का नाम बदलकर डाक औषधालय कर दिया गया है।

निरीक्षण

1.52 प्रधान डाकघरों, उप डाकघरों, शाखा डाकघरों की निरीक्षण प्रश्नावली में संशोधन किए गए हैं तथा ये द्विभाषी फार्मेट में जारी किए गए हैं। डाकघरों के लिए निरीक्षण मार्गनिर्देशों में संशोधन करके उन्हें जारी किया गया है।

जन शिकायतें

1.53 सितम्बर, 2005 तक कुल 5,22,567 जन शिकायतों पर कार्रवाई की गई तथा कुल 4,69,164 मामलों को निपटाया गया। सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा हमारे कार्यकलापों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एलएसजी स्तर तक के सभी विभागीय उप डाकघरों में नागरिक घोषणा पत्र कार्यान्वित किया गया है। विभाग ने अपनी सेवाओं में संतुष्टि के स्तर व प्रत्याशाओं का आकलन करने के उद्देश्य से रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन तथा वाणिज्य मंडलों को फोन करके, निजी दौरे करके तथा प्रश्नावलियों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किए हैं।

Financial assistance from Central Welfare Fund for prolonged illness

1.46 Committee constituted for deciding grant of financial assistance to Departmental officials on compassionate grounds for medical reasons headed by Member (D) in a meeting held on 8th June, 2005 cleared four proposals for a total sum of Rs. 60,000/.

Financial assistance from Field Service (Postal) Benevolent Fund

1.47 Rs. 35,000/- was granted as financial assistance to the 10 bereaved families and children of the deceased employees on deputation to Army Postal Service and Rs. 12,000/- as one time scholarship for 24 children of deceased employees.

Meghdoot Awards

1.48 The Meghdoot Awards are being given in six individual categories. The award comprises of a scroll, a gold sovereign of about Rs. 5000/- and cash award of Rs. 11,000/-. The awards for the year 2005 were distributed to six personnel by the Hon'ble Minister of Communications and Information Technology on 18th October, 2005 in a function organized by the Department at New Delhi.

Sports

1.49 During the period from 1st April to 31st December, 2005, All India Postal Sports Tournaments in 8 events viz. Football, Carrom, Basketball, Volleyball, Table-Tennis, Kabaddi, Chess and Wrestling were organised. In addition, a cultural meet was also organized. India Post Teams participated in various National Meets.

1.50 By 31st March, 2006, review of budgetary allocation to different Circles would be made keeping in view the balance amount in the Central Welfare Fund and the pending demands of Circles. A meeting of the Empowered Committee is to be convened shortly to decide further cases for grant of financial assistance. A

meeting of the Postal Sports Board is to be held in the month of March, 2006. All India Postal events viz. Hockey, Cricket, WL/PL/BP and Badminton are to be held. India Post teams would be participating in :-

- i). XXXV Senior National Carrom Championship to be held at Pune w.e.f. 20.01.2006 to 25.01.2006; and
- ii). 67th Senior National Table Tennis Championship to be held at Jaipur w.e.f. 21.02.2006 to 26.02.2006.

Medical Facilities

1.51 As a welfare measure, Department of Posts is running 52 Postal Dispensaries in 48 cities/towns in various parts of the country. These dispensaries extend out door treatment facilities to the eligible beneficiaries. Employees as well as pensioners of the Department of Posts and Department of Telecom are entitled to Postal Dispensary facilities, wherever such facilities are available. Postal Service Board has approved merger of four Dispensaries i.e. two dispensaries each into one at Bhopal and Vadodara and three dispensaries into one at Jabalpur. The nomenclature of 'P&T Dispensary' has also been changed as 'Postal Dispensary'.

Inspection

1.52 The inspection questionnaires for Head Post Offices, Sub Post Offices, Branch Post Offices have been revised and issued in bilingual format. Inspection Guidelines for Post Office have been revised and issued.

Public Grievances

1.53 Up to September, 2005, total 5,22,567 cases of public grievances were handled and a total of 4,69,164 cases were settled. The implementation of Citizen's Charter has been carried out in all Departmental Sub-Post Offices up to LSG level with the view to improve quality of service and have increased participation of citizens in our functioning. The Department took efforts to reach its customers like Residents Welfare Associations and Chambers of Commerce, etc. through phone calls, personal visits and questionnaire with the aim to assess their satisfaction level with its services and further expectations.

मानव संसाधन विकास

पोस्टल स्टाफ कालेज

1.54 पोस्टल स्टाफ कालेज ने 8 प्रवेशकालीन प्रशिक्षण तथा 18 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 444 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 101 अधिकारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्याशित है कि 25 और अधिकारियों को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण तथा 01.01.2006 से 31.03.2006 तक विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 152 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

विदेश में प्रशिक्षण

1.55 1.4.2005 से 31.12.2005 तक एशियाई प्रशांत कालेज, बैंकाक में विभिन्न विषयों पर 12 भारतीय डाक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा मार्च 2006 तक और 5 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना है।

डाक प्रशिक्षण केन्द्र

1.56 संदर्भित अवधि के दौरान छह डाक प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 8477 और 9,072 कर्मचारियों को सेवाकालीन/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण व कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,748 तथा 3,462 कर्मचारियों को क्रमशः सेवाकालीन/प्रवेशकालीन तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्य-स्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाएं (डब्ल्यूसीटीसी)

1.57 दिसम्बर, 2005 तक 60 डब्ल्यूसीटीसी द्वारा कुल 20,000 कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान और 15,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्थापना

1.58 डा. उ. श्रीनिवासराघवन को सचिव (डाक) के पद पर 01.11.2005 को पदोन्नत किया गया। श्री आई.एम.जी. खान को सदस्य, डाक सेवा बोर्ड के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। सात एसटीएस (आईपीओ ग्रुप 'क') अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में (तदर्थ आधार पर) तथा 12 एसटीएस (आईपीओ ग्रुप 'क') अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (नियमित आधार

पर) में पदोन्नत किया गया है। 102 आईपीओ/आईआरएम लाइन अधिकारियों को पीएस ग्रुप 'ख' में पदोन्नत किया गया है। सहायक निदेशक (भर्ती) के पद पर डीपीसी 10 जनवरी, 2006 को आयोजित हो चुकी है। 111 पीएसएस ग्रुप 'ख' अधिकारियों को आईपीओ ग्रुप 'क' के जेटीएस पर पदोन्नत कर दिया गया है। सीएसई, 2003 (मुख्य) परीक्षा के माध्यम से चयनित एक उम्मीदवार को आईपीओ ग्रुप 'क' में जेटीएस के पद पर नियुक्त किया गया है। 11 जेटीएस अधिकारियों को आईपीओ ग्रुप 'क' के एसटीएस पर मार्च 2006 तक पदोन्नत करने की संभावना है।

राजभाषा

1.59 दिसम्बर 2005 तक संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने छह कार्यालयों का निरीक्षण किया।

1.60 राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 में दिए दिशा निर्देशों के अनुसरण में विभाग के अधिकारियों द्वारा दस कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा पर संसदीय समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने विभाग के सात विभिन्न कार्यालयों के अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया।

1.61 14 सितम्बर, 2005 को विभाग में हिन्दी दिवस मनाया गया तथा 01 से 15 सितम्बर, 2005 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। पखवाड़े के दौरान दो हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

सामग्री प्रबंधन

1.62 विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की मांग, कि डाक विभाग के फील्ड यूनिटों के पात्र ग्रुप 'ग' व ग्रुप 'घ' कर्मचारी जो सामान्य स्टेशनों में पद स्थापित हैं तथा जहां वर्दी प्रदान की जाती है, को चार वर्षों के ब्लाक में पालिएस्टर काटन वर्दी के चार सैट उपलब्ध कराए जाएं जो कि प्रत्येक वर्ष के लिए एक सैट वर्दी बनती है, को मान लिया गया है। सितम्बर 2003 को डाक सेवा बोर्ड की 13वीं बैठक में लिए निर्णयों के अनुसरण में, डाक सर्किलों को ऊनी जर्सी, ऊनी ग्रेट कोट के लिए कपड़ा, पत्र पेटियों, फार्म मुद्रित करने के लिए पेपर तथा ऊनी सर्ज क्लाय (किस्म-IV) की अधिप्राप्ति को विकेन्द्रीकृत करने के आदेश भी वर्ष के दौरान जारी किए जा चुके हैं।

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Postal Staff College

1.54 The Postal Staff College conducted 8 Induction and 18 in-service training programmes, in which 444 officers participated. Besides, 101 officers were imparted training in computers during the period. It is anticipated that an additional 25 officers would be imparted induction training and 152 officers would be trained on various computer training programmes from 01.01.2006 to 31.03.2006.

Training Abroad

1.55 12 Indian Postal Service Officers were trained on various subjects at Asia Pacific College Bangkok from 1.4.2005 to 31.12.2005 and 5 more officers are likely to be trained by March, 2006.

Postal Training Centres

1.56 A total number of 8,477 and 9,072 officials were imparted in-service/induction training and computer training respectively by the six Postal Training Centers during the reference period. It is anticipated that an additional number of 1,748 and 3,462 officials would be imparted in-service/induction training and computer training respectively during the current financial year.

Work Place Computer Training Facilities (WCTCs)

1.57 By December, 2005, a total number of about 20,000 officials were imparted training on computers by 60 WCTCs. It is anticipated that an additional number of about 15,000 officials would be imparted training during the current financial year.

Establishment

1.58 Dr. U. Srinivasa Raghavan was promoted as Secretary (Posts) on 01.11.2005. Shri I.M.G. Khan was promoted to the grade of Member, Postal Services Board. Seven STS(IPoS Group 'A') Officers have been promoted to JAG(on ad-hoc basis) and twelve STS(IPoS Group 'A') Officers have been promoted to JAG(on regular basis). 102 IPO/IRM line officers have been

promoted to PS Group 'B'. DPC for the post of Assistant Director (Rectt.) has been conducted on 10th January, 2006. 111 PSS Group 'B' Officers have been promoted to JTS of IPoS Group 'A'. One candidate selected through CSE, 2003 (Main) has been appointed to JTS of IPoS Group 'A'. 11 JTS Officers are likely to be promoted to STS of IPoS Group 'A' by March, 2006.

Official Language

1.59 Up to December, 2005, the second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language carried out inspections in six offices.

1.60 In pursuance of the directives laid down in the Annual Programme 2005-06 issued by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), ten Offices have been inspected by the Officers of the Department. The Drafting and Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language held discussions with the heads of the seven different offices of the Department.

1.61 Hindi Diwas was observed in the Department on 14th September, 2005 and Hindi Fortnight was observed from 01st to 15th September, 2005. Prizes were distributed to the winners of various competitions held during the Hindi Fortnight. Two Hindi Workshops were also organized during the fortnight.

Material Management

1.62 The demand of the Staff Side of the Departmental Council (JCM) that eligible Group 'C' and Group 'D' employees of the field units of the Department of Posts posted in plain stations where warm uniform is supplied, may be provided with four sets of Polyester Cotton uniforms in a block of four years, at an average of one set per year has been accepted. In pursuance of the decision taken by the Postal Services Board in its 13th meeting held in September, 2003, orders for decentralization of Procurement of Woolen Jerseys, Woolen Great Coat Cloth, Letter Boxes, Paper for Printing of Forms and Woolen Serge Cloth (Variety IV) to the Postal Circles were also issued during the year.

अनुबंध

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

डाक विभाग के कार्यकरण पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है :-

1. **सेवा कर की वसूली न होना-** वित्त अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अनुसरण में तार प्राप्तियों पर सेवा-कर उगाहने में विफल रहने के परिणामस्वरूप सेवा-कर और उस पर ब्याज की वसूली नहीं हुई। 20 डाक सर्किलों की यह राशि 66.94 लाख रुपये है।

(2005 की रिपोर्ट सं. 2)

2. **सावधि जमा खातों को अनियमित रूप से खोलना-** दिल्ली डाक सर्किल के तीन प्रधान डाकघरों ने नियमों का उल्लंघन

करते हुए संस्थानों/संस्थाओं के पक्ष में सावधि जमा खाते खोले और 41.24 लाख रुपये के ब्याज के अनियमित भुगतान की अनुमति दी।

(2005 की रिपोर्ट सं. 2)

3. **आवर्ती जमा खातों पर अनियमित भुगतान -** वर्ष 2002-03 के दौरान राजस्थान सर्किल में दो प्रधान डाकघरों के हैड पोस्टमास्टर्स और छत्तीसगढ़ सर्किल में एक प्रधान डाकघर ने बचत बैंक सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हुए 32.43 लाख रुपये के अनियमित भुगतान की अनुमति दी।

(2005 की रिपोर्ट सं. 2)



ANNEXURE

AUDIT OBSERVATIONS OF C&AG

Summary of audit observations on the working of Department of Posts provided by C&AG is as follows :-

1. Non realization of Service-Tax : Failure to levy Service-Tax on telegraph receipts in terms of the provisions in the Finance Act, 2001 resulted in non-recovery of Service-Tax and interest thereon amounting to Rs. 66.94 Lakh in 20 Postal Circles.

(Report No. 2 of 2005)

2. Irregular Opening of Time Deposit Accounts : Three Head Post Offices in Delhi Postal Circle opened time deposit accounts in favour of

institutions/associations in contravention of rules and allowed irregular payment of interest of Rs. 41.24 Lakh.

(Report No. 2 of 2005)

3. Irregular Payments against Recurring Deposit Accounts : Head Postmasters of two Head Post Offices in Rajasthan Circle and one Head Post Office in Chhattisgarh Circle allowed irregular payment of Rs. 32.43 Lakh during 2002-03 in contravention of Post Office Savings Bank General Rules.

(Report No. 2 of 2005)

तालिका 15

31.3.2005 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

समूह	अनुसूचित जाति	कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत
समूह 'क'	98	13.90	51	7.23
समूह 'ख' (राजपत्रित)	207	10.27	77	3.82
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	662	15.43	354	8.25
समूह 'ग'	34,648	17.68	13,230	6.75
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	8,447	19.73	3,002	7.01
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	703	83.10	60	7.09

तालिका 16

31.3.2005 को भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और महिला कर्मचारियों की संख्या

समूह	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग भूतपूर्व सैनिक	महिला
समूह 'क'		0	91
समूह 'ख' (राजपत्रित)	0	0	83
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	2	0	199
समूह 'ग'	1,687	45	26,827
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	271	6	4,288
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	2	1	312



TABLE 15 NUMBER OF EMPLOYEES : SCHEDULED CASTES/TRIBES AS ON 31.3.2005				
Group	Scheduled Castes	Percentage to Total no. of Employees	Scheduled Tribes	Percentage to total no. of employees
Group 'A'	98	13.90	51	7.23
Group 'B' (Gazetted)	207	10.27	77	3.82
Group 'B' (Non Gazetted)	662	15.43	354	8.25
Group 'C'	34,648	17.68	13,230	6.75
Group 'D' (Excl. Sweeper)	8,447	19.73	3,002	7.01
Group 'D' (Sweeper)	703	83.10	60	7.09

TABLE 16 NUMBER OF EMPLOYEES : EX-SERVICEMEN, DISABLED EX-SERVICEMEN AND WOMEN AS ON 31.3.2005			
Group	Ex-Servicemen	Disabled Ex-Servicemen	Women
Group 'A'	1	0	91
Group 'B' (Gazetted)	0	0	83
Group 'B' (Non Gazetted)	2	0	199
Group 'C'	1,687	45	26,827
Group 'D' (Excl. Sweeper)	271	6	4,288
Group 'D' (Sweeper)	2	1	312

तालिका- 17
कार्मिक - 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार वास्तविक संख्या
(विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण पर गए कर्मचारियों को मिलाकर)

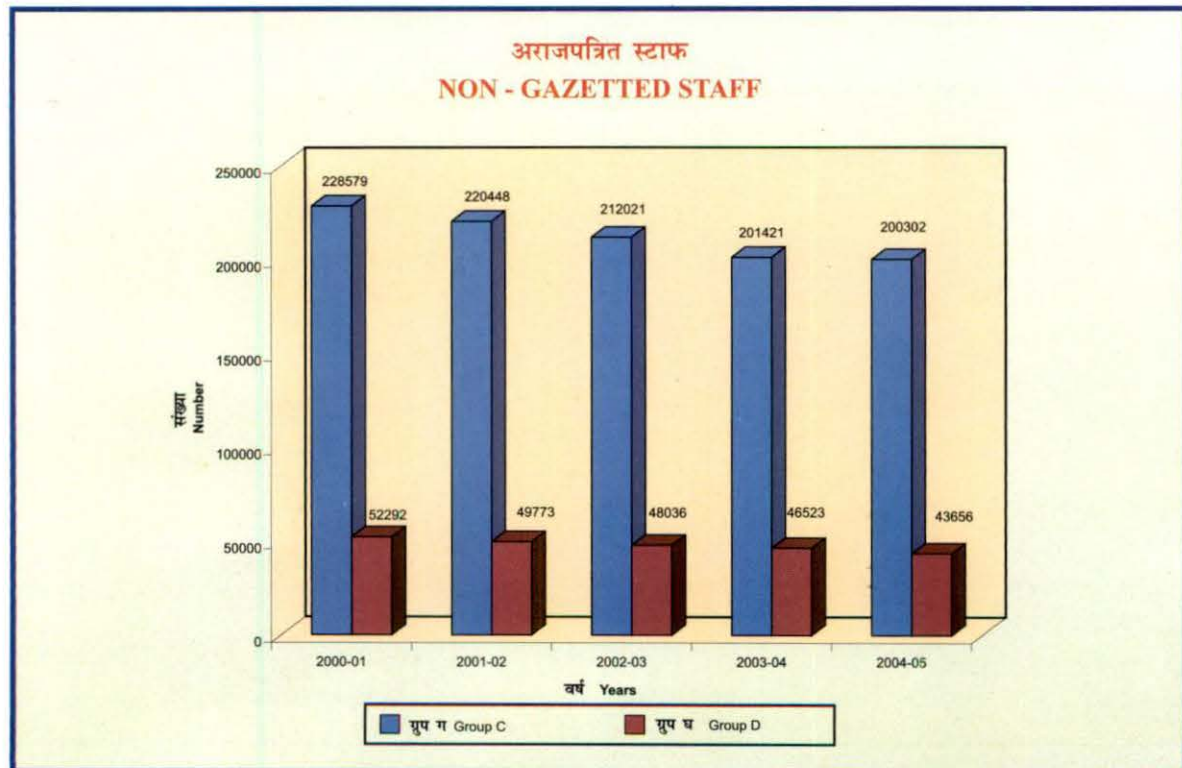
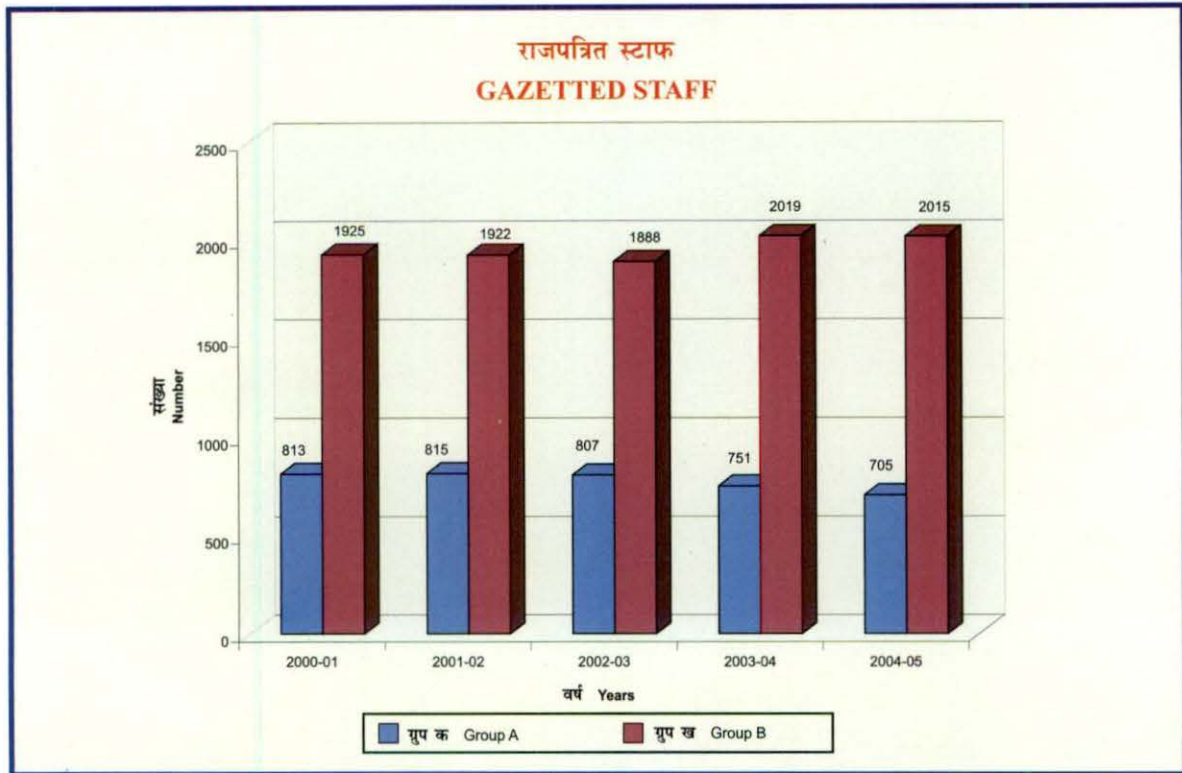
क. विभागीय राजपत्रित	समूह 'क'	समूह 'ख'	कुल
भारतीय डाक सेवा समूह 'क'			
सचिव (डाक),	1	-	1
सदस्य, डाक सेवा बोर्ड	2	-	2
प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	2	-	2
वरिष्ठ उपमहानिदेशक/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	21	-	21
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	75	-	75
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	137	-	137
वरिष्ठ समयमान	74	-	74
कनिष्ठ समयमान	111	-	111
डाक सेवा समूह 'ख'	-	866	866
डाक तार लेखा एवं वित्तीय सेवा			
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	4	-	4
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	22	-	22
वरिष्ठ समयमान	25	-	25
कनिष्ठ समयमान	19	-	19
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	-	245	245
सहायक लेखा अधिकारी	-	617	617
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	20	40	60
सिविल विंग			
मुख्य अभियंता	2	-	2
अन्य	57	173	230
अन्य सामान्य केन्द्रीय सेवा	133	74	207
कुल (राजपत्रित)	705	2015	2720
अराजपत्रित	समूह "ग"	समूह "घ"	कुल
निदेशालय	478	130	608
डाकघर	174290	27404	201694
रेल मेल सेवा	21144	13775	34919
मेल मोटर सेवा	1664	407	2071
अन्य	2726	1940	4666
कुल (अराजपत्रित)	200302	43656	243958
कुल विभागीय (क)			246678
ख. ग्रामीण डाक सेवक			293656
कुल योग (क+ख)			540334

Table 17

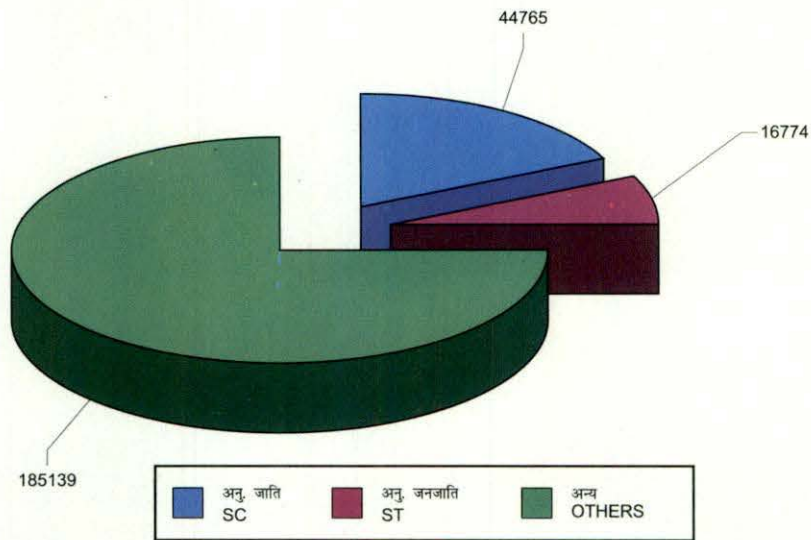
Personnel: Actual strength as on 31.3.2005

(including those on deputation and training outside the Department)

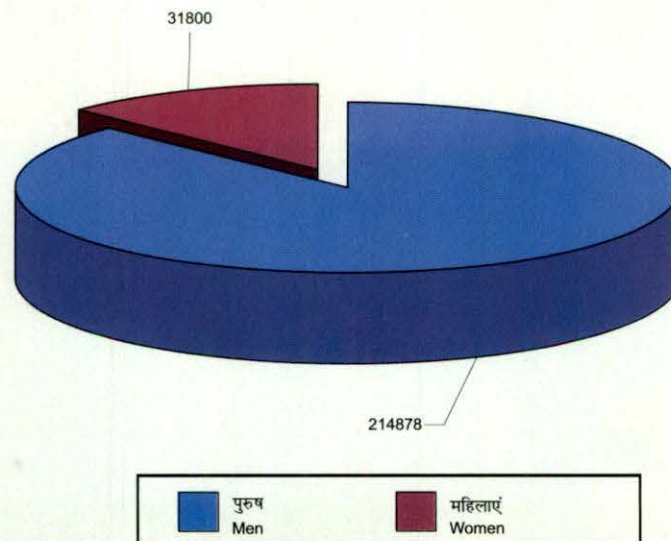
A.DEPARTMENTAL GAZETTED	GROUP"A"	GROUP"B"	TOTAL
INDIAN POSTAL SERVICE GROUP"A"			
Secretary(Posts)	1	-	1
Member, Postal Services Board	2	-	2
Principal Chief Postmaster General	2	-	2
Sr.DDG/Chief PMG	21	-	21
Senior Administrative Grade	75	-	75
Junior Administrative Grade	137	-	137
Senior Time Scale	74	-	74
Junior Time Scale	111	-	111
POSTAL SERVICE GROUP "B"	-	866	866
P& T ACCOUNTS & FINANCE SERVICE			
Senior Administrative Grade	4	-	4
Junior Administrative Grade	22	-	22
Senior Time Scale	25	-	25
Junior Time Scale	19	-	19
Senior Accounts Officer/Accounts Officer	-	245	245
Asstt. Accounts Officer	-	617	617
CENTRAL SECRETARIAT SERVICE	20	40	60
CIVIL WING			
Chief Engineer	2	-	2
Others	57	173	230
OTHER GENERAL CENTRAL SERVICE	133	74	207
TOTAL(GAZETTED)	705	2015	2720
NON GAZETTED	GROUP"C"	GROUP"D"	TOTAL
Directorate	478	130	608
Post Offices	174290	27404	201694
Railway Mail Service	21144	13775	34919
Mail Motor Service	1664	407	2071
Others	2726	1940	4666
TOTAL(NON GAZETTED)	200302	43656	243958
TOTAL DEPARTMENTAL(A)			246678
B. GRAMIN DAK SEWAK			293656
GRAND TOTAL(A+B)			540334



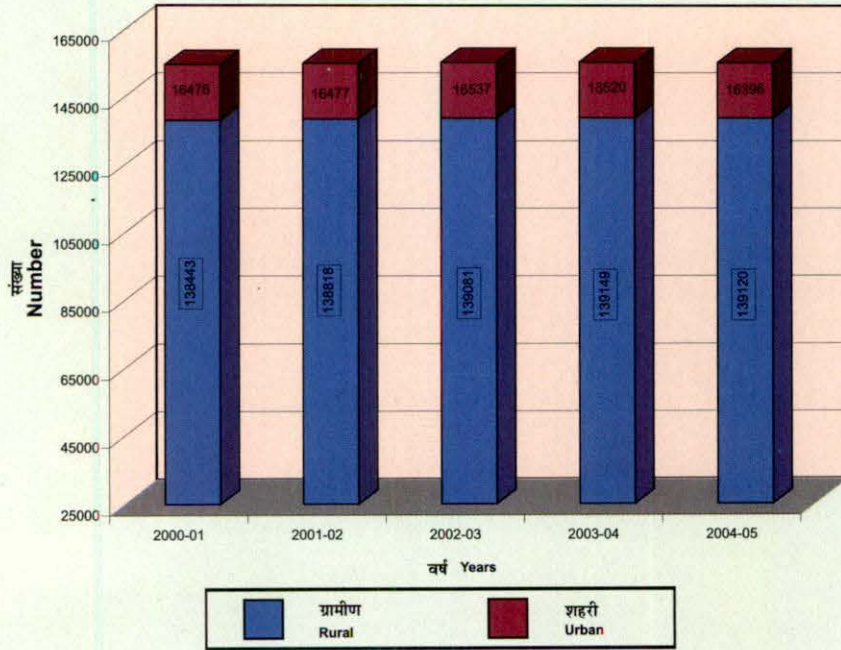
31.03.2005 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी (विभागीय)
SC/ST Employees as on 31.03.2005 (Departmental)



31.03.2005 को महिला कर्मचारी (विभागीय)
Women Employees as on 31.03.2005 (Departmental)



डाकघरों की संख्या
NUMBER OF POST OFFICES



प्रतिदिन निपटाई गई महानगरीय डाक
METRO MAIL HANDLED PER DAY

